हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 मार्च, 1983

खंड 1, अंक 11

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 21 मार्च, 1983

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एव उतर	(11)1

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(11)24
हरिजन लडकियो के कथित अपहरण। कानून तथा व्यवस्था की स्थिती सम्बन्धी मामला उठाया जाना	(11)27
वक्तव्य	
मुख्य मंत्री द्वारा उपयुक्त मामले सम्बन्धी	(11)28
विभिन्न विशयों का उठाया जाना–	
(i) फतेहाबाद मे हरिजनों को तंग करने सम्बन्धी	(11)29
(ii) पुलिस अफसरो को बहादूरी के लिए ईनाम देने सम्बन्धी	(11)30
(iii) दवाइयों पर सेल्ज टैक्स ऐबोलि ा करने सम्बन्धी	(11)30
(iv) डी.ए. की तीन किस्तों सम्बन्धी	(11)30
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव––	
सिविल हस्पताल, महैन्द्रगढ, सम्बन्धी	(11)31
बिल्ज (इन्ट्रोड्यूस्ड–सदन की अनुमति से)	
(i) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एंड	(11)34

वैलीडै ान) बिल, 1983	
(ii) दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एंड डिवैल्पमैंट) अमैंडमैंट बिल, 1983	(11)36
(iii) दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड युनानी प्रैक्टि ानर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल 1983	(11)38
(iv) दि हरियाणा फौरेस्ट डिवैल्पमैंट बिल, 1983	(11)39
(v) दि महार्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैडमैंट) बिल, 1983	(11)42
वर्श 1983–84 के बजट पर अनुदानों की मांगो पर चर्चा	(11)44
बैठक का समय बढाना	(11)79
वर्श 1983–84 के बजट पर अनुदानों की मांगो पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(11)79
वर्श 1983–84 के बजट पर अनुदानों की मांगो पर मतदान	(11)80

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 21 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ. में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारासिंह) ने अधयक्षता की।

तांराकित प्र न एवं उतर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवाल होगें।

Remodelling/Renovation of Civil Hospital, Ambala.

***99. Seth Ram Dass Dhamija:** Will the Minister for Health be pleased to State—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to re-model/revovate the building of the Civil Hospital in Ambala Cantt.

(b) whether the bed strength of the said Hospital is also proposed to be raised; and

(c) if so, the details thereof togetherwith the details of the new X-Ray plants and Ambulace Vehecles, if any, proposed to be purchased?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमति प्रसन्नी देवी):

(क) नही जी।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नही है, परन्तु इस बारे मांग तथा रोगियां की सख्या को ध्यान मे रखते हुए विचार किया जा सकता हैं।

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) के सम्मुख प्र न ही उत्पन्न नही होता।

श्री राम बिलास भार्मा: मंत्री महोदय ने भाग 'ख' के उतर मे कहा है कि रोगियो की संख्या को ध्यान मै रखते हुए विचार किया जा सकता हैं। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि यह विचार कितने समय मे किया जा सकता हैं।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, जब भी पैसा मिल जाएगा उस वक्त जितना विस्तार करने की जरूरत होगी उतना विस्तार कर दिया जाएगा।

सैठ राम दास धमीजा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने तीनों भागो का जवाब न में दिया हैं। स्पीकर साहब, अम्बाला छावनी बहुत बड़ा भाहर हैं। लगभग एक लाख की आबादी यहा की हैं और दौ लाख की आबादी आसपास के गावों की हैं। पहले यह अस्पताल मिलिटरी एडमिनिस्ट्रे ान के नीचे था। लेकिन बाद में स्टेट गवर्नमैंट ने ले लिया और जब से एक पैसा भी इस पर नही

लगाया गया हैं। मन्त्री महोदया, का जवाब ना जसल्लीबक ा हैं। चीफ मिनिस्टरप साहब ने हाउस में वायदा किया था कि और बजट में से कुछ हिस्सा काट कर इस हस्पताल की तरफ पूरी जबज्जो दी जाएगी तथा 31 मार्च तक इस अस्पताल में ऐम्बूलैंस आ जाएगी और एक्सरे तथा दिगर सहूलियते अगले सात तक दी जाऐगी। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि इस मुनाासिब काम को कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, इस अस्पताल की बिल्डिंग को पी.डब्लयू.डी. ने कन्डैम किया हुआ हैं। अगर इस सारी बिल्डिंग को नए सिंरे से बनाया जाता हैं तो 225 लाख रूपया खर्च करना पड़ेगा और अगरप इसकी रिपेयर की जाए तो 68 लाख रूपया चाहिए। स्पीकर साहब, हमारे बजट मे हैल्थ के लिए केवल 70.70 लाख रूपया रखा गया हैं। इसलिए जब भी बजट में पैसा बढ़ जाएगा इसको ठीक करवाने का यत्न किया जाएगा। इस वक्त समस्या पैसे की हैं।

Shri Mangal Sein: Speaker, Sir in reply to part (b) of this question it has been written as under:-

"There is no proposal but it can be considered depending upon the demand and attendance of patients.

क्या मंत्री महोदया बातने की कृपा करेगी कि कितने पै ोन्टस के बाद किसी अस्पताल को अपग्रेड किया जाता हैं ओर

दूसरी सारी फैसिलीटीज प्रोवाइड की जाती हैं और क्या दूसरे अस्पतालों का अपग्रेड करने के लिए भी कोई डिमान्ड आई हैं?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, फैसिलीटीज बढाने के बारे में डिमान्ड और भी बहुत से अस्पतालों की है ओर फेसिलीटीज बढनी भी चाहिए क्योकि स्वास्थ्य की सेवाए जितनी ज्यादा से ज्यादा दी जा सकती हो उतनी दी जानी चाहिएं लेकिन स्पीकर साहब, बजट के मुताबिक ही चलना पड़ता है।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने कहा कि पैसे की कमी है और इस वजह से उनकी मजबूरी हैं। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि अम्बाला छावनी के साथ ज्यादती करने का क्या कारण हैं?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः अध्यक्ष महोदय, ज्यादती किसी के साथ नही हो रही हैं। अम्बाला सिटी में दो सौ बैडज का अस्पताल हैं औरप अम्बाला छावनी में पचास बैडज का अस्पताल हैं। दोना मिलकर अढाई सौ बैडज के अस्पताल बन जाते हैं ओर कोइ दिक्कत की बात नही हैं। लेकिन असली पैसे वाली बात हैं। जब भी पैसा आ जाएगा काम कर दिया जाएगा।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने माना हैं कि इस अस्पताल की कंडी ान ठीक नही हैं, छते गिरी हुई हैं और यह मुरम्मत गांगती हैै। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि जहा–जहां पर सी.एम.साहब ने नए अस्पताल बनाने की

घोशणा की हैं वहां पर पहले अस्पताल बनाए जाएगें या वहां का फण्ड काटकर जो बिल्डिंग पहली बनी हुई है उनकी मरमम्त या रैनोवे ान पर पैसा खर्च किया जाएगा?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, जिस अस्पताल की बिल्डिंग ठीक नही हैं, जैसे अम्बाला छावनी के बारे में कहा गया हैं, जहां दवाईयों की कमी हैं, जहां डाक्टर नही और जहां पर ऐम्बूलैंस नही है वहा पर और जगह का पैसा काटकर इन्तजाब किया जाएगा। स्पीकर साहब, ऐसी जगहों पर सरकार पूरी तरह से पूरा इन्तजाम करेगी।

श्री मनफूल सिंह: क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेगी कि असन्ध मे कितने बैडज का अस्पताल है?

(इस प्र न का उतर नही दिया गया)

श्री फतेंह चन्द विज: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने रिटन रिप्लाई मे कहा है कि पे ोन्टस की संख्या देखकर विचार किया जा सकता है और सप्लीमैन्टरी के जवाब में कहा है कि पैसा नही हैं इसलिए काम नही हो सकता। क्या मंत्री महोंदया बताने की कृपा करेंगी की कौन सा जवाब ठीक है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: जो मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है वह जवाब ठीक हैं।

श्री हरिचन्द हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने कहा हैं कि जो भी अस्पताल खराब हालत मे होगा हम उसका इन्तजाम पहले करेगें। अध्यक्ष महोदय, रोहतक सिविल अस्पताल में जब भी बरसात होती हैं तो लगभग चार–चार फुट पानी भर जाता हैं। क्या मुख्यमंत्री महोदय सिविल अस्पताल रोहतक के बारे में भी कुछ विचार करेगें।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदया, मैने कहा है कि जिस अस्पताल की बिल्डिंग खराब होगी उसकी मरम्मत की जाएगी। अस्पताल के अन्दर पानी भी जाता हैं यह अलग बात हैं। अध्यक्ष महोदय मैने खुद ने देखा है कि रोहतक भाहर में बहुत सी जगह ऐसी है जहां बरसात में पानी खडा़ हो जाता है। हमारी मंत्री महोदया ने भी गली गली घूम कर देखा हैं। सरकार ने सारे भाहर के लिए स्कीम बनाई है और चालू भी कर दी हैं तथा हमारी पूरी कोि ा ा है कि अगली आने वाली बरसात मैं पहले हम ऐसा इन्ताजाम कर दे जिससे कि वहा पर पानी इक्ट्ठा न हो। इसमें थोड़ा बहुत सयय लग सकता हैं लेकिन हमारी कोि ा ा हेागी कि अगली बरसात मे रोहतक भाहर में पानी इक्ट्ठा न हो।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदया, मै मुख्य मंत्री महोदय का बहुत म ाकूर हूं कि इन्होने रोहतक के लिए स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि यह योजना कब तक पूरी हो जाएगी और क्या उस अस्पताल मे बैडज बढाने तथा दूसरी फैसिलिटीज बढाने के बारे में वहा से कोइ

रिप्रेजैन्टे ान इनका मिला हैं। अगर हां तो अब तक क्या एक ान लिया गया हैं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से अपने वजीर साहब से एक बात बताना चाहता हूं।(व्यवधान व भाोर) मेन सवाल तो 1978–79 और 1979–80 के बारे में है लेकिन इनके पास अपटूडेट जवाब तो तैयार होगा। क्या उनकी नालेज में कोई ऐसी बात है 1982–83 में रोहतक मंडी मे नीलामी हुई थी और क्या वहां पर किसी कैटेगरी के लिए साईटस रिजर्व की हुई हैं? क्या मुख्य मंत्री जी ने लाईसैंस होलडर्ज को यानि व्यापारियों को रिजर्व प्राईस ऊपर जमीन देने का वायदा किया था। क्या वे यह भी बताएगें कि औक ान कैसे की जाती हैं?

सरदार हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, इस सवाल की आड़ में रोहतक की मंडी के बारे में पूछने की कोई रैलेवैसी नही हैं। वैसे मंडियो में हम जो औक ान करते हैं वह समय–समय पर की जाती हैं। जब औक ान रिजर्व प्राईस से ऊपर चली जाये जो वह औक ान ऐप्रूव हो जाती हैं औरप जहां पर प्राईस कम रह जाए तो वह औक ान ऐप्रूव नही होती। कुछ देर इसलिए वेट करते हैं ताकि मंडियो की कुछ डिवैल्पमैंट हो जाए ओर औक ान में प्राईस ज्यादा आ जाए। इसलिये समय समय पर औक ान की जाती हैं। मंडी रोहतक में कब औक ान हुई ओर कितने प्लाट बाकी रह गए, इसके लिए डाक्टर साहब अलग से नोटिस देगें तो सारी बात इन्हे बता दी जाएगी।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरा प्र न बड़ा ही सिम्पल था कि आया मुख्य मंत्री महोदय ने किसी औल्ड लाईसैंसी को इस तरह की साईटस रिजर्व प्राईस के ऊपर देने का आ वासन दिया था।

श्री अध्यक्षः उन्होने कहा कि यह बात उनके इल्म में नही हैं।

श्री नेकी रामः अभी मिनिस्टर महोदय ने यह जवाब दिया हैं कि 1981 में कुछ मंडिया ऐग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड को ट्रांसफर हुई हैं। क्या वे बताएगें कि बोर्ड द्वारा हरिजनो को कितनी दुकाने दी गई है?

सरदार हरपाल सिंहः ऐग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड में इस तरह की रिजर्वे ान हैं। उनके द्वारा कितनी दुकाने दी जा चुकी हैं या नही दी जा चुकी हैं, इस बारे में चौधरी सुरेन्द्र सिंह जी ही ठीक बता सकते हैं। लेकिन मैं इनता ही बता सकता हूं कि रिजर्वे ान उसमें अव य हैं। 5 परसैन्ट हरिजनो के लिए और 10 परसैन्ट औल्उ लाईसैसीज के लिए रिजर्वे ान हैं।

श्री नेकी रामः स्पीकर साहब, मेरा सवाल है कि बोर्ड को कितनी मंडिया ट्रांसफर हुई और उनमे कितनी दुकाने हरिजनो को अलाट की गई हैं?

सरदार हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, बोर्ड को 1981 में 10 मंडियां ट्रांसफर हुई थी और 35 मंडियां अब डिपाटमैंट के पास हैं।

प्रो. सम्पत सिहंः स्पीकर साहब, जो जमीन मंडियों के लिए ऐक्वायर की जाती हैं, उस जमीन का मालिक अमूमन किसान ही होता हैं या कोई दूसरा व्यक्ति होता हैं। उन मंडियो में चाहे रैजिडैंि ाचल प्लाटस दिए जाएं या दूकानो के लिए प्लाटस दिए जाए क्या जिन किसानो की जमीने ऐक्वायर की जाती हैं, उनको भी कोई इस मामले रिजर्वे ान दी जाती हैं यानि उन लोगों को रिजर्व प्राईस पर प्लाटस दिये जाते हैं या नही?

सरदार हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, 1960 के न्यू–मण्डी टाऊन ि ासप ऐक्ट में इस तरह का कोई प्रोविजन नही हैं और जितने भी प्लाट्स चाहे रैजिडैन्ि ायल हैं या भौापस के हैं, सभी प्लाट्स औक ान पर दिये जाते है।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी सवालो का जवाब देते हुए कहा है कि कुछ रिजर्वे ान रखी जाती हैं लेकिन अपने लिखित जवाब में यह कहा कि कोई रिजर्वे ान नही हैं। क्या मंत्री जी बताएगें कि लिखित उतर में ऐसा क्यो लिखा गया हैं?

सरदार हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, केवल कोलोनाईजे ान डिपार्टमैंट में कोई रिजर्वे ान नही हैं।

कृशि मंत्री(चौधरी सुरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि औलड लाईसैनसीज की प्रोपोजल हमारे पास आयी थी और उस पर पूरी तरह से विचार विर्म ा करके बोर्ड की मिटिंग में यह फैसला किया गया कि ओल्उ डीलर्ज को प्लाटस दे दिये जाए। स्पीकर साहब, मै अब हाउस की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि अब जितने प्लाटस हैं उससे ज्यादा लाईसैन्सीज हमे मिल जाते हैं। रिजर्वे ान का जहां तक सवाल हैं, बोर्ड ने यह फैसला किया है कि 10 परसैन्ट ऐक्स सर्विसमैन के लिए, 5 परसैन्ट हरिजनों के लिए, 10 परसैन्ट बैकवर्ड क्लसिज के लिए और 10 परसैन्ट उन लैन्ड ओनर्ज के लिये जिनकी जमीन सरकार ने मंडियो के लिए ऐक्वायर की है, रिजर्वे ान दी जाए।

चौधरी हुकम सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया कि ऐक्स सर्विसमैन के लियें, बैकवर्ड क्लासिज के लोगों के लिये और हरिजनों के लिये सरकार ने प्लाट्स में रिजर्वे ान दी हैं लेकिन जो किसान अनाज पैदा करता हैं और फिर मंडियो मे लाता हैं उनके लिये ऐसा प्रोविजन क्यो नही हैं? क्या सरकार ऐसा करने का विचार रखती ताकि किसान को भी कुछ राहत मिल सके?

चौधरपी सुरेन्द्र सिंहः ग्रेअर्ज के लिए तो पहल ही हमने ग्रेन मर्किट्स में सभी तरह की सहूलियतें दी है लेकिन जहां तक प्लाट्स का ताल्लुक हैं, उनके लिये तो ओपन औक ान होती हैं।

उसमे ग्रोअर्ज भी ले सकते हैं और ऐक्स सर्विस मैन भी ले सकते हैं। हरिजनो में ग्रोअर्ज बहुत से होते हैं।

श्री नेकी रामः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बतांएगे कि जहां पर आबादी थोडी़ है वहां पर रिजर्वे ान ज्यादा ओर जहा पर ज्यादा आबादी हैं वहा पर रिजर्वे ान थोडी़ की गई हैं, इसके क्या कारण हैं।

श्री अध्यक्षः यह कोई क्वै चन नही हैं।

चौधरी भाग मलः अध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर बाताया गया कि 10 परसैन्ट ऐक्स सर्विसमैन के लिए, 10 परसैन्ट बैक्वर्ड क्लासिंज के लिए 10 परसैन्ट लैन्ड औनर्स के लिए और 5 परसैन्ट हरिजनो के लिए प्लाटस वगैरह की अलाटमैनट में रिजर्वे ान हैं। क्या मंत्री महोदय बताएगें कि एसी ऐनीमली क्यो हैं?

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, इसमे किसी किस्म की ऐनामली नही हैं। बड़ी बात यह हे कि हरिजन इससे ज्यादा लेने के लिये भी नही आते।

Boards and Corporations Covered under the companies Act.

***214 Dr. Bhim Singh Dahiya:** Will the Minsiter for Finance be pleased to State—

(a) the names for Boards and Corporations in the State covered under the Companies Act and have a paid up share capital of Rs. Twenty five lacs or more; and

(b) the names fo companies (Boards and Corporations) out of those referred to in part (a) above which have appointed duly qualified Company Secretaries?

Finance Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar):

(a) Eleven Corporations and 3 companies (subsidiaies fo Haryana State Industrial Development Corporation Ltd.) have been injcorporated under the Companies Act an have a paid-up share copital of Rs.25 lakhs or more in the state.

A list of such Corporations and Companies is given at annexure “A”

(b) 7 Corporations and 3 Companies (Subsidiaries of Haryan State Industrial Development Corporation Lte.) out of those referred to in part (a) above, have appointed qualified

A list of such Corporations and Companies is given at annexure “B”

ANNEXURE “A”

Name of corporation/Companies covered under the companies Act and have a paid up share capital of Rupees twenty five lacs more-

Corporations

1. Haryana Agro Industries Corporation Ltd Chandigarh.

2. Haryana Handloom & Handicrafts Corporation Ltd. Chandigarh.

3. Haryana Harijan Kalyan Nigam Ltd. Chandigarh.

4. Haryana State Industrial development Corporation Ltd.

5. Haryana Land Reclamation & Development Corporation Ltd. Chandigarh

6. Haryana State Minor Irrigation (Tubewells) Corporation Ltd. Chandigarh

7. Haryana State Small Indsutries and Export Corporation Ltd. Chandigarh.

8. Haryana Seeds Development Corporation Ltd. Chandigarh

9. Haryana Tourism Corporation Ltd. Chandigarh

10. Haryana Backward Classes Kalyan Nigan Ltd. Chandigarh.

11. Haryana Economically Eeaker Sectorns Kalyan Nigan Ltd. Chandigarh.

Companies.

1. Haryana Concast Ltd. Satrod (Hissar).

2. Haryana Tanneries Ltd. Jind.

3. Haryana Breveries Ltd. Murthal

ANNEXURE "B"

Name of corporation/Companies which have a paid up share capital of Rs.25 lacs or more and have appointed qualified Company Secretaries.

Corporations

1. Haryana Handloom & Handicrafts Corporation Ltd. Chandigarh.

2. Haryana State Industrial development Corporation Ltd.

3. Haryana Land Reclamation & Development Corporation Ltd. Chandigarh

4. Haryana State Minor Irrigation (Tubewells) Corporation Ltd. Chandigarh

5. Haryana State Small Indsutries and Export Corporation Ltd. Chandigarh.

6. Haryana Seeds Development Corporation Ltd. Chandigarh

7. Haryana Tourism Corporation Ltd. Chandigarh

Companies.

1. Haryana Concast Ltd. Satrod (Hissar).

2. Haryana Tanneries Ltd. Jind.

3. Haryana Breveries Ltd. Murthal

डा0 भीम सिंह दहियाः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने खुद माना है कि चार कोर्पोरे ान ऐसी हैं जिनमे कम्पनी सैक्रटरी नही हैं। मै मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन चार कोर्पोरे ान कितने अरसे से कम्पनी सक्रेटरी नही हैं और उनको अप्वायंट न करने की क्या बजह थी?

चोधरी कटार सिंह छोकरः अध्यक्ष महोदय, इन चार कोर्पोरे ांज/कम्पनीयों भ्रुरू से ही कम्पनी सक्रेटरी नही हैं। वे अब इसलिए नही लगाए जो सके क्योकि क्वालीफाईड कम्पनी सैक्रेटरी नही मिल पाए।

श्री राम बिलास भार्माः क्या मन्त्री महोदय बताऐगे कि जिन 11 कोर्पोरे ान के चेयरमेन लगए गए है उनमे से नान औफि्सयल कितने है और उनको चैयरमैन नियुक्त करते समय किस खास बात का ध्यान रखा गया था?

चोधरी कटार सिंह छोकरः अध्यक्ष महोदय, यह कम्परी सैक्रेटरी के बारे मे सवाल था, इसमे चेयरमैन का कोई सवाल नही हैं। अगर अलग से नोटिस दिया जाऐगा तो बता दिया जाऐगा।

डा0 भीम सिंह दहियाः अभी मन्त्री जी ने कहा कि क्वालिफाईड कम्पनी सेक्रेट्रीज अवेलगबल नही हैं। मै जानना चाहूगां कि इन चार कार्पोरे ांज ने क्या कया प्रयन्त किए? कइी पोस्टे ऐडवरटाइज की या कोई और कोि ा ा की? दूसरे कम्पनी

ऐक्ट के तहत यह भी है कि अगर क्वालिफाइड सैकेटरी अपवायंट नही किया जाता तो सैट्रल गर्वनमैंट कोर्पोरपे ान के खिलाफ कोई ऐक ान इनि ियेट करती हैं। मै जानना चाहता हूं कि क्या किसी कार्पोरे ान के खिलाफ कोई एक ान लिया गया?

चोधरी कटार सिंह छोकरः स्पीकर साहब, जहां तक पोस्ट भरने के लिए प्रयत्न की बात हैं, ये कुल चार कार्पोरे ान है जिसमें कम्पनी सैक्रेटरी नही है। इनमे दो तो बहुत ही थोंडा अरसा पहले बनी हैं। एक बैकवर्ड क्लासिज कल्याण निगम हैं जो 1980 मे बनी थी और दूसरी इकोमिकल बैकवर्ड क्लासिज कल्याण निगम हैं जो 1982 मे बनी थी। इसके काम का अभी बहुत ज्यादा विस्तार नही हुआ हैं कि कम्पनी सैक्रेटरी लगाए जांए। इसके अलावा जो दो ओर कार्पोरे ान है उनमें एक हरिजन कल्याण निगम हैं जिसके लिए दो बार एम्पलायमैंअ एक्सचैंज को डिमांड भेजी गई हैं लेकिन कोई आदमी नही मिला एक बार अखबारों मे एडवरटाईजमैंअ की गई। सात आदमियों ने एप्लाई किया था जिनमें से तीन आदमी आए। तीन में से दो आदमी ऐसे थे जो पहले ही ज्यादा ग्रेड ले रह थे, उन्होने यहा आने से मना कर दिया। तीसरा आदमी जो था वह क्वालीफाईड नही था। चहा तक चौथी कार्पोरे ान एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरे ान का सवाल है उसके लिए भी बार बार अखबारेां में ऐजबरटाईजमैंट की गई। तीन बार लोगों ने एप्लाई किया। एप्लीके ान आई, प्रोसैस की गई लेकिन कोई भी आदमी क्वालीफाईड नही पाया गया। जहां तक गवर्नमैंट

आफ इडिंया द्वारा कोई एक ान लेने का सवाल हैं उसके बारे मे पोजी ान यह है कि जैसी कोई बात होती हैं उसके लिए गवर्नमैंट लिखती रहती हैं कि ऐसा कोई आदमी लगाया जाए। इसके अलावा ओर कोई कार्यवाही नही हुई

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, अभी वित मंत्री महोदय ने फरमाया कि जो लोग आए वे आलरेडी ज्यादा ग्रेड ले रहे थे, उनको अट्रैक्यान नही हुई और वे वापिस चले गए। उनके अलावा इनकों क्वालिफाईड आदमी नही मिले। मै मंत्री ही से जानना चाहूंगा कि उस पोस्अ के लिए रिक्वीजिट क्वालिफिके ान क्या हैं? दूसरे क्या इन्होने यह विचार किया कि इन हालात के अन्दर जब लोग कम तनख्वसह पर आना नही चाहते तेा तनख्वाह को इनक्रीज करके तथा और सुविधाएं ज्यादा देकर इन कार्पोरे ांज को संभालने के लिए कोई ऐसा विचार कर रहे हैं कि दोबारा पोस्टें एडवरटाइह की जाए?

चौधरी कटार सिंह छोकरः अध्यक्ष महोदय, जहां तक ज्यादा तनख्वाह बढाने की बात हैं, ऐसा विचार तो नही किया गया। लेकिन टर्म्ज इतनी सख्त नही थी बल्कि ओपन थी अगर कोई सूटेबल कैंडीडेट होता तो विचार किया जा सकता था। कम्पनी सैक्रेटरी के लिए क्वालीफिके ान एक ही हैं कि आदमी के लिए इस्टीच्यूट आफ कम्पनी सैक्रेटरीज का मैम्बर होना अनिवार्य हैं।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन कम्पनी सैक्रेटरीज को न लगाने की वजह से क्या इन चार कोर्पोरे ान को घाआ हुआ? क्या सरकार आवयकता समझती है कि इनको लगाए जाए या नही? दूसरे क्या सरकार हरियाणा कनकास्अ लिमिटिड वगैरह को लीज आऊट या सेल करने की सोच रही हैं?

चौधरी कटार सिंह छोकरः हरियाणा कनकास्ट लिमिटिड को लीज आउट करने या सेल करने का इस सवाल से कोई संबंध नही है। वैंसे उसमें ता बाकायदा कम्पनी सैक्रेटरी लगा हुआ है। दूसरी बात जो इन कोर्पोरे ान में सैक्रेटरी लगाने की पूछी गई उसके लिए मैने पहले भी बताया कि दो कोर्पोरे ान ता अभी नही ही हैं जिसमें सरकार ने कम्पनी सैक्रेटरी लगाना ठीक नही समझा क्योंकि अभी काम काज इतना नही हैं। बाकी दो के लिए हमने पूरे प्रयत्न किए हैं और कर रहे हैं।

श्रीमती चन्द्रावतीः क्या मंत्री महोदय बताएगें कि क्वालीफाइड सैक्रेटरीज न लगाने की वजह से और इनका आडिट न करने की वजह से केन्द्र सरकार ने इन कोर्पोरे ान या कम्पनियों पर कोई जुर्माना भी किया है?

चौधरी कटार सिंह छोकरः कोई जुर्माना नही किया।

श्री हरि चन्द हुड्डा: क्या मंत्री महोदय बताएगें कि प्राईवेट कम्पनियों के मुकाबिले में हमारी कोर्पोरे ान में घाटा होने के क्या कारण हैं?

चौधरी कटार सिंह छोकर: केवल कम्पनी सैक्रेटरी न होने की वजह से ही घाटा नही हैं। मैम्बर साहब खुद भी जानतें होगें कि हमारी कोर्पोरे ान में बडी़ देर से तनख्वाहे भी बढी देर से तनख्वाहे भी बढी है तथा खर्चा भी बढा हैं। इस तरह से मंहगाई का असर इन पर भी हैं। फिर भी सभी संस्थाए घाटे में नही हैं, थोड़ी बहुत में घाटा हैं।

श्री निहाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने इकोनोमिक प्रोग्राम को चलाने के लिए स्टेटस को हिदायत दी थी कि जितनी अननसैसरी काम करने वाली कोर्पोरे ान हैं उनकी तादाद कम की जए ओर कोर्पोरे ान को अमलगामेट किया जाए। क्या मंत्री जी बताएगें कि इस सिलसिले में सरकार क्या कर रही है?

चौधरी कटार सिंह छोकर: जो ऐसी एन्टरप्राइजिज है उनको सुचारू रूप से चलाया जाए, यह भी बीस प्वायंट प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम है। सरकारप इसको समय समय पर रिव्यू करती रहती हैं। जहां किसी कोर्पोरे ान को दूसरी के साथ मिलाने की बात देख लेंगे। अगर कही आव यता पड़ा तो विचार कर लेंगे।

डा0 भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, जैसे अखबारें में आया हैं कि कम से कम दस कोर्पोरे ान ऐसी हैं जिनमें क्वालिफाइड कम्पनी सैक्रेटरीज लगने के बावजूद अम्बैजलमैंट हो गई * * * * ** * * *

श्री अध्यक्ष: आपने जो हरियाणा ब्रीवरीज की बात कही है, उस आप सवाल नही पूछ सकते क्योंकि उसकी रिपोर्ट अभी फाईनल नही हुई हैं। इसलिए हरियाणा ब्रीवरीज के बारे मै सवाल कार्यवाही से काट दिया जाए।

चौधरी कटार सिंह छोकर: अध्यक्ष महोदय, इनके सवाल के बाकी भाग को जहा तक सम्बन्ध अकाऊंटस में कोई कमी नही हैं। कायदे के मुताबिक बक्त्न–फवक्तन बाकायदा औडिट होता हैं। उसकी रिपोर्ट तैंयार होती हैं, रिव्यू तैयार होते हैं। पूरी चौकसी रहती हैं।

श्री कंवल सिंह: स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया कि दो नई कोर्पोरे ान हरियाणा बैकवर्ड क्लासिज कल्याण निगम और हरियाणा वीकर सैक ांज कल्याण निगम बनाई गई हैं। लेकिन हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कोर्पोरे ान बहुत पुरानी कोर्पोरे ान हैं और उसमें भ्रश्टाचार तथा इररैगंलर्टीज बहुत ज्यादा हैं। मै आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस कोर्पोरे ान में इन–रैगुलर्टीज और भ्रश्टाचार को मद्देनजर

रखते हुए सरकार उसमें कम्पनी सैक्रेटरी अप्वायंट करने के लिए कोई स्पै ान इन्जजाम करेगी?

चौधरी कटार सिंह छोकरः अध्यक्ष महोदय, मैने पहले ही अर्ज किया हैं कि हमने कम्पनी सैक्रेटरी अप्वायंट करने के लिए बहुत बार एडवर्टाइजमैंट की थी लेकिन कोई भी क्वालिफाईड कैंडीडेट नही मिला। अब सरकार ने एग्रो इंडस्ट्री कोर्पोरे ान में का एच0सी0एस0 आफिसर लगाया हुआ हैं वह कम्पनी सैक्रेटरी का काम भी करता हैं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, हरियाणा कनकास्ट लिमिटिड, सातरोड़ हिसान के पास हैं। उसमे चार करोड़ रूपय का घाटा हैं लेकिन उसके पड़ौस मे जा प्राईवेट लोग है वे अपनी फैक्टरीज चला रहे हैं और काफी पैसा कमा रहें हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हरियाणा कनकास्ट लिमिटिड में इतने ज्यादा घाटे का क्या कारण हैं?

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय–डाक्ब्र साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे है कि हरियाणा कनकास्ट लिमिटिड वाकई घाटे मे चल रही हैं । इस फैक्टरी में आज से घाटा नही है बल्कि जब से यह फैक्टरी लगाई हैं उसी समय से घाटे में चल रही हैं। इस फैक्टरी को प्रोफिट में लाने के लिए पूरे प्रयास भी किए गए हैं। जिस समय दूसरी फैक्टरीज के लिए बिजली का कट लगाया गया था उस समय इस फैक्टरी को सुचारू रूप से चलाने

के लिए आफिसर्ज भी छांट कर लगाए गए हैं ताकि किसी तरह से यह फैक्टरी प्रोफिट में आ जाए। इतने प्रयास करने के बावजूद अब वह फैक्टरी इतने घाटै में नही हैं। अब उसकी हालत पहले से अच्छी हैं। पहले उस फैक्टरी में हर महीने जो लगभग 15 लाख रूपये का घाटा था अब वह घाटा घट कर लगभग 6–7 लाख रूपय रह गया है।

तांराकिज प्र न एंव उतर

Allotment of Huda Plots at Sonepat

***233. Shri Devi Dass:** Will the Minister for Town & Country Planning be pleased to state—

(a) the number of plots cut in sector 14 of HUDA colony at sonepat together with the area of the said plots, separately;

(b) The conditions on which the said plots were allotted;

(c) Whether the conditions as mentioned in the agreement made between HUDA and plots holders have been fulfilled by HUDA; if not, the reason therefore;

(d) the number to plots out of these referred to in part (a) above the allotment of which has been cancelled together with the names of the concerned plot holders; and

(e) The criterion adopted for allotting the plots, referred to in part (d) above, to other persons together with the names and all addresses of the said persons?

Town & Country Planning Minster (Sardar Harpal Singh):

(a) The numbers of residential plots Covered in sector -14 sonepat are as under--

Size of plots	Total No. of Plots
160 Sq. Yards	260
250 Sq. Yards	446
350 Sq. Yards	332
500 Sq. Yards	304
	1342

(b) a copy of the conditions, as contained in allotment letters then issued, is placed on the Table of the House.

(c) The conditions pertaining to HUDA have been fulfilled.

(d) Nil.

(e) Question does not arise.

Copy of conditions.

Registered A.D.

From

The Estate Officers,

Urban Estate.

To,

Sh./Smt. --------

Memo No. ---------- /E.O.

Dated ---------- the ----------19.

Subject:- Allotment of Residential plots in the Urban Estate at----------

Reference you application dated ---------- for the allotment of a residential plot in the Urban Estate at ----------

1. Plot No. ---------- measuring ---------- in sector No. ---------- of the Urban Estate at ---------- is hereby allotted to you. The total tentative sale price of the said plot is Rs. ----------

2. The plot is preferential one and an additional price at the rate of 10 percent of the price mentioned in Para I above is Rs. ----------

3. The total tentative sale price of this plot (normal plus Preferential cost) is Rs. ----------

4. The above price of the plot is subject to variation with reference to the actual measurement of the plot as well as in case of enhancement of compensation of acquisition cost of land of this sector by the Court or otherwise and you shall have to pay this additional price of the plot, if any, as determined by the Department within 30 days from the date of demand.

5. You shall unless you refuse to accept this allotment by a Registered A/D letter within 30 days from the date of issue of this allotment letter, have to pay---------- percent of the total tentative sale price amounting to Rs. ---------- or such other amount which together with the amount already paid equals to at least ---------- percent of the total tentative sale price of the plot. In case of failure to deposit the said amount the allotments shall be cancelled and earnest money already paid forfeited for which you shall have no claim.

6. In case you refuse to accept this allotment through an acknowledgement due registered letter addr3essed to the undersigned within 30 days from the date of issue of allotment letter you will be entitled to the refund of the earnest money already paid by you.

7. On payment of 25 percent of the total tentative sale price of the plot you shall have to execute a Deed of Conveyance on the prescribed form in such manner as may be directed by the undersigned.

8. Balance---------- percent of the total tentative sale price shall be payable either in lump sum within

60 days from the date of issue of allotment letter without interest or in ---------- equated annual installments with interest at the rate of ----------percent per annum. the first and the remaining installments of the balance amount together with interest at the rate of ---------- percent per annum on the unpaid amount of the total tentative sale price shall fall due for payment as under and no notice shall be served upon you to pay the same but in case an installment is not paid in time, you will be served with a notice to pay the same within a month together with a sum not undersigned, by way of penalty. If the payment is not made with in undersigned, not exceeding three months in all from the date on which the installment was originally due, the same will be recovered as an arrear of land revenue of action will be taken under Section 10 of the Punjab Urbane states (Development and Regulation)Act 1964:-

Number of Installment	due date on which the payment is to be made
First	-------
Second	-------
Third	-------
Fourth	-------
Fifth	-------
Sixth	-------

9. Each remittance should be made to this office by means of a demand draft payable to the Estate Officer-------

and drawn on any schedule Bank situated at ------- Each such remittance shall be accompanied by a letter showing full particulars of the plot i.e. Plot No. -------, Sector No. allotment Letter No. and Dated etc. In the absence of these particulars, the amount shall not be deemed to have been received.

10. You shall have to pay separately for any building, Material, trees, structures compound wall etc., existing in the plot at eh time of allotment for which compensation has been assessed and paid by the Government, in case you want to make use of the same failing which the Government shall have the right to remove or dispose of the same even after the delivery of possession is handed over to you.

11. The allotment shall be liable to cancellation in case any of the declarations made in the application for the allotment of a residential plot is established to be incorrect.

12. You shall have to complete the building within three years form the date of issue of this allotment letter after getting the plans of the proposed building approved by the competent authority in accordance with the rules regulating the erection of buildings. This time limit is extendable only if it is found due to the cause beyond your control other wise this plot or building erected on it will be resumed and also the whole or part of the money, if any, paid in respect thereof forfeited.

13. The Government shall not be responsible for leveling the uneven plots and fragmentation of them is not permitted. Neither the plot nor any building erected thereon

can be used for a purpose other than for which it has been allotted.

14. You shall not transfer by way of sale, mortgagee gift or otherwise the site or any right, title or interest therein (except by way of lease on monthly basis) save with the sanction of the Chief Administrator till such time total sale price is paid and a building has been constructed on a minimum of at least 10 percent to the total permissible covered area of the plot.

15. This allotment is subject to the provisions of the Punjab Urban Estates(Development and Regulation) Act, 1964 and the rules framed the under as amended from the time to time and you shall have to accept and abide by them.

Estate Officer,

Urban Estate, Sonepat.

श्री देवी दासः स्पीकर साहब, मैंने अपने सवाल में यह पूछा था कि कितने आदमियों के प्लाट जब्त किए गए? मंत्री जी ने जवाब दिया है कि किसी का भी प्लाट जब्त नहीं किया गया। मेरी जानकारी में है कि सोनीपत के सैक्टर 14 में काफी लोगों के प्लाट जब्त किये गये है और वे लोग कोर्ट में अपील कर रहे है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन आदमियों के प्लाट जब्त किए गए है वे किस–किस को अलाट किए गए हैं?

सरदार हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर ने जो सवाल पूछा है उसमे थोड़ी सी गलती कर दी। इन्होनें जो

सवाल पूछा है उसमें सिर्फ यह पूछा है कि कितने प्लाट कैंसिल किए गए हैं यह नहीं पूछा कि कितने प्लाट रिज्युम किए गये हैं। कैंसिल करने में और रिज्युम करने में काफी फर्क है। हमने वहां पर कोई भी प्लाट कैंसिल नहीं किया यदि कोई प्लाट कैंसिल ही न किया हो तो किसी को अलाट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने कैंसिल और रिज्युम भाब्द का लाभ उठा कर बड़ी होि ायारी से सवाल का जवाब दे दिया कि सवाल पैदा नहीं होता। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वहां पर कितने प्लाटस रिज्युम किए गए है।

सरदार हरपाल सिंहः स्पीकर साहब इसके लिए सैपरेट नोटिस देना चाहिए कि कितने प्लाटस रिज्युम किए गए है। लेकिन वहां पर कोई भी प्लाट कैंसिल नहीं किया गया। जब किसी आदमी के पास प्लाट की आफर आ जाए और वह आदमी उस प्लाट की दस परसैंट अरनैस्ट मनी जमा करवा देता है तो उसके पास अलाटमैंट का लैटर चला जाता है। उसके साथ ही उसकों यह लिख दिया जाता है कि विद इन तीस डेज पंद्रह परसैंट मीन जमा करवाएं। अगर वह तीस दिनों के अंदर पंद्रह परसैंट पैसा जमा नहीं करवाता है तो उसकी अलाटमैंट कैंसिल कर दी जाती है। अगर वह पंद्रह परसैंट पैसा जमा करवा देता है तो उसके पास अलाटमैंट कंफर्मे ान का लैटर चला जाता है।

उसके बाद यदि वह बाकी इंस्टालमैंट जमा नहीं करवाता है और उसको जो तीन–चार साल का टाईममकान की कंस्ट्रक ान के लिए दिया हुआ होता है उसको फुलफिल नहीं करता है तो उसका प्लाट रिज्युम कर लिया जाता है। यदि वह तीन–चार साल तक जो उसको मकान की कंस्ट्रक ान के लिए टाईम दिया हुआ होता है मकान नहीं बनता है और उस प्लाट को ज्यादा पैसे लेकर बेचना चाहता है तो उस कंडी ान में बकायदा उसको एक महीने का नोटिस दिया जाता है। यदि वह फिर भी मकान की कंस्ट्रक ान भुरू नहीं करता तो उसको तीन महीने का नोटिस दिया जाता है। यदि वह फिर भी मकान नहीं बनाता तो उसको तीन महीने का नोटिस दिया जाता है। यदि वह फिर भी मकान नहीं बनाता तो वहां के स्टेट आफिसर को यह अथोरिटी है कि अगर कोई अलाटी कंडी ान फुलफील नहीं करता तो उसको हियरिंग देकर उसका प्लाट रिज्युम किया जाए।

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने अलाटी थे जो कंडी ान फुलफील नहीं करते थे जिसके कारण उनके प्लाट रिज्युम कर लिए गए?

सरदार हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, इसके लिए सेपरेट नोटिस चाहिए।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, जिन लोगों ने प्लाट खरीदे हैं उनमें से बहुत से ऐसे लोग भी है जिन्होन प्लाट तो खरीद लिए लेकिन मकान बनाने के लिए उनके पास पैसा नही हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास मकान बनाने के लिए पैसा नही क्या उन लोगों के लिए सरकार कर्जा देने का प्रावधान करेगी?

सरदार हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, प्राइम मिनिस्टर महोदया के नए 20 सुत्री कार्यक्रम के तहत हरियाणा सरकार ने वीकर सैक ांज के लिए हाउस कंस्ट्रक ान का काम भाुरू किया हैं। हम 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत लगभग 400 मकान फरीदाबाद में बना रहे हैं। वहां पर एक मकान की कौस्ट 16 हजार रूपय हैं जिनका हमने 12 हजार रूपये में देने का फैसला किया हैं।(थम्पिंग)

श्री हरि चन्द हुड्डाः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी, ने थोडी देर पहले यह कहा था कि वे रोहतक की गली–गली में घूम कर आए हैं। क्या इनकी जानकारी में यह बात है कि हुड्डा वाले करोड़ो रूपय की जायदाद बनाकर बेठे है।(ाोर एव विघ्न)

श्री अध्यक्षः यह कोई सवाल नही है।

श्री देवी दासः स्पीकर साहब, सैक्टर 14 के अन्दर इन्होने पहले सड़के बना दी थी, अब पाईप डाल रहे हैं जिस के कारण वहा की सारी सड़के टूट गई हैं मैं मंत्री महोदय से जानना

चाहता हूं कि क्या पले पाईप लाईन डालकर सडके बाद में बनाने का विचार हैं?

सरदार हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, अर्बन सैक्टर सोनीपत में हुड्डा की तरफ से जितनी सुविधा दी जानी थी वे सारी दे दी गई हैं। वहांपर वाटर सप्लाई, सिवैरज, रौड़स और बिजी आदि पकी सारी सुविधा दे दी गई हैं। मै आनरेबल मैम्बर्ज को रिक्वैसट करूंगा कि वे अब जाकर अर्बन सैक्टर को देखे कि अर्बन सैक्टर कितनी अच्छी तरह से डिवैल्प हो रहा हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हुड्डा की तरफ से अर्बन सैक्टर्ज को ब्यूटीफाई करने के लिए हार्टिकल्चरप की प्लान भी भुरू की जा रही हैं। वहां पर 20 परसैन्ट प्लाट वीकर सैक ान के लिए भी रिजर्व रखे हैं। डिवैल्पमैंट पूरी हो रही है। मैम्बर साहब द्वारा उस अर्बन सैक्टर को जा कर देखें, ओर उसके बाद यहा पर सवाल पूछें।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मुझे यह सुन कर बहुत प्रसन्नता हुई कि हुड्डा की तरफ से वहां पर हार्टिकल्चर की स्कीम भी बनाई जा रही हैं यानि डिवैल्प हो रही हैं। साथ ही इन्होने यह भी कहा हैं कि हमें वहा पर जाकर खुद देखना चाहिए। मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप मेरी कांस्टिच्यूऐंसी रोहतक में आएं। आपने जो कमर्ि ायल कम्पलैक्स बनाया हैं और जहां लोग इजी होने के लिए जाते हैं उसे जा कर देखें। वहां पर

सरकार की तरफ से करोड़ो रूपये का कम्पनसै ान कमर्ि ायल कम्पलैक्स के लिए दिया गया हैं और वह चार साल से पैंडिग है।

सरदार हरपाल सिंहः वहां पर हुड्डा की तरफ की से कोई सैक्टर डिवैलप नही हो रहा।

श्री मंगल सैनः कमर्ि ायल कम्पलैक्स का क्या बना?

सरदार हरपाल सिंहः हुड्डा की तरफ से कमर्ि ायल कम्पलैक्स अभी तक कम्पीलट नही हुआ हैं।

श्री मंगल सैनः उनको पूरा करने के लिए सी.एम. साहब ने भी कह रखा हैं। स्पीकर साहब, यह बड़ा सीरियस मामला हैं। वहां पर 4–5 करोड़ रूपये की सम्पति लगी हुई हैं, उसको जरूर टेक–अप करना चाहिए।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): इसको जरूर देखेंगें।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः स्पीकर साहब, हुड्डा लेण्ड औनर की जो जमीन एक्वायर करता हैं और उसका जो कम्पनसे ान किसानों को दिया जाता हैं उसमें एक और 100 रूपये का अन्तर हैं। मै पूछना चाहता हूं कि इतना अधिक अन्तर क्यों हैं?

सरदार हरपाल सिंहः हुडडा नो प्रोफिट और नो लोस बेसिज पर काम करता हैं। हुड्डा जमीन एक्वायर करने के बाद प्लाटों की औक ान करता हैं। हुड्डा कोई प्रोफिट बौडी नही हैं।

पिछले सै ान में भी सी.एम. साहब ने सदन को आ वासन दिया था कि किसानों की जो जमीन एक्वायर की जायेगी उसका उचित मुआवजा दिया जाऐगा। उसी आधार पर सरकार ने अब पोलिसी रिवाईज की हैं। सदन में बताते हुए मुझे खु ाी होती हैं कि रिवाईज्ड पोलिसी के अनुसार यदि किसानेां की जमीन एक्वायर होती हैं तो उनको भविश्य में मार्किट प्राइस दी जाएगी। जो उचित मुआवजा देने की कोि ा ा की जाऐगीं मेरे ख्याल में अब किसी भी मैम्बर को इस संबंध में कोई ि ाकायत नही आयी होगी। भविश्य में ज्यादातर जमीन किसानों को एक्वायर न करने की कोि ा ा पूरी–पूरी की जायेगी। यदि कही जरूरी हुआ तो उसी हालत में किसानों की जमीन एक्वायर की जायेगी क्योंकि सरकार भी किसानों की आम जमीन लेने के हक में नही हैं।

श्रीमती चन्द्रवतीः भाहरों के आसपास जो जमीन एक्वायर करते समय इकट्ठी जमीन एक्वायर की जाती हैं। बीच मे किसी को छोड़ा नही जाता। हमारे पलानर जो प्लान बनाते है उसी हिसाब से जमीन एक्वायर की जाती हैं। किसी साईड में रैजिडैन्ि ायल परपजिज के लिए जमीन एक्वायर करनी होती हैं, किसी तरफ इण्डस्ट्रीज के लिए और किसी तरफ कमि र्ायल साइटस के लिए जमीन एक्वायर करनी होती हैं। जिस तरह के एरिया की जरूरत होती हैं, उसी हिसाब से इकट्ठी जमीन एक्वायर की जाती है।

श्रीमती चन्द्रावती: बल्ल्भगढ़ के पास झाड़ सेतली गांव हैं। वहां जमीन एक्वायरप करते समय बड़े–बड़े लोगों की ओर इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स की जमीन दी गई जबकि छोटे–छोटे किसानों की जमीन एक्वायर कर ली गई हैं।

श्री अध्यक्ष: इस सप्लीमैंटरी का इस सवाल से कोई संबंध नही है।

Construction of an over-bridge at railway crossing, Kurukshetra

***220. Chaudhri Sahab Singh Saini:** Will the Minister of State for Public Works (B&R) be pleased to state—

(a) whether an over-bridge at the railway crossing, Kurukshetra, has been sanctioned; if so, the date of the sanction thereof; and

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative the time by which the construction of the said over-bridge is likely to be started?

Minister of State for Public Works(Chaudhri Goverdhan Dass Chauhan):

(a) The consent of the Railways to share the cost of the over-bridge has been received and the formal sanction of the works will be issued shortly.

(b) The construction will be taken up during 1983-84.

चौधरी साहब सिंह सैनीः स्पीकर साहब, पुल के खर्चे का हिस्सा देने के लिये रेलवेज की सहमति हो गई हैं ओर दूसरी भार्ते भी पूरी हो चूकी है मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या 1983–84 के अन्दर ही वहा पर काम भूरू हो जायेगा?

चोधरी गोवर्धन दास चौहानः स्पीकर साहब, इसी मार्च में भारत सरकार से सैक ान आई हैं। इस काम के लिए 1983–84 का जा साल दिया है इसका मतलग है कि इसी साल के अप्रैल मे हम भी अपनी सैक ान भेज देंगें उसके बाद इस पुल पर कन्सट्रक ान का काम भाुरू हो जाऐगा।

चौधरी औम प्रका ाः मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ओवरब्रिज बनाने का क्या क्राईटेरिया हैं? रोहतक और सोनीपत के अन्दर कई सड़को पर बड़ी भीड़ रहती हैं। इसलिए मै जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे भाहरों मे आवरब्रिज बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

चोधरी गोवर्धन दास चौहानः स्पीकर साहब, एक क्राईटेरिया तो यह भी है कि जिन सड़को पर ज्यादा भीड़ भड़ाका रहता हैं, उन पर ओवर ब्रिज बनाये जाये। यह सवाल धार्मिक स्थल कुरूक्षेत्र से संबंधित था इसलिए इसका जवाब दिया गया है ओर इस पर काम भी भीघ्र ही भाुरू होने जा रहा हैं जिन रोड़ज पर ज्यादा भीड़ रहती हैं और लोगों की डिमांड होती हैं, उसी आधार पर हम ओवर ब्रिज बनाने की कोि ा ा करते हैं।

श्री नेकी रामः स्पीकर साहब, हिसान का औवरब्रिज आधा बना हैं और आधा बनना बाकी रहता हैं। मै जानना चाहता हूं कि यह कब तक पूरा हो जाऐगा?

चोधरी गोवर्धन दास चौहानः स्पीकर साहब, इस पुल पर काम चल रहा हैं और जल्दी ही इस को पूरा कर दिया जायेगा।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इन्होने अभी फरमाया है कि ओवरब्रिज वहा पर बनाया जा सकता हैं जहां पर भीड़–भडका ज्यादा हैं या ट्रैफिक जाम होती हैं। पानीपत के बारे मे इन्होने स्थिति स्पश्ट नही की। मै पूछना चाहता हूं कि क्या रोहतक के डिप्टी कमि नर ने यह लिख कर भेजा हैं कि झज्जर जाने वाली जो सड़क हैं, उस पर ओवरब्रिज बनना चाहिए। क्या ऐसी कोई बात आपके नोटिस में हैं?

चोधरी गोवर्धन दास चौहानः यह सवाल कुरूक्षेत्र से संबंधित था। जहां तक रोहतक के डी.सी. द्वारा कोई रिकमैंन्डै ान करके भेजने का सवाल हैं, उसके बारे में मुझे मालूम नही हि उन्होन को रिकमैंन्डै ान की है या नही।

श्री फतेह चन्द विजः स्पीकर साहब, पानीपत के अन्दर जी.टी. रोड़ पर पहले ही बहुत भीड़ रहती है। अब वहां पर एक तेंल भाोधक कारखाना लगने जा रहा हैं ओर वहा पर थर्मल प्लांट भी है, जिस कारण अब और भी अधिक भीड़ होने की आ ाा हैं।

मै जानना चाहता हूं कि क्या पानीपत के अन्दर कोई ओवर ब्रिज बनाने का विचार हैं।

चोधरी गोवर्धन दास चौहानः स्पीकर साहब, वैसे तो इस सवाल का मूल सवाल के साथ कोई सम्बन्ध नही हैं लेकिन जानकारी के लिए मै बता देता हूं कि यह मामला विचारधीन हैं, जल्दी ही इस पर गौर किया जाएगा।

Vacant posts of M.B.B.S. Doctors.

***250. Shri Fateh Chand Vij:** Will the Minister for health be pleased to state—

(a) the total number of Posts of M.B.B.S. Doctors lying vacant in the State as on 31.01.1983;

(b) the time by which the said posts are likely to be filled up;

(c) whether the Government proposes to provide one doctor for every 5000 persons in the State; and

(d) if so, the times by which the said proposal is likely to be implemented?

Health Minister (Shrimati Prasanni Devi):

(a) 93

(b) Appointment orders have already been issued in all cases.

(c) No.

(d) Question does not arise.

श्री फतेह चन्द विजः स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने पार्ट(डी) के जवाब में कहा है कि "Question does not arise" क्या यह मुनासिब नही है कि 5 हजार की आबादी के पिछे एक एम.बी. बी.एस. डाक्टर हो जाए?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, इन्होने जो सवाल पूछा था, उसका मैने उतर दे दिया हैं। जहां तक 5 हजार की आबादी के पिछे डाक्टर देने का सवाल हैं, ऐसी कोई स्कीम नही है, क्योकि 5 हजार की आबादी बहुत कम हैं।

श्री राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने बताया हैं कि एक एम.बी.बी.एस. डाक्टर की 93 पोस्ट हरियाणा में खाली थी लेकिन अग वे भरी गई हैं। मै मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि 93 पोसटो में से कितनी पोस्टें रूरल हैंलि सैन्टर्ज की भरी गई हैं और कितनी खाली पड़ी हैं?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा मैम्बर साहब को बताना चाहती हूं कि आज के दिन तक सभी जगहों को भरने के लिए, चाहे वे गांव हों, चाहे भाहर, जितनी पोस्टे हमारे पास खाली थी, नियुक्ति–पत्र जारी कर दिये है ओर उनके ज्वाईन पोस्टे खाली बचती है और कितनी भरी गई हैं।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः स्पीकर साहब, मै मंत्री महोदया का बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के में कुछ गांव ऐसे है जिन

की आबादी 10 हजार से ज्यादा हैं। इनमें से किसी गांव में भी डिस्पैसरी नही हैं।क्या इन गावों मे डिस्पैंसरी खोलने की कोई प्रपोजल हैं?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः मैम्बर साहब, का गांव तो भिवानी मे आता हैं लैकिन फिर भी मैं उन्हे बताना चाहती हूं कि यू.एस.एड की एक स्कीम हैं जिसके तहत सैन्ट–पर–सैन्ट ग्रांट मिलती हैं। इस स्कीम के तहत भिवानी, महेन्द्रगढ़ और सिरसा मे 1985 तक के अस्रे के मध्य, पांच–पांच हजार की अबादी के स्भी गावों में एक–एक सब–सैन्टर खोला जाएगा जिसमें मल्टीपर्पज वर्कर महिलाये और मल्टीपर्पज वर्कर पुरूश होगें।

श्री बसंती देवीः क्या मंत्री महोदया बतायेगी कि मल्टीपर्पज वर्कर महिलाये क्या होती हैं्! क्या ये भी एम.बी.बी.एस. होगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः ये तो एम.बी.बी.एस. होती हैं, आप इनको नर्स भी कह लिजिए।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, गवर्नमैंट की पालिसी हैं कि हर एक ब्लाक को एक–एक प्राइमरी हैलि सैन्टर दिया जाए। कथुरा ब्लाक और गोहाना ब्लाक ऐसे है जिन में कोई प्राइमरी हैल्थ सैन्टर नही हैं। इन गावों के लोगों ने पैसे भी भर रखे है और जमीन भी दे रखी हैं। क्या मंत्री महोदया बतायेगी कि इन

दोनो ब्लाक्स मे प्राईमरी हैल्थ सैन्टर बनाने के लिए कब तक काम भाुरू हो जाएगा?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, हमारे कुछ ब्लाक्स ऐसे है जिन में प्राइमरी हैल्थ सैन्टर नही बने हैं। पिछले साल दो बनाये गये है और अगले साल दो को और टेक–अप किया जाएगा। हर साल इन में से दो–दो प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्ज को बनाते चले जाऐंगे। इकट्ठा इसलिए टेक–अप नही कर सकते क्योंकि इन पर काफी पैसा खर्च होता हैं। इसकी बिल्डिंग भी खुद ही बनानी पड़ती है और 60 हजार रूपये से कुछ नही बनता, तकरीबन 30 लाख रूपया खर्च होता हैं। इसलिए हर साल दो–दो को टेक–अप कर रहे हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, बहन जी ने एक अनुपूरक प्र न के उतर में फरमाया हैं कि ग्रेवाल साहब का एरिया भिवानी में है और भिवानी, महेन्द्रगढ और सिरसा इन तीनो जिलो का यु.एस.एड की स्कीम के अर्न्तगत सुविधायें दी जाएगी और यह सुविधा इन जिलों के हर गांव मे दी जा रही हैं । मै बहन जी से पूछना चाहता हूं कि बाकी 9 जिलों में यह सुविधा कब से दी जाएगी, क्या उनकी कोई योजना है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, यह नीति भारत सरकार निर्धारित करती है और उनकी इस नीति के मुताबिक दो हजार ईस्वी तक पांच हजार तक के गावों को यह सुविधा दी

जाऐगी। पहले इन तीन जिलो को ही टेक–अप किया जो रहा हैं। लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार इस कोि ा ा में है कि भारत सरकार की इस नीति को लागे करने से पहले ही पबाकी जिलो को टेक–अप करे, लेकिन इसके रास्तें में कुछ दिक्कतें हैं हमने ट्रनिंग भी देनी है और बिल्डिंग भी बनानी हैं। एम्पलाईज के लिए रिहाय ाी मकान भी चाहिए। इस तरह की दिक्कतें हमारे रास्ते में है लकिन फिर भी जो–जो सहूलियत, जितनी जल्दी हो सकेगी, सरकार देने की कोि ा ा में हैं।

मास्टर राम सिंहः स्पीकर साहब, लाडवा ब्लाक, गावं बबैन के अन्दर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर के लिए पंचायत की तरफ से जमीन अलौट हो चुकी हैं जिसके बारे में मुख्य मंत्री जी अनाऊसमैंट भी हो चुकी हैं, लेकिन अीाी तक प्राइमरी हैल्थ सैन्टर बनाने का काम भाुरू नही किया है। क्या मंत्री महोदया बतायेगी कि यह सैन्टर कब तक बनाया जाएगा। इसके अलावा रादौर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर के लिए सरकार ने एक्स–रे प्लांट मन्जूर कर दिया हैं, लेकिन अभी तक प्लांट चालू नही किया है। क्या मंत्री महोदया बताऐगी कि यह कब तक चालू हो जाएगा?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, वैसे तो प्राइमरी हैल्थ सैन्टर और एक्स–रे प्लांट का इस सवाल के साथ कोई ताल्लूक नही है, यह एक अलग सवाल है, लेकिन मैं बता देती हूं कि जहां तक रादौर में एक्स–रे प्लांट लगाने का ताल्लूक हैं, कुछ

महीने पहले इसकी सैक ान हो चुकी हैं और एक्स–रे प्लांट जितनी जल्दी हो सकेगा, दे दिया जाएगा।

चौधरी कुन्दन लालः स्पीकर साहब, सब डिविजन सफीदों के अन्दर 30 बिस्तरो का एक ही होस्पिटल हैं, लेकिन उसकी बिल्डिंग इतनी खराब हैं कि सारे के सारे मरीज सर्दी मे बाहर पड़े रहत हैं। वहां पर जो एक्स–रे प्लांट हैं, पता नही वह किस सदी का बना हुआ है जो ठीक से काम नही करता। वहा पर पूरा स्टाफ भी नही है। वहां पर लोगो की दुर्द ाा प ाुओं के समान हैं। क्या मंत्री महोदया वहा पर नया एक्स–रे प्लांट लगाने की कृपा करेगीं?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः स्पीकर साहब, मेरे नाटिस में ऐसी बात कभी नही आई, लेकिन अगर माननीय सदस्य ठीक कहते हैं तो इसकी इन्क्वायरी करवायेगे। अगर इसमे कोई कमी होगी तो नौर्म के मुताबिक जो हो सकेगा, करेगे।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने सिरसा जिले को स्वास्थ्य सुविधाऐ देने की बात कही है। सिरसा जिले का नाम यहा बार–बार लिया जाता हैं। क्या मंत्री महोदया बतायेगी कि सिरसा और सिरसा जैसे दूसरे जिलो के गावों को यह सुविधा कब तक दी जाएगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवीः इसके लिए अलग नोटिस दे, जवाब दे दिया जाएगा। क्योंकि सब–सैन्टरो की संख्या एक हजार

से ज्यादा हैं इसलिए अलग–अलग नही बताया हा सकता। अगर आनरेबल मैम्बर नोटिस देगें तो बता दिया जाएगा।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, ये सिरसा का नाम बार–बार ले रहे हैं लेकिन असल में ये गलत नाम ले रहे हैं। सिरसा के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। ये जोर–जोर से इसलिए कह रहे हैं ताकि सिरसा जिले का नाम कागजों में आ जाए, लेकिन वास्तव में सिरसा के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। 20–25 बैड्ज को होस्पिटल तो अलग बात हैं मेरी कांस्टिच्यूऐंसी मे तो एक बैड का होस्पिटल भी नही है। क्या मंत्री महोदया एलनाबाद हल्के के होस्पिटल बनान के बारे के सोचेंगे।

श्रीमती प्रसन्नी देवीः वैसे तो तकरीबन सभी प्राइमरी हैल्थ सैन्टर में बैडज हैं, लेकिन माननीय सदस्य अपनी कांस्टिच्यूऐंसी के बारे में घबराये नही। अगर वे बीमार होगे तो उनका जरूर इलाज कर देगें।

Mr. Speaker: Question Hour is now over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रख गए तारांकित प्र नो के लिखित उतर

Construction of Drains in Kiloi constituency

***269. Shri Hari Chand Hooda:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state the Number of drains sanctioned for construction togetherwith the number out of

those as have actually been constructed during the years 1981, 1982 and 1983 in Kiloi Constituency of Distt. Rohtak?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): अब तक नई ड्रन/लिंक ड्रेन, जिस में ड्रेनो की रिमॉडलिग भी भाामिल हैं, की 15 स्कीमें स्वीकृत की गई। इसमें से वर्श 1981 से पहले 9 स्कीमें वर्श 1981 में 2 स्कीमे ओरप वर्श 1982 में 2 स्कीमें कार्यन्वित की गई। वर्श 1983–84 में भोश 2 स्कीमों को टेक–अप किया जाना रहता हैं।

Construction Roads by the Marketing Committees in the State.

***247 Master Ram Singh:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the number of roads constructed or got constructed by the marketing committees in the State during the period from 1972-73 to 1982-83; and

(b) whether the above said roads are being repaired or got repaired regularly; if so the name of the repairing agency thereof and the amount of expenditure incurred on their repairs during the above said period.

कृशि मंत्री (चौधरी सुरेन्द्र सिंह):

(क) 611

(ख) जी हां जब मुरम्मत की आव यकता उत्पन्न होती हैं। सड़को की मुरम्मत हरियाणा राज्य कृशि विपणनन बोर्ड की

निर्माण भाखा तथा लोक निर्माण विभाग (भवन एव सड़के) के माध्यम से कराई जाती हैं। 1972–73 से 31.01.1983 तक की अवधि में सड़को की मुरम्मत पर 2,56,03,195.35 रूपये खर्च किये गये थे।

Drinking Water Tanks

***278. Shri Nar Singh:** Will the Minister of State for public Health be pleased to state whether any water tanks for the supply of drinking water have been constructed in the State during the period from 1978-79 to date; if so, constituency wise number thereof?

@ INTERIM REPLY

लाल सिह

9/15/83–पी.एच.(3)

राज्य मंत्री

जन–स्वास्थ्य विभाग हरियाणा

चण्डीगढ़

दिनांक 18 मार्च 1983

प्रिय

विधान सभा तारांकित प्र न 278 जो 21.03.1983 की सूची में श्री नर सिंह सदस्य हरियाणा विधान सभा के नाम दर्ज हैं

के संदर्भ में मुझे यह कहना है कि उक्त प्र न का उतर अभी तेयार नही हुआ हैं। इस प्र न के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही हैं जिसको अभी समय लगेगा। अतः आप से अनुरोध करूंगा कि इस प्र न का उतर देने के लिए 14 दिन और प्रदान किये जाएं।

आपका

हस्त/–

(लाल सिंह)

श्री तारा सिंह

अध्यक्ष,

हरियाणा विधान सभा चण्डीगढ़

Taking Samples of Medicines.

***281. Shri Man Phool Singh:** Will the Minister for Health be pleased state—

(a) the designations of officers who have been authorized to take samples of the medicines in the State;

(b) whether the Government is aware of the fact that some unauthorized Juniors of such officers as mentioned in

part (a) above also take the samples of the medicines, if so, the reasons therefore?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) उप–राजकीय औशधि नियंत्रक हरियाणा, सहायक राजकीय औशधि नियंत्रक तथा जिला औशधि निरिक्षक ही हरियाणा राज्य में दवाइयो के टैसट व वि लेशण हेतू नमूने भर सकते है।

(ख) कोई भी ऐसा व्यक्ति सरकार के ध्यान मे नही आया।

Tehbazari in the Grain Market of Gohana

***328. Shri Kitab Singh:** Will the Minister of Agriculture be pleased to state—

(a) whether it is fact that the Market Committee of Gohana passed a resolution on 13.11.80 that the platform of the said grain Market be leased out for "Tehbazari" ; and

(b) if so, whether the said platform is being leased out for Tehbazari and if not, teh reasons therefore?

कृशि मंत्री (चौधरी सुरेन्द्र सिंह):

(क) जी नही।

(ख) उपरोक्त (क) पर दिये गये उतर के दृश्टिगत प्र न ही नही उठता।

Maintenance of Buidings of Erstwhile Zila Parishads

***324. Master Shiv Parshad:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state—

(a) The agency through which the State Government is maintaining teh buildings of the e rstwhile Zila Parishads in the State; and

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to hand over the said buildings to the concerned Panchayat Samitis for the maintenance thereof?

विकास मंत्री (श्रीमती भाारदा रानी कवंर):

(क) लोक निमार्ण विभाग(भवन तथा सड़को)

(ख) नही।

हरिजन लड़कियों के कथित अपहरण/कानून तथा व्यवस्था की स्थिति सम्बन्धी मामला उठाना

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मुझे कुछ टेलीग्रामज मिले हैं, मै उन्हे हाउस मे पढ कर सुनाना चाहती हूं। एक टेलीग्राम श्री मनी राम बागड़ी एम.पी. की तरफ से आई हैं ओर इसमे लिखा हैंकि–

"Two minor Harijan Girls kidnapped from Barwala on Wednesday Night stop residents agitated law and order deteriorating stop no Police action stop either you resign or

dismiss Haryana Ministry Immediately stop-Mani Ram Bagri Member of Parliament"

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, जिस टेलीग्राम का बहिन जी जिक्र कर रही है उसके बारे मे बताने में हमे कोई गुरेज नही हैं। मै हाउस के सामने सारी स्थिती स्पश्ट कर देता हूं।(विध्न)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मै भी ला एन्ड आर्डर की सिचुए ान के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आज ला एन्ड आर्डर की बहुत बुरी हालत हैं। मेरी भी इस बारे में काल–अटैन्सन मौ ान थी, उसके बारे मे कोई जवाब नही आया। पानीपत के अन्दर ए.एस.आई. का मर्डर किया गया हैं। आज तक उन आदमियों को पकड़ा नही गया। इसी तरह से हिसार से दो लडकियों को उठाया गया उनके बारे में भी कुछ पता नही चला।

वक्तव्य–

मुख्य मंत्री द्वारा उपयुक्त मामले सम्बन्धी

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, पहले मे बहिन जी के पास जो टेलीग्राम आये हैं उनके विशध में अर्ज कर दूं। दो हरिजन लड़कियों की जहां भाादी हुई थी वे वहां पर कलेस के कारण जाना नही चाहती थी। वे घर से लड़कर चली गई। बरवाला हिसार जिले मे अच्छा कस्बा हैं। वे दोनों लड़किया वहा पानी के टैंक मे डूबी हुई पायी गई। (ाोर) अब पता नही

चला कि वह खुदकु ाी को केस हैं या दूसरा हैं लैकिन हमने खुदक ाी का केज दर्ज नही किया हैं बाकायदा 302 का मुकदमा दर्ज हुआ ह।। तफती ा जारी हैं। जो आदमी भी कसूरवार मिलेगा उसे माफ नही किया जाऐगा। जहां तक ए.एस.आई. के मर्डरप का सम्बन्ध हैं एक ए.एस.आई. और एक हैड कास्टेबल सड़क पर खड़ें हुए थे। उन्होने इ ाारा करके एक कार को रूकवा लिया ताकि आगे से बस में चला सके। इ ाारे पर कार को रोक लिया और वे दोनो उस कार में बैठ गये। जब कार चल रही थी तो ए.एस.आई. ने कार में बैठे हुए आदमी को कहा कि तू जगदी ा हैं। जगदी ा काफी दिनो से मफरूर था। ए.एस.आई. ने जगदी ा को पकड़ने की कोि ा ा की। जब उसकी जफी भरने की कोि ा ा की गई तो गाड़ी उल्ट गई। ए.एस.आई. नीचे गिर गया। ए.एस.आई. को जगदी ा ने गोली मार दी और उसका पिस्तौल भी ले गया। गाड़ी को छोड़ कर वह एक मोटर साइकिल पर सवार हो कर भाग गया। बाकायदा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया हैं। जो ए. एस.आई. मारा गया है उसे इस हजार रूपये ईनाम दिया गया हैं। सरकार की तरफ से कोई कोताही नही की जा रही है। पुलिस उसकी तला ा में है।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, रोहतक के अन्दर एक 23–23 साल के लड़के को उठा ले गये लेकिन आज तक उसका पता नही चला। लडका टैक्सी मे बैठ कर गया है न टैक्सी का

पता लगा है ओर न ही लड़के का पता चला हैं। ऐसी हालत है ला एण्ड आर्डर की।

दूसरे उस ए.एस.आई. को दस हजार रूपया बहुत कम ईनाम दिया गया है कम से कम 50 हजार रूपया दिया जाना चाहिए था।

श्री किताब सिंहः स्पीकर साहब, 13 तारीख को लाखन माजरे के समुंद्र सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया। उसको पुलिस ने बहुत बुरी तरह से पीटा। 17 तारीख को उसे छोड़ा गया। 18 तारीख को उसका मेडिकल हुआ। उसके भारीर पर 6–7 नि ाान हैं।(ाोर)

विभिन्न विशयों का उठाया जाना––

(i) फतेहाबाद मे हरिजनों को तंग करने सम्बन्धी

श्री मनफूल सिंहः स्पीकर साहब, मैने एक काल–अटैन ान मौ ान दी थी लेकिन आपने उसे डिस–अलाउ कर दिया हैं। यह तो बड़ी गलत बात हुई हैं। भागीरथ नाम का व्यक्ति फतेहाबाद का रहने वाला है। पुलिस की मदद से वह हरिजनो को तंग कर रहा था। 19 हरिजनों का चालान किया गया। इसने हरिजनों को रिवाल्वर से मारनेकी भी धमकी दी हैं। वहां बाल्मीकि हरिजनो का खतरा हैं इसलिए इसे आप कंसिडरप करें।

श्री अध्यक्षः आप बैठिए, मैने इसे डिस–अलाऊ कर दिया है।

श्री लछमन सिंह कम्बोजः स्पीकर साहब, इन्द्री कस्बे के अन्दर मुसलमानो की मस्जिद हैं। उस मस्जिद को गिराया जा रहा हैं। यह एक धार्मिक स्थान हैं और उस इलाके के मुसलमान बड़े परे ाान हैं एक ए.एस.आई. जिस को नाम मै बता सकता हूं बदमा ा औरत से मिल कर ऐसा कर रहा है। वहां के लोगों ने मुख्य मंत्री जी, को तार भी दिया हैं। उन्होने मेरे पास भी एप्लीके ान दी हैं। पहले यह मस्जिद किसी कमेटी के पास थी, अब भी उसी के पास रहनी चाहिए लेकिन उन लोगो के हाथ मे ं नही जानी चाहिए जो इसपर नाजायज तौर पर कब्जा करना चाहते हैं। (ाोर)

श्री मनफूल सिंहः स्पीकर साहब, क्या मै जान सकता हू कि आप लोग थोड़ा सा प्रोसीजर की तरफ भी ध्यान दिया करे।(विध्न) आप अपने मैबरान को समझाये। मैने एक मैम्बर की काल–अैन ान मो ान डिस–अलाऊ कर दी हें लेकिन फिर भी वे बोले जा रहे है कि क्यों डिस–अलाऊ की है। न वे पढ कर आतें और न ही समझाने पर समझने की कोि ा ा करते हैं।

श्री मंगल सैनः इनका कहने का मतलब यह था कि इस बारे मे किसी पहलू पर विचार करना रह गया हैं इसलिए ये आपे रिक्वैस्अ कर रहे थे।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, उनकी ऐसी नीयत नही थी।

श्री अध्यक्ष: क्या मै आपसे पूछूंगा कि उनकी क्या नीयत थी?

(ii) पुलिस अफसरो को बहादुरी के लिए ईनाम देने सम्बन्धी

श्रीमती बसन्ती देवी: स्पीकर साहब, मै पुलिस की बहादुरी के बारे मे अर्ज करना चाहती हूं। राज सिंह एस.आई. और रणबीर सिंह डी.एस.पी. चार डाकुओ को पकड़ा हैं। इन डाकुओ ने 10 डाके डाले थ। क्या इन पुलिस के बहादुर अफसरो को भी ईनाम दिया जाऐगा?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अगर अच्छा काम किया हैं तो उनहे भी जरूर ईनाम दिया जायेगा।

(iii) दवाइयों पर सेल्ज टैक्स ऐबौलि ा करने सम्बन्धी

Smt. Chandravati: Sir, the second telegram reads as under

"Please Abolish sales tax on Medicine Karnal Chemists Association"

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, सारे साल में 17–18 दिन का सै ान होता हैं। अगर इन दिनों में भी आपका ध्यान इन बातों की और न दिलाये तो कब दिलायें? करनाल से मेरे पास भी

तार आया हैं। उसमे वहां के लोगो ने लिखा है कि मैडिसन्ज पर भी सेल्ज टैक्स बढा दिया है जो कि नही बढना चाहिए। हम इलैक्टिड रिप्रैजैन्टेटिव्ज हैं। हमारे द्वारा ही वे सरकार के पास अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हम आपके द्वारा ऐसा कर सकते है।

श्री अध्यक्षः सेल्ज टैक्स का बिल आ रहा है। उस टाईम आप अपनी बात कह लेना।

(iii) डी. ए. की तीन किस्तो सम्बनधी

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मुझे एक और टेलीग्राम कर्मचारियो को डी.ए. की किस्तों सम्बन्ध में श्री हवा सिंह से आई वह इस प्रकार हैं:–

"Please raise Assembly Question three D.A. Instalments."

Mr. Speaker: Please take you seat. You will agree that the subject matter of every telegram that you receive, cannot be raised like this withour proper notice.

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव–

सिविल हस्पताल महेन्द्रगढ संबंधी

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे श्री राम बिलास भार्मा की और से महेन्द्रगढ सिंविल हस्पताल के बारे में एक

काल–अटैन ान मौ ान का नोटिस मिला है। मैं इसे ऐडिमिट करता हूं। श्री राम बिलास भार्मा अपना नोटिस पढ दे और मन्त्री महोदया अपनी स्टेटमैंट दे दें।

श्री राम विलास भार्माः स्पीकर साहब, इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आकृश्ट करना चाहता हूं कि महैन्द्रगढ़ का सिविल हस्पताल पिछले काफी लम्बे समय से ठीक नही चल रहा है। बीमारों का वहां कोई उपचार नही हो रहा है तथा उनके साथ बदसूलकी होती है। लोगों में इस व्यवहार को लेकर आक्रो ा हैं। एक कैम्स्टि हस्पताल के डाक्टर की मिली भगत से नकली दवाए बेच रहा हैं। इसकी ि ाकायत की गई थी। 08.04.1981 की विभागीय जांच में उक्त कैमिस्ट औशध–पत्र (पर्सक्रिप् ान) बदलने का दोशी पाया गया था परन्तु अब वह दोशी डाक्टर एव कैमिस्ट के खिलाफ कोई कार्यवाही नही हुई हैं। महैन्द्रगढ में यदि यह सिलसिला यथावत जारी रहा तो कभी भी हुच दुर्घटनाए हो सकती हैं। सारी जिम्मेवारी सरकार पर होगी। 24.12.1982 को श्री वी.एन.माथुर उप निदे ाक भी जांच के लिए महेन्द्रगढ गए थे। महेन्द्रगढ के वकील समुदाय संगठन (बार एसोि ाएन) का सर्वसम्मत प्रस्ताव भी इसी सम्बन्ध मे था। पूरा वकील समुदाय संगठन (बार एसोि ाएन) यानी उस दिन उपस्थित 45 वकील भाारिरिक रूप से जांच में ब्यान देने आए थें। नगर एवम् इलाके के सैकडो़ लोगों ने हस्पताल में व्याताल भ्रश्टाचार, बदसलूकी और बदइतंजामी के कारण नही हुई।

हस्पताल की बदइतंजामी, नकली दवा का डाक्टर द्वारा प्रचार और बीमारों के साथ बदसलूकी से हाहाकार मचा हुआ हैं। सरकार के प्रति इलाके के लोगो में भय ओर अवि वास फैल रहा है। डाक्टर के सम्बन्ध में जिन लोगों ने स्पश्ट ब्यान दिए उनको डाक्टर द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। उन्हे नमूना(सैम्पल) भरने की धमकी दी जा रही है। इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से गुजारि ा है कि वह अपनी स्थिति स्पश्ट करे और डाक्टर और कैमिस्ट के खिलाफ कार्यवाही करे ताकि आम आदमी को राहत मिल सके।

स्वास्थ्य मंत्री(श्रीमती प्रसन्नी देवी): स्पीकर साहब, यह ठीक नही है कि सामान्य हस्पताल, महेन्द्रगढ़ सुचारू रूप से नही चल रहा है। यह भी ठीक नही हैं कि वहां मरीजों का इलाज अच्छी प्रकार से नही किया जा रहा है तथा मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है।

2. पिछले विधान सभा अधिवे ान के दौरान दिनांक 18.09.1982 को श्री राम बिलास, एम.एम.ए. ने बताया था कि ''दैनिक ट्रिब्यून'' 01.08.1982 तथा 09.08.1982 और ''दि ट्रिब्यून'' दिनांक 21.08.1982 मे सामान्य अस्पताल, महेन्द्रगढ में कार्यरत महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमिताताओं बारे खबरे छपी थी। उन्होने महिला चिकित्सा अधिकारी के विरूध कार्यवाही की मांग की थी। इसके उपरान्त उन्होने दिनांक 30.09. 1982 को निदे ाक, स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा को कुछ कागजात, जिसमें महेन्द्रेगढ अस्पताल में कार्य कर रहे चिकित्सा अधिकारियों

के विरूद्व कुद आरोम लगाए गए थें, दिये इन कागजात में कुछ समाचार पत्रो की कटिंग भी भाामिल थी।

3. इन सभी आरोपों के बारे में तथ्यो को जानने हेतू डा. वी. एन. माथुर संयूक्त निदे ाक, स्वास्थय सेवाए ने जांच की। जांच के समय महेन्द्रगढ बारे ऐसेसिऐ ान के 34 वकील (ना कि 45) जांच अधिकारी से मिले और उन्होने इन चिकित्सा अधिकारियों के विरूद्व आरोपो का समर्थन किया। दूसरी और इनके विपरीत सैकड़ो लोगों ने चिकित्सा अधिकारियों के कार्य की सहारना की और जांच अधिकारी से अनुरोध किया कि इन चिकित्सा अधिकारियों को महेन्द्रगढ से न बदला जाए क्योंकि वे अच्छे कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वहां के आसपास के क्षेत्र की पंचायतों के 34 सरपंचों ने भी सरकार से लिखित रूप से अनुरोध किया है कि इन चिकित्सा अधिकारियों को महेन्द्रगढ से उनके अच्छे काम के कारण न बदला जाए। संयुक्त निदे ाक, स्वास्थय सेवाए द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन हैं और यदि कोई चिकित्सा अधिकारी दोशी पाया गय तो न केवल उसे महेन्द्रगढ से बदल दिया जाएगा अपितु ऐसे चिकित्सा अधिकारी के विरूद्व कड़ी अनु ाासनिक कार्यवाही की जाएगी।

4. ऐसे किसी व्यक्ति जिसने जांच अधिकारी के सन्मुख गवाही दी थी, को तंग नही किया जा रहा हैं। दवाईयों के नमूने लेने के मामले मे किसी भी कैमिस्ट से भेदभाव नही बरता जा रहा हैं। यदि कोई भी कैमिस्ट नक्ली, घटिया तथा मिलावटी दवाईयां

रखता हुआ, बेचता हुआ तथा बनाता हुआ पाया जाता हैं तो उसे माफ नही किया जाएगा।

5. सरकार अपने इस कर्तव्य से भली भान्ति जागरूक हैं कि राज्य में सभी चिकित्सा संस्थाए सुचारू रूप से कार्य करें तथा चिकित्सा अधिकारी जनता को न केवल पर्याप्त तथा अच्छी चिकित्सा उपल्बध करे अपितु यह सुविधाए श्रद्वा तथा सहानुभूति प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करें।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, वैसे तो जो कुद मंत्री महोदया ने ब्यान दिया हैं उस पर अपनी टिप्पणी नही कर सकता परन्तु इन्होने अपने जवाब में इस बात को स्वच स्वीकार किया हैं कि वहां पर बार–एसोसिए ान के 34 लोग जांच के दौरान जांच अधिकारी से मिले थें और सब ने एक यानि सर्वसम्मत ब्यान दिया। स्पीकर साहब, 18.09.1982 को मैने इस सदन का ध्यान वहां पर हो रही अनियमितताओं की ओर तो डिपार्टमैंट ने प्रेस्क्रीप् ान चेन्ज करने के मामले में डाक्टर और कैमिस्ट दोना को दोशी पाया था। उन लोगों का कसूर केवल यह हैं कि उनका नुमायन्दा मैं हू। दोशी पाये जाने के बावजूद भी उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई हैं। मै मंत्री महोदया से यह कहना चाहता हूं कि वे मुझे बे ाक इसका क्रेडिट न दें और वहां पर एक बारे स्वयं महेन्द्रगढ अस्पताल मैं विजिट करके लोगों से पूछ ले। इसको राजनैतिक मसला न बनायें और वहां के लोगों को कुछ राहत पहुंचान की कृपा करें।

श्रीमती प्रसन्नी: स्पीकर साहब, राजनैतिक मसला बनाने की कोई बात ही नही हैं। इमने इस मामले की इन्कवायरी ज्वायंट डायरैक्टर से करवाई है। मैम्बर साहब ने वैसे ही इस मसले को पोलीटीकल बना दिया है, वैसे कोई बात थी नही। जहां पर उन अधिकारियों के खिलाफ कुछ आरोप इन्होने लगाये थे वहां पर यह भी आरोप बीच में आया कि क्योकि इन्होने चुनाव में इनके खिलाफ प्रचार किया था, इसलिये उन्हे तंग किया जा रहा हैं। इन सब बातों की इन्कवायरी की गई। वहां पर एक भी ऐसी चीज नही पाई गई जो इन्होने अपने मो ान में कही कि वहां पर काफी कुछ खराबी हैं। मैने अपने तौर पर भी पता किया और मुझे यह पता चला हैं कि वहा पर कोई ऐसी बात नही हैं जोकि सीरीयस हो और जिससे वहां के लोगों को नुक्सान हो रहा हों।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, जो बात इन्होने चुनाव की कह दी, वह न तो मैने पहले कभी कही हैं और न ही अब कहता हूं। मै मंत्री महोदया से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन्होने इस बात को स्वयं स्वीकार किया हं कि वहां पर इन्कवायरी में वहा के वकील समुदाय ने एक बात को सर्वसम्मति से का हैं। इसके अलावा 08.04.1981 को जब विभाग पने इन्कवायरी की थी, उस समय तो मैं विधायक भी नही था। जब उस समय प्रैस्क्रीप् ान चेन्ज करने के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार मिलता हैं तो उसके खिलाफ तो कार्यवाही होनी चाहिए थी। क्या मंत्री महोदया इस बात का यकीन दिलायेगी कि जिन आदमियों

को उस जांच के दौरान दोशी पाया गया था, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी?

श्रीमती प्रसन्नी: जैसे मैने बताया, ऐसी कोई चीज जांच मे नही पायी गई। फिर भी इस मामले को बड़ी गहराई से अध्धयन किया जा रहा है। अगर किसी का कोई कसूर मिलेगा तो उस को केवल बदलने से कोइ बात नही बनती, उसके विरूद्व कड़ी अनु ाासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाऐगी। (व्यवधान व भाोर)

बिल्ज (इन्ट्रोड्यूस्ड–सदन की अनुमति से)

(i) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एंड वैलीडै ान) बिल, 1983

श्री अध्यक्ष: अब एक मिनिस्टर साहब दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एंड वैलीडै ान) बिल, 1983 को इन्ट्रोडयूस करने के लिए हाउस से परमि ान लेगें।

Irrgation & Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Sujewala): Speaker, Sir I beg to move—

That leave be granted to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill 1983.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That leave be granted to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill 1983.

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, आज मंत्री महोदय दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एंड वैलीडै ान) बिल को सदन में प्रस्तुत करने के कलए सदन से स्वीकृति लेना चाहते हैं। मै यह चाहता हूं कि सदन को उनको यह स्वीकृति नही देनी चाहिए। इसलिए नही देनी चाहिए क्योकि पहले ही हमारे प्रदे ा का नागरिक करों के बोझ से दबा हुआ हैं। कैन्द्रिय सरकार के कर हैं, प्रदे ा के कर हैं और इसके अलावा एक और उप–कर लगाया जा रहा हें। एक–एक चीज पर तीन नामों के कर लगाये गए हैं। अखिरकार उपभोक्ता तो वही हैं। स्पीकर साहब, अनाज तो एक हें लेकिन उसके ऊपर एक मार्कीट फीस हैं, दूसरे सेल्ज टैक्स हैं तीसरा इनहोने सेस लगा दिया हैं। इस सैस को लगाने के लिए इन्होने बहाना क्या बनाया है कि रूरल डिवैलपमैंट के लिए यह फण्ड बनाया जा रहा हे। जो करोड़ो अरबों रूपया स्टेट बजट का हैं, वह किस काम आयगां? क्या 8 करोड़ रूपए से ही रूरल विलैपमैंट होगी? ऐसा करना तो तफरकात और भेदभाव पेदा करने की बात हैं हम तो यह कहते हैं कि आप 70 प्रति ात रूपया बजट को गांवो की डिवैल्पमैंट पर खर्च कीजिए। 8 करोड़ रूपय ही क्यों खर्च करो? जो गावों के रहने वाले लोग है, उनको भी पूरी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। स्पीकर साहब, अगर यह पेसा ही चाहते है तो अपने खच्र कम करे कान्कास्ट कम्पनी की बात पर चोधरी भजन लोल ने स्वयं स्वीकार किया हैं। यह इन्होने ठीक की कहा हैं कि जग से यह कम्पनी बनी हैं, जब से ही घाटे में जा रही हैं। मै भी इस डिपार्टमैंट के

ऊपर सवा दो साल तक रहा हूं। इस कम्पनी की तो बुनियाद ही बे–मानी पर थी क्योंकि उस समय भी कांग्रेस का राज था जब यह बनाइ गई थी। जब मैने अपने वक्त में इसको डिस्पोज आफ करने की बात कही तो सरकारी नौकर ाही ने ऐसा नही करने दिया। स्पीकर साहब, आज प्रदे ा में जितनी कार्पोरे ानज हैं चाहे वह दूध बेचने वाली कार्पोरे ान के सभी कार्पोरे ान घाटे में जा रही हैं लेकिन फिरप भी यह सरकार इनको सीने के साथ लगाए बैठी हैं क्योंकि पोलिटिकल कप्पल ान हैं। कोआप्रोटिव सोसायटीज की तो बात ही जाने दीजिएं अध्यक्ष महोदय, हमारे जो मंत्री महोदय, बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उन्हे दो अढाई साल तक अपोजी ान में बैठने का मौका नही मिला हैं। उस वक्त वे कहा करते थे कि सरकार को ऐसे मैयर्ज अडोप्ट करने चाहिए जिनसे जनता पर बोझ न पड़े लेकिन अब जब वे मिनिस्टर बन गए हैं तो इस प्राकर से बिल इन्ट्रोडयूस कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन की कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। इसलिए मेरा उनसे निवेदन हैं कि वे अपनी आत्मा की आवाज को सुने ओर इस बिल को हाउस में न लाए।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, डा. मंगल सैन ने कहा है कि इस बिल को इन्ट्रोड्यूस न किया जाए। इनको यह एतराज हैं कि सात परसैन्ट से जो आठ परसैन्ट की इन्क्रीज है और साथ ही आढती पर जो एक परसैन्ट का सैस लगाया है यह ठीक नही है। यह सैस

लगाकर सरकार गांव और भाहर के लोगों मे भेदभाव कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में सदन में पहले भी बताया जा चुका हैं और मुख्य मंत्री महोदय ने विस्तार से इसका जवाब दे दिया हैं कि इस सैस से आठ करोड़ रूपया या इससे भी ज्यादा रूपया इक्ट्ठा हो सकता हैं । देहात में छोटे–छोटे काम हैं जिन के लिए बजट में कोई प्रावधान नही हैं वे काम इस इस रूपए से किए जाऐगें। ऐसे कामो को करने के लिए रूपए की सख्त जरूरत हैं। अध्यक्ष महोदय, गांव ओर भाहर में किसी तरह को भेदभाव करने की सरकार की कोई मं ाा नही हैं। स्पीकर साहब, दूसरी बात यह हें कि दो चार परसैन्ट खर्चा की हरियाणा के लोगों पर पडेगा वरना 98 परसैन्ट बौझ दूसरे प्रान्तो पर पड़ेगा क्योंकि एफ.सी. आई. हरियाणा में जो वीट और राइस खरीदेगी वह दूसरे प्रान्तो को ि ाफट हो जाएगा ओर एफ.सी.आई. को यह सैस देना पड़ेगां इसलिए मै कहना चाहता हूं कि हरियाणा के लोगों पर किसी प्रकार का बोझ नही पड़ेगां न भाहर के लोगो पर पड़ेगा और न ही गांव के लोगो पर पड़ेगा। जनरल सेल्ज टैक्स की अमैण्डमैंट के बारे में फाईनैंस जो आम लोगो के इस्तेमाल की हैं, रोज के काम में आने वाली हैं नही बढाई जाएगी बल्कि जो लग्जरी आइटम्ज हैं, आम लोगों के इस्तेमाल की चीजे नही हैं उन पर इंक्रीज होगी इसलिए एक परसैंट इंक्रीज को अनजस्टिफाईड नही कहा जा सकता हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां ता कार्पोरे ान की वर्किंगे का सवाल हैं, फाईनैंस मिनिस्टर साहब ने कहा हैं कि सरकार की पूरी कोि ा ा है कि सारी कार्पोरे ान ठीक काम करे ं और उनमें घाटा न हो। इन सारी बातों को देखते हुए मै सदन की इजाजत चाहूंगा कि इस बिल को इन्ट्रोडफयूस करने की इजाजत दी जाए।

Mr. Speaker: Question is –

That leave be granted to introduce the Haryana Gerneral Tax (Amendment and Validation) Bill, 1983.

The Motion was carried.

Irrigation and Power Minister(Chaudhri Shamsher Singh Surjewala): Speaker, Sir I introduce the bill.

(ii) दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एंड डिवैल्पमैंट) अमैंडमैंट बिल, 1983

Minister of State for Lacal Government (Shri A.C. Chaudhry): Mr. speaker, sir I beg to move—

That leave be granted to introduce the Faridabad Complex(Regulkation and Development) Amendment Bill, 1983.

Mr. Speaker: Motiod Moved—

That leave be granted to introduce the Faridabad Complex(Regulkation and Development) Amendment Bill, 1983.

श्री मंगल सैन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एण्ड डिवैलपमैंट) अमैण्डमैंट बिल सदन में इन्ट्रोड्यूस करेन के लिए परमि ान चाही हैं। स्पीकर साहब, हरियाणा और पंजाब के पुनर्गठन के बाद फरीदाबाद का महत्व बहुत बढ गया हैं। वहा पर दिल्ली के उधोगपतियों ने काफी उधोग लगाए हे। दे ा भर के मजदूर अपनी रोटी कमाने के लिए वहा पर आए हुए हैं। वहां पर ज्यादातर मध्यम श्रेणी के लोग और लोयर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। किसानो की धरती से जो प्रोडक ान होती हैं वह वहां के लोगो को फीड करती हें। पहले तो वहां पर म्युनिसिपल कमेटी थी। फरीदाबाद टाउनि ाप तो केन्द्रीय सरकार ने बनाया था लेकिन इन्होने वहा पर एक कम्पलैक्स बनाया है ओर यह प्रवाधान कर दिया है कि दस साल तक चुनाव नही होगे। इस साल के बाद उसको ग्यारह साल कर दिया ओर अग ये बारह साल करने की इजाजत मांग रह है। स्पीकर साहब, डैमाक्रेसी में इस सरकार द्वारा लोगो को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा हैं। यह सरकार टैक्स तो वहां से ले रही है। लेकिन चुनाव नही कराना चाहती। डैमोक्रेसी का जो ऐसैन्स हैं जो उनकी जान हैं वह लोगों की कन्सैन्ट के साथ गवर्न होनी चाहिए। सारे अफेयर्ज को डील करने का लोगों को अधिकार होना चाहिए। लोगो से पूछना चाहिए। सारे अफेयर्ज को डील करने का लोगों को अधिकार होना चाहिए। लोगों से पूछना चाहिए कि तुम्हार नुमइन्दा कौन हैं? स्पीकर साहब, वहां का एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो एक बहुत बड़े आदमी

का दामाद हैं। वहा के लोग और विधायक दोनो ही ब्यूराक्रेसी से परे ाान हैं। मेरा कहना यह है कि वहा पर लोगों को जो उनका मूल अधिकार हैं वह मिलना चाहिए ओर अपने अफेयर्ज को कन्ट्रोल करने का अधिकार लोगों के नुमाइंदो को होना चाहिए। फरीदाबाद की जनता को चुनाव का मौका मिलना चाहिए। मैं मिनिस्टर महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर आप चुनाव कराने का बिल लाते हैं तो वहां के लोग आपको फूल मालाऔ से लाद देते और आपकी तारीफ करते लेकिन आपने ऐसा नही किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह बिल सदन में न लाया जाए और मै इसका विरोध करता हू।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, ये जो फरीदाबाद कम्पलैक्स (विनियमन तथा विकास) सं ाोधन विधेयक, 1983 को यहां पर इन्ट्रोड्यूस करने की इजाजत मांग रहे हैं। यह ठीक नही हैं। मेरे विचार से तो इस बिल को यहा पर लाने की इन्हे इतनी जल्दी नही करनी चाहिए।(ाोर एव व्यवधान)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री(चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर हैं कि रूरज के अनुसार इस स्टेज पर इस बिल पर डिसक ान नही हो सकती। यह गल्त रिवायत हैं।

श्री अध्यक्ष: यह आवजैक ान रेज कर सकते हैं।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मेरी समझ मे नही आता कि ये ट्रेजरी बेन्चिज वाले इस बिल को इतनी जल्दी यहां पर इन्ट्रोड्यूस क्यों करना चाहते है, यह एक गल्त रिवायत है। इसमे 17 पंचायतें इंवालवड हैं। गलत तरीके से किसानों की जमीनें एक्वायार कर रहे हैं। इसलिए हमें इस बिल की इन्ट्रोक ान पर बिल्कुल एतराज हैं। इतनी गलत बात ये लोग करने जा रहे है और फिर कहते हैं कि हमें यहां पर बोलने का इस स्टेज पर कोई हक नही हैं। स्पीकर साहब, वहां के गांव के गावं उजाड़ रहे है। झांक सेंजली एक गांव हैं, वहा की जमीन बड़ी ही उपजाऊ हैं। वहा पर हद से ज्यादा गेंहू और सरसों की पैदावार होती हैं और उसी जमीन को उजाड़ की ये वहां पर क्लोनीज बनाने के लए जमीन एक्वायर कर रहे है। स्पीकर साहब, यह बिल एक एन्टीपीपल बिल हैं और इससे किसी गरीब आदमी का या किसान का कोई भला नही होने वाल हैं। आप को पता है है कि फरीदाबाद एक गन्दगी का घर हैं वहा पर मच्छर ही मच्छर हैं। जिससे बीमारियां फैल सकती हैं। इस तरफ सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए लेकिन यह सरकार उपजाऊ जमीनो को ना ा करने में लगी हुई है। यह बिल केवल कुछ चन्द लोगो की भलाई के लिए ही यहां पर लाया गया हैं। इसलिए मै आपकी मारफत सरकार से यह कहूंगी कि इस वक्त यह बिल यहां पर लाना गरीब किसानों के साथ घोर अन्याय करना हैं। यह गलत रिवायत डालना हैं। इस बिल को वापिस लिया जाना चाहिए। स्पीकर साहब, असल बात तो यह हैं कि ये लोग किसानों की उपजाऊ जमीनों को हड़पना

चाहते हैं इसी लिए बिल ला रहे हैं। मैं इसका सख्त विरोध करती हूं और इन ट्रेजरी बैंचिज पर बैठे अपने भाइयों को आपके द्वारा फिर कहती हूं कि यह एन्टी पीपल बिल हैं, इससे लोगों का भला नही होने वाला हैं, इसलिए इस बिल को वापिस ले लिया जाए।

स्थानिय भाासन राज्य मंत्री(श्री ए.सी. चौधरी): स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से डा0 मंगल सेन जी की बात जो इन्होने इलैक ान के बारे में कही, का जवाब देना चाहता हूं। (ाोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, आप इलैक ान की बात बीच में न लाए। आप यह बातए कि इस बिल को लाने की क्या आव यकता हैं।

श्री ए.सी.चौधरीः आज स्पीकर साहब, यह बिल इस लिए यहां पर इंट्रोडयूस किया गया है क्योंकि इसकी टर्म एक्सपायर हो रही थी। इस की टर्म एक साल और बढाने के लिए यहा पर लाया गया हैं। जब तक हम बार्डबन्दी नही करेगें जब तक इलैक ान नही करवाये जा सकते। अगर इसका इम्पलीमैंट नही करेगें ता इसके स्ट्रक्चर की वैल्यू क्या रहेगी? जमीन एक्वायर जरूर हुई है लेकिन मेरे विचार में अगर आप लोगों से पूछें, पंचायत वालो से पूछे तो वे सभी इन बातो को कंडैम करेगें। अतः इस बिल में चूंकि आपति वाली कोई कात नही हैै, इसलिए स्पीकर साहब, इसे इंट्रौडयूस करने की आज्ञा दी जाए।

Mr. Speaker: Questionis –

That leave be granted to intorduce the Punjab Ayurvedic and Unini Practitionsers (Haryana Amendment) bill 1983.

The motion was carried.

Health Minster(Shrimati Parsanni Devi): Sir, I Introduce the bill.

(iv) दि हरियाणा फौरेस्ट डिवैल्पमैंट बिल, 1983

Revenue Minister(Chaudhri Phool Chand): Sir, I beg to Move—

That leave be granted to intoduce the Haryana Forest Development Bill, 1983.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That leave be granted to intoduce the Haryana Forest Development Bill, 1983.

श्री वीरेन्द्र सिंह(नारनोंद): स्पीकर साहब, जब से यह फौरेस्ट डिवेलपमैंट बोर्ड का आर्डीनैन्स हरियाणा के विधायकों के सामने और आम जनता के सामने आया है, तब से आम लोगों में इसकी खासी आलोचना हुई हैं। गवर्नर अड्रैस पर और बजट स्पीच पर डिसक ान के दौरान भी इस बारे में काफी आलेाचना हुई हैं। स्पीकर साहब, कनकरैन्ट और तीसरी स्टेट लिस्ट हैं। पहले यह मामला यूनियन लिस्ट में आता था। लेकिन 1976 मे जब 42वी

अमैन्डमैन्ट कांस्टिच्यूए ान मे हुई, उसके बाद यह मामला बना हुआ है और फोरैस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड बनाना उसके अनुकूल नही है तथा इस सम्बन्ध में मामला हाई कोर्ट में चैलैन्ज हुआ हैं। इस बारे में अखबारो में भी काफी चैलैन्ज हुआ हैं। इस बारे में अखबारो में भी काफी खबरे आती रही हैं। उस दिन श्री फूल चन्द मुलाना जी ने इब प्र नो का उतर दिया ये कुछ पत्रों को और उनको अपने पास इस तरह छिपा रहे थे जैसे कि उनके पास ये लैटर बड़े ही सुरक्षित हों। मै उनको यह बाताना चाहता हूं कि वे सभी पत्र मेरे पास मौजूद हैं। अगर वे कहे तो मैं उनको पढकर भी सुना सकता हूं कि वे कौन कौन से लैटर हैं और उनका क्या मजबून हैं। पता नही मंत्री जी उस दिन क्यों उनकों छुपाये हुए थे। अगर आप चाहे तो मै उस लैटर का नम्बर, डैट और सब्जैक्ट मैटर बता सकता हूं। यह सब जो फौरेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड बनाने जा रहे हैं, यह पहले के फारैस्ट एक्ट की कन्ट्राडिक ान में है इसलिए ऐसा कदम मत उठाऔ। उन्होने यह भी कहा कि आप जो स्टेटमैंट दे रहे हैं उनके हिसाब से तो जो यूनियन गवर्नमैंट रिटन स्टेटमैंट फाईल करना चाहती हैं। वह क्नट्राडिक्ट हो जाएगी। गवर्नमैंट आफ इन्डिया ने इनको एक तरह से वार्न किया हे। कि यह बिल्कूल गलत बात हैं। इसका कोई हिसाब नही, सारे असैटस और सारी लाईबिलिटीज बोर्ड को दे दी। वह बोर्ड ट्रेड भी करेगा। इस तरह से उसका बहुत वाईड स्कोप बना दिया गया है। चौधरी फूल चन्द जी एम.ए.एल.एल.बी. हैं बहुत समझदार और बढिया आदमी हैं। ये बहुत एफीि ाएंटली काम कर रहे थे।

मुख्यमंत्री जी और वित मंत्री जी ने खुद ब्यान दिया हैं कि सभी बोर्ड और कार्पोरे ान घाटे मे जा रहे हैं लेकिन फिरप भी मंत्री जी अपनी पावर क्या घटा रहे हैं और क्यो न्यूटरपेलाइज हो रहे हैं? स्पीकर साहब, इस बोर्ड को बनाने मा औबजैक्ट यह बताया गया है–

"..... for the constitution fo an alternative and effective agency for the implemenation of the massive programme."

स्पीकर साहब, हरियाणा प्रान्त मे जब सारे बोर्डज और कार्पोरे ानज टोटल फेलयार हैं तो यह बौर्ड सारे हरियाणा प्रान्त की काया कल्प केसे बदल देगा? मै कहता हूं कि इससे मंत्री जी न्यूटरेलाठज होकर रह जाएगें। Why is he intersted in his suicide only God Knows. मै तो मुख्य मंत्री और ट्रेजरी बैंचिज के मैम्बरो से यही कहना चाहता हूं कि इस पर फिर गौर कर लें। आप जिसे अकामोडेट करना चाहते हैं, उसको ओर कही भी कर सकते हैं। इनके बहुत लम्बे हाथ हैं। परन्तु इस प्रकार से तो जो आपको 35–36 करोड़ रूपया मिलने जा रहा हैं वह बर्बाद न हो जाए। यहां पर जो भी बेदार मैम्बर बैठे हैं मै उनसे कहूंगा कि वे इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करने की परमि ान न दें और हमारे साथ 'नो' बोले।

डा0 भीम सिंह दहिया(रोहट): स्पीकर साहब, फौरेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड नही होना चाहिए, इस बारे में तो चौधरी बीरेन्द्र

सिंह जी ने बहुत कुछ कह दिया। मैं तो एक टैक्नीकल बात कहना चाहता हूं। यह तो मूझे पता है कि बोर्ड का नाम तो ये यही रखेगें क्योंकि ये मैजौरिटी में है। इसका नाम फोरेस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड रख गया हैं। डिवैल्पमैंट बोर्ड जो हैं यह एक स्पैसिपिक एक्टीविटी को प्वायंट बोर्ड रखा गया हैं। डिवैल्पमैंट बोर्ड जो यह एक स्पेसिपिक एक्टीविटी को प्वायंट आउट करता है लेकिन क्लाज 20 मे जो डियूथीज की डैमिनि ान दी गई हैं उसमें बी.सी. औउ डी. जो हैं वे डिवैल्पमैंट ऐक्टीवीज नही है। उसमें लिखा हैं:– (b) to market the various products both raw and refined goods, inside and outside the Stae fo Haryana; (c) to establish and manage industries based on forest procuce; (d) to undertake trade in forest produce and to promote the development of forest resoureces in the State of Haryana. इसलिए या तो डिवैल्पमैंट भाब्द को ड्रौप करके इसका नाम खाली फौरैस्ट बोर्ड रख लिया जाये या फिर फौरेस्ट डिवैल्पमैंट एण्ड मार्किटिंग बोर्ड रख लें।

राजस्व मंत्री(चौधरी फूल चन्द): स्पीकर साहब, बन विकास बोर्ड पर बोलते हुए चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कुछ आपतियां उठाई। उन्होने पहली आपत्ती यह उठाई कि इसकी धाराए भारत सरकार के फारैस्ट एक्ट के विरूध हैं। हमने कानूनी वि ोशज्ञो से राय ले ली है। इस बोर्ड के बिल की कोई भी धारा केन्द्र के एक्अ से कन्ट्राडिक्ट नही करती और यह जो बोर्ड बनाया जा रहा हैं। यह भारत सरकार की नई वन विकास नीति को ध्यान में रखते

हुए बनाया जा रहा हैं। आपको मालूम है कि पिछले साल में भी हरियाणा सरकार की और से 6 करोड़ पोधे लगाये गये थै। आपको यह भी मालूम हैं कि जब पंजाब और हरियाणा अलग अलग बने तो दोनो प्रान्त ही वनो से वंचित रह गए थे और सारे वन हिमाचल में चले गये थे। हरियाणा मे हम वन उगर रहे हैं। उनकों उगाने के लिए और उनकी इफैक्टिव इम्पलीमैंटे ान के लिये एक ऐसी एजेंसी की आव यकता थी जिसके लिये यह बिल हम ला रहे है। (विघ्न) एक प्रिवलेजड डाकुमैंट की बात कही बई कि मैं उसे छुपाता रहा। इस चीज को तो ये भी समझते है कि केन्द्रीय सरकार और प्रान्त की सरकार में कोई भी कम्यूनिके ान हो that is a privileged document and that cannot be disclosed. पता नही वह किस रास्ते से डिसक्लोज हो गया या इन्होने उसे कैसे पढ लिया? इसके लिये तो मै इनको दाद देता हूं। पता नही इन्होने कैसे घुस पैठ करके उसका विवरण ढूंढ लिया। इन्होने एक बात यह भी कही कि सारी की सारी पावर बोर्ड को दी जा रही हैं। ऐसी बात नही है, हम तो बिल ला रहे हैं उसमें पूरा कन्ट्रोल हरियाणा सरकार का होगा। कुछेक और भी आपत्तियां उठाइ गई। उनके बारे में मैने एक सवाल का जवाब देते हुए बातया था कि मामला कोर्ट में है यानी सब–जुडिस हैं। कानूनी राय हमने ले ली हैं, इसमे कोई आपत्ति वाली बात नही हैं। दहिया साहब ने कहा कि बोर्ड का नाम ठीक नही हैं। दहिया साहब बहुत काबिल मैम्बर हैं और मै उन्हे बताना चाहता हूं कि forest developement is the

specific pupose of this bill. Sale and marketing of forest is also one of the specific puposes of this bill.

श्री अध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा फौरेस्ट डिवैल्पमैंट बिल, 1983 को इन्टोड्यूस करने की परमि ान दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राजस्व मंत्री (चौधरी फूल चन्द): अध्यक्ष महोदय, अब मै बिल प्रस्तुत करता हूं।

(v) दि महार्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैडमैंट) बिल, 1983

श्री अध्यक्षः अब एजूके ान मिनिस्टर मूव करेगें कि महार्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैडमैंट) बिल, 1983 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

ि ाक्षा राज्य मंत्री(श्री जगदी ा नेहरा): स्पीकर साहब, मै प्रस्ताव करता हूं–

कि महार्शि दयानन्द वि वविधालय (सं ाोधन) विधेयक, 1983 को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि महार्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैडमैंट) बिल, 1983 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाए।

डा0 भीम सिह दहिया (रोहट): स्पीकर साहब, महार्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी ऐक्ट क्यो अमैंड हो रहा हैं इस बारे में कुछ कहना चाहूगां। अध्यक्ष महोदय, वहां के जो उपकुलपति हैं उन्होन कई सालो से बड़ा भाोर मचा रखा हैं। वे सरकार पर आरोप लगाते हैं कि यू.जी.सी. इस यूनिवर्सिटी को इसलिये रिकोगनाईज नही कर रहा हैं क्योंकि इसके ऐक्ट मे अमैडमैंट नही हो रही हैं। स्पीकर साहब, असलियत यह है कि जब था। उन्होने सिर्फ एक औबजैक ान किया था कि आपका जो 1975 का ऐक्ट हैं उसमें लिखा हुआ हें कि यह युनिवर्सिटी लाइफ साइंस को ऐडवांस करने के लिए बनाई गई है लेकिन हुआ क्या हैं कि कभी ला डिपार्टमैंट खोल दिया जाता हैं ओर कभी हिस्टरी डिपार्टमैंट खोल दिया जाता हैं लाईफ साइंस कि लिये कुछ नही किया गया जब इस औबजैक ान पर कुद कहा गया तो उन्होने कहा कि अगर आपने लाइफ सांइस डिपार्टमैंट नही बनाना हैं तो ऐक्ट चेज कर लिजिए। लेकिन इस समय हाउस के सामने उसक ऐक्ट की जा अमैडमैंट लाई जा रही है इसमे उसके बारे में कोई जिक्र नही है वह यूं का यू हैं। मै ज्यादा लम्बी कहानी मे नही जाना चाहता। मै इस बारे में सिर्फ दो तीन बाते ही कहना चाहता हूं। जो बिल हमारे सामने पे ा किया जा रहा हैं इसमे बहुत गलत और खतरनाक बात हैं। यदि वे बाते यूं कि यू रह गई तो यूनिवर्सिटी तबाह हो जाएगी। स्पीकर साहब, स्टैच्यटस को बनाने का या उनाक अमैंड करने का हर यूनिवर्सिटी में एक प्रोसीजर होता हैं जो स्टैच्यूटस बनाए जाते हैं या जो भी अमैंडमैंट की जाती हैं उसको पहले ऐगजीक्यूटिव

कौंसलि परपोज करती है, फिर उसको कोर्ट ऐप्रुव करती हैं और उसके बाद चांसलर ऐप्रूव करता हैं। लेकिन इस बिल के जरिए जो अमैंडमैंट लाई जा रही हैं वह यह कि ऐग्जीक्यूटिव कौसिंल के बाद कोर्ट की ऐप्रूवल की कोई जरूरत नही है वही फाईनल अथोरिटी होगी। ऐग्जीक्यूटिव कौसिंल मे 15 मैम्बर होते हैं। अगर यह कह दिया जाए कि सारे रूरलज कैबिनेट बनाएगी उन रूल्ज को हाउस के सामने ले जाने की कोई जरूरत नही हैं तो यह कभी नही होता ओर न ही ऐसा किसी दूसरे मुल्को में होता हैं। स्पीकर साहब, अगर यह बात महार्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव कौंसिल पर छोड़ दे तो आप अभी अंदाजा लगा सकते हैं कि वह क्या करेगें। इसके अलावा दूसरी बात मै यह कहना चाहता हूं कि वाईस चासंलर को एक एमरजैंसी पावर दी हुई हैं। वह एमरजैंसी पावर कुरूक्षेत्र और महार्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर को दी हुई हैं। वह पहले ऐक्ट में भी थी और इस ऐक्ट मे भी है। वह ऐमरजैंसी पावर यह है कि वाइस चांसलर जब जी चाहे, जब ठीक समझें अपने घर मे बैठ कर यूनिवर्सिटी के जो रूलज या स्टैच्यूटस हैं उनको बदल सकता हैं और ऐगजीक्यूटिव कौंसिल और कोर्ट की जो भी पावर्ज हैं उनको वह ख़ुद यूज कर सकता हैं। इस किस्म की बात होने पर इस ऐक्ट की जरूरत ही नही हैं सिर्फ एक वाइस चांसलर अप्वायंट कर दिया जाए वह जब मर्जी रूल्ज बनाए औरप जब मर्जी उनको अमैंड कर दे। मैं सरकार से यही कहूंगा कि आप वाइस चांसलर पर कोई चैक लगाए ताकि यूनिवर्सिटी अच्छी तरह से चल सके। इसके

अलावा बहुत सी बाते हैं। जैसे वहां के टीर्चस की बात है इस बारे में मै लिखित रूप से अमैंडमैट सबमिट कर रहा हूं और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि जब यह बिल कंसीडर हो उस समय मेरी वह अमैंडमैंट भी उस बिल के साथ जोड़ दी जाए।

ि ाक्षा राज्य मंत्री(श्री जगदी ा नेहरा): अध्यक्ष महोदय, अभी दहिया साहब ने यह बात कही कि महार्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी के उप–कुलपती ने भाोर मचा रखा हैं और उसकी वजह से यूनिवर्सिटी के ऐक्ट में अमैंडमैंट लाई जा रही हैं । अध्यक्ष महोदय मैं इनको बताना चाहता हूं कि ऐसा नही हैं इसकी मेन वजह यह हैं कि यू. जी. सी के नौर्मज के मुताबिक उस एक्ट को बनाया जा रहा हैं। वह एक्ट यू.जी.सी. के नामर्ज के मुताबिक न बनाने की वजह से यूनिवर्सिटी को करोड़ो रूपए का नुक्सान हुआ हैं। यू.जी.सी. के नार्मज के मुताबिक ही उस ऐक्ट मे अमैंडमैंट की जा रही हैं। अब यू.जी.सी. ने 40–50 लाख रूपए देने का वायदा भी कर लिया है। इसलिए मेरी प्रार्थना हैं कि इस बिल को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

Mr. Speaker: Question is—

That leave be granted to intoduce the Maharshi Dayanand University(Amendment) Bill 1983.

The Motion was carried

Minister of State for Education (Shri Jagdish Nehra): Sir, I intorduce the bill.

वर्श 1983–84 के बजट पर अनुदानों की मांगो पर चर्चा

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब 1983–84 के बजट पर डिमान्ड्ज फार ग्रांटस पर डिसक ान होगी। पहली प्रैक्टिस के अनुसार और हाउस का समय बचाने के लिए आर्डरप पेपर पर रखी गई सभी डिमांडज फार ग्रांटस एक साथ पढी गई तथा पे ा की गई समझी जाएगी। माननीय सदस्य किसी भी डिमांड पर डिस्क ान कर सकते हैं लेकिन बोलते समय वह डिमांड का नम्बर दे जिसके ऊपर बोलना चाहते हैं।

That a sum not exceeding Rs.5,48,36,520 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of the charges under Demand No.4 revenue.

That a sum not exceeding Rs.62,65,40,005 for revenue expenditure and Rs. 1,01,23,26,500 for capital expenditure be granted to Governor to defray Charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No. 15-Irrigation.

That a sum not exceeding Rs.40,33,88,750 for revenue expenditure and Rs.3,24,56,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of the charges under Demand nO.17-Agriculture.

That a sum not exceeding Rs.9,48,40,000 for revenue expenditure be granted to the governor to defray

charges that will come in the course of payment of the year 1983-84 respect of charges under Demand No. 18-Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 13,21,33,100 for revenue expenditure be to granted the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of the charges under Demand No.21-Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 4,73,03,000 for revenue expenditure and Rs.12,09,74,300 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of charges under Demand No.22-Cooperation.

16.00 बजें

चोधरी साहब सिंह सैनी(थानेसर): स्पीकर साहब, मै डिमांउ नम्बर 17 और 22 पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। डिमांड नम्बर 17 ऐगीकल्चर के बारे में हैं। स्पीकर साहब, गर्वनर ऐड्रेस में भी कृशि को बहुत ही ज्यादा महत्व दिए जाने के बोर मे कहा गया है। इस डिमांड के जरिए 40 करोड़ 33 लाख 88 हजार 750 रूपए की रा ि ा ऐग्रीकल्चर के लिए निर्धारित की गई है जोकि हाउस से मंजूर करवाई जा रही हैं। स्पीकर साहब, ऐग्रीकल्चर के लिए जो पैसा रखा गया है यह बहूत ही कम हैं। कृशि विभाग का बहूत बड़ा अदायरा हें। इसमे से बहुत ज्यादा पेसा इस विभाग की ऐसटेब्लि ामैंट पर खर्च हो जाएगां इसमे ंसे

ज्यादातर पैसा जो कर्मचारियों/अधिकारियों की तनखाहें और भत्ते वगेरह हैं उसमे चला जाएगा। इसलिए इस पैसे से किसानों को काई वि ोश राहत मिलने वाली नही हैं। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय गवर्नरप साहब के ऐड्रेस में सिंचाई की जितनी भी स्कीन्ज हैं वे सारी की सारी पैसे के बगैर अधूरी पड़ी हैं यह पैसे के बगैर भुारू ही नही की गई हैं या पैसे की कमी के कारण बीच में ही बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा स्पीकर साहब, सरकार ने किसानो को कीटना ाक दवाईयां देने की बात कही हैं। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य राव इन्द्रजीत सिंह पदासीन हूए।) चेयरमैन साहब, जो कीटना ाक दवाईया ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट और इफको की तरफ से किसानो को दी जाती हैं वही दवाई ओपन मार्किट में मिलती हैं। ओर उन दवाइयों में मिलावट पाई जाती हैं। चेयरमैन साहब कीटना ाक दवाइयो ंमे बहुत ज्यादा बंगलि हुई हैं ओर किसानों को सबसीडाइज्ड रेट पर जो कीटना ाक दवाइयो इफको और एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट की तरफ से दी जानी थी वही दवाई ओपन मार्किट मे ं200 या 300 रूपए की मिलती रही। इस तरह से कीटना ाक दवाइयों में बहुत ज्यादा बंगलिक हुई हैं। इसी प्रकार से खाद की बात हें। किसानों को जो खाद की मात्रा बहुत कम होती हैं। ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट की तरफ से किसानों को जो खाद सप्लाई की जाती हैं उन कट्टो में खाद का वजन कम होता हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो इस डिमांड के जरिए सदन से जितने पैसे की मंजूरी ली जा रही हैं । ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के

अधिकारीयों को राहत देने कि लिए इस पैसे की मंजूरी ली जा रही हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के कर्मचारियों/अधिकारीयों को तनखाहें और भते आदि देने के लिए पेसा मांगा जा रहा हैं। यह बहुत ही खतरनाक बात हैं। इसी प्रकार से गवर्नरप साहब के ऐड्रेस में ओर बजट स्पीच में यह कहा गया हैं कि हम किसानों को सस्ते दामों पर बीज देगें ओर खाद देगें तथा किसानों को हर तरह से राहत देंगे लेकिन जो पैसा एग्रीकल्चर के लिए दिया जा रहा हैं यह बहुत ही कम है इस पैसे से किसानों को बहूत ज्यादा राहत मिलने वाली नही हैं इस पैसे को बढाया जाए। कृशि मंत्री जी हाउस में बैठे हैं मैने इनको कुरूक्षेत्र जिले में एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट और इफको की इन्कवायरी के बारे में लिखित रूप में दिया हैं। उनकी इन्कवायरी की जाए। मुझे उम्मीद हैं कि कृशि मंत्री जी एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट और इफको की इन्कवायरी करवाऐगी। इसकी अलावा चेयरमैंन साहब, मैं डिमान्ड नम्बर 22 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। डिमांड नम्बर 22 काप्रोरे ान डिपार्टमैंट के बारे में हैं। पिछले साल यानि 01.07. 1981 से 30.06.1982 तक कोआप्रेटिव विभाग ने लैण्ड डिवैलपमैंट बेंका के जरिये हरियाणा राज्य में किसानो को ट्रैक्टर खरीदने , ट्यूबवैल लगाने तााि अन्य कार्यो के लिए लगभग 36 करोड़ 4 लाख रूपए का कर्ज दिया था। लेकिन अब 01.07.1982 से लेकर अब तक केवल 11 करोड रूपये को लोन दिया गया हैं। जबकि पिछले साल 25 करोड़ रूपये का लोन किसानो को अधिक दिया गया था। किसानों को जो 11 करोड रूपये कर्जा अग तक दिया

हैं। यह बहूत कम हैं जबकि कृशि वर्श 30 जून को समाप्त हो रहा हैं। मैं यह समझता हूं कि यह रा ि ा बहुत कम हैं जो अभी तक दी गई इसे और बढाया जाना चाहिए।

चेयरमैन साहब, इसी प्रकार से कोआप्रेटिव डिपाटमैंट के तहत भी किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत देने का प्रोविजन होना चाहिए था। जैसा मै पहले कह चुका हू कि जो रा ि ा ये इन डिमान्डज के जरिए मांग रहे हैं यह रा ि ा तो डिपार्टमैंट के अधिकारियों/कर्मचारियों के टी.ए.डी.ए. तथा तनख्वाह आदि पर खर्च हो जाएगी। किसानो को इस पैसे से कोई फायदा पहुंचने वाला नही हैं। सहकारी विभाग के बारे में मैने पहले भी बोलते हुए कहा है कि एक मिनी बैंक मोरथला। जिला कुरूक्षेत्र में एक धर्मबीर हुडा मैनेजर लगा हुआ थां उसने लगातार दो साल तक युनिवर्सिटी का डी.पी.ई.डी. कोर्स रैगूलरली किया हैं और साथ ही साथ बैंक से तनख्वाह भी ड्रा करता रहा हैं। डिपार्टमैंट मे इस तरह की जो बगलिग हो रही हैं। उसके बारे में भाायद मंत्री महोदय को भी मालूम होगा। इसी प्रकार से कोआप्रेटिव इन्टीच्यू ान के तहत किसानो को जो राहत देने की बात कही गई है वह भी ठीक नही हैं। कान्फैडप की देहात के अन्दर जगह जगह पर दुकाने खुली हुइ है। लेकिन उन दुकानों मे किसानो के लिए कोई सामान नही पहुच पाता है। कानफैड की जितनी भी दुकाने देहात के अन्दर हैं उनमें कोई सामान पूरा नही जाता। जो अच्छा अच्छा सामान होता है वह तो बिल्कूल ही नही पहुंच

पाता, उसको जो बड़े बड़े लोग बीच मे ही उठा ले जाते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सूझाव है कि किसानो को भी सारी चीजे इन दूकानो की मार्फत मिलनी चाहिए और किसानो के लिए अधिक सामान का प्रावाधान इन दुकानो मे होना चाहिए। चेयरमैन साहब, कान्फैड की दुकानो पर जो सटाफ लगा रखा हैं वह बहुत ही ज्यादा हैं। इस स्टाफ को भी कम किया जाना चाहिए। उनके पास चूंकि कोई सामान बेचने के लिए नही होता इसलिए वे भी हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं औरप तनख्वाह लेते रहते हैं। सरकार पर इस तरह का जो बर्डन है उनका कम किया जाना चाहिए। इस तरह का जितना भी नाजायज खर्चा होता हैं वह आम जनता पर ही पड़ता हैं। इसी प्रकार से भूगर मिलों की हमारे यहां हालत खराब हैं। प्राइवेट सैकटर में यमूना नगर के अनदर जो मिल लगी हूई है वह तो फायदें मे चल रही ह और काआप्रेटिव सैक्टर में जो मिले लगी हुई है वे सभी की सभी घाटे मे चल रही हैं। वे घाटे मै इस लिए चल रही है कि वहां का ऐडमिनिस्ट्रे ान ठीक नही होता उसका पता है कि साल या 6 माह के बाद उनकी बदली हो जानी है इसलिए वे रूचि लेकर काम नही करतें इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इस और भी सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। गन्ने की जो कीमत आज किसानों को सरकार की तरफ से दी जा रही है उससे तो किसानो की गन्ने की का त की लगत भी पूरी हो पाती। सरकार 20 रूपये प्रति किवंटल के हिसाब से पेमैंट करती हैं जबकि उसकी कोस्अ इससे कही अधिक आती हैं। प्राईवेट जौ क्रे ार या छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगी हुई है वे

तो 20 रूपए की बजाऐ सिंर्फ 10–12 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ही किसानों को गन्ने की पैमेंट करती हैं जिससे किसानो को बहुत ही घाटा हो रहा है। यमूनानगर मे जो पूरी नाम के व्यक्ति की मिल लगी हूई है उसने तो किसानों के गन्ने को लेने की मात्रा भी कम कर दी हैं। पहले जिस किसी किसान से समय के अनुसार 100 ट्राली ली जाती थी अव पड़ते के अनुसान 20 या 50 कर दी हैं। जिससे किसान का गन्ना खेत में खड़ा रहेगा। उसे मजबूरन अब प्राइवेट क्षेत्र में जो इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं उनको 10 रूपये क्विंटल के हिसाग से ही देना होगा जिसके कारण यह बहूत ही घाटे मे जाएगा। इस संबंध में मेरा सरकार को सूझाव हैं कि सरकार को गुड़ का एक्सपोर्ट करना चाहिए जिस गुड की कीमत बढ सके और जो लोग क्रे ान लगाए हुए है वे किसान को अधिक से अधिक गन्ने का मूल्य दे सके। यदि किसानों की समस्या की तरफ ध्यान न दिया गया तो मजबूरन किसानों को पहले की तरह अपने गन्ने के खेतों मै आग लगानी पड़ेगी। इस डिमांड मे भी किसानों को राहत देने वाली कोई बात नजर नही आती। चेयरमैन साहब, मै एक बात और लैण्ड डिवेलपमैंट बैंक के बारे मै कहना चाहता हूं। लैण्ड डिवैल्पमैंट बैंक की तरफ से किसानों को ट्रैक्टर खरीदने व इन्जन आदि खरीदने के लिए कर्ज दिया जाता हैं लेकिन यह कर्ज किसान को न देकर बैंक डीलर को देता हैं जिसमें सामान खरीदना होता है। इस तरह डिलर्ज को सीधा पैमैन्ट करने से बैंक के एम्पलाईज और डिलर्ज मिल कर बिच मे कमी न खा जाते हैं जिस के कारण किसान को सफर करना

पड़ता हैं। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि इस प्रकार का लोन किसानों को दिया जाए वह सीधा किसानों का ही दिया जाए न की डीलर को। सीधा लोन उसे मिलने से वह अपनी चीज कही से भी खरीद लेगा ओर उसे सफर नही करना पडेगा। 500—700 रूपए का जो कमी ान ऐम्पलाईज और डीलर मिल कर खा जाते हैं उससे किसान बच जाएगा। इस संबंध में मेरी पुनः सरकार को प्रार्थना हैं कि पैसा सीधा एग्रीकल्चरिस्ट को दिया जाना चाहिए। इन भाब्दो के साथ चेयरमैन साहब, मै आपका ध्न्यावाद करते हुंए अपना स्थान लेता हूं ओर जिन डिमांडज के तहत ये पैसा मंाग रही हैं मैं उन का विरोध करता हूं।

प्रो0 सम्पत सिंह(भट्टूकलां): चेयरमैन साहब, सबसे पहले मै डिमाण्ड नमबर 4 के बारे मे बोलना चाहता हूं। यह 5,48,36,520 रूपए की डिमाण्ड राजस्व विभाग से संबंधित हैं। यह बात ठीक हैं जो पैसा ये मांग रहे हैं उसे खर्च किया जायेगा। मैने पहले भी बातया हैं कि हरिजनो के पास जमीन नही हैं, यदि है भी तो बहुत कम हैं। जिन लागो के पास जमीन थी उनकी जमीन सरप्लस लेण्ड मे आ गई। 1965 से ऐसे केसिज चले आ रहे है जिन्हे जमीन पर काम करते हेंए आज 20—20 साल हो गए हैं लेकिन उनको कब्जा उस जमीन का आज तक नही मिल पाया हैं। ऐस जमीनो पर अधिकतर हरिजनो का कब्जा हैं, उनको आज की सरकार बसाने की बजाये उखाड रही है। इसी तरह से जो लोग पाकिस्तान से आये थे उनको भी यहां पर जमीन अलाट होनी थी।

कुछ लोगों को जमीन अलाट होने से रह गई थी। चेयरमैन साहब, हालत यहां तक खराब है कि जो लोग पाकिस्तान में ही मर गए है उनके नाम भी मरने के बाद जमीन अलाट करवाई जा रही हैं। चेयरमैन साहब, यह बड़े राज की बात है। बड़ी महंगी जमीन को जिसकी किमत 500–700 रूपये एकड़ हैं, रि वत ले करके बेचा जा रहा हैं। सरकार के जो उच्च कोटी के लोग हैं उनक लोगो के साथ मिलीभगज कंरके कुछ बोग बीच में कमी ान ले रहे हें। झूठे आदमियों के नाम गलत ढंग से जमीन अलाट करवाई जा रही हैं। चेयरमैन साहब, इतना ही नही आज हरियाणा के अन्दर सिर्फ तीन व्यक्तियों को ही पावर आफ अटार्नी दी हुई हैं। इनमे से एक अबूब ाहर को कोई ि ावनारायण हैं, एक कोई जुलाना का ब्यक्ति हैं और तीसरा रोहतक का कोई मि.अरोड़ा हैं। आज हरियाणा के अन्दर इन्ही सिर्फ तीन व्यक्तियो पास पावर आफ अटार्नी हैं। यह सरकार आज किसानों को एक रूपये तक देने के लायक नही रही है। चेयरमैन साहब, आज ये एग्रीकल्चर के संबंध में करोड़ो रूपये कि डिमांड मांग रहे हैं। आज प्रातः ही आपने अखबार पढा होगा जिसके अन्दर सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने हरियाणा सरकार कौ बुरी तरह लताडा हैं। केन्द्रीय सरकार ने कहा हैं कि पांच साला योजना जो थी उसके अन्दर 55 करोड़ रूपये रखे गये थे। अब तक इस सरकार ने मु ि कल से 20 करोड रूपया ही खर्च किया हैं। यह पैसा भी तीन साल में खर्च किया हैं। हमारे सैन्ट्रल गवर्नमैंट के एग्रीकल्चर मिनिस्टरप बड़े सुलझे हुए हैं। पता नही उनका कही कही जरूर गडबड़ हैं। सैन्ट्रल गवर्नमैंट की और

हरियाणा सरकार की आपस मे अनबन हो गई हैं जिसकी वजह से हरियाणा सरकार को लताडना पडा हैं। इस सरकार को बदल जान चाहिए क्योंकि हरियाणा दिन प्रतिदिन सफर करता जा रहा हैं। पैसा ठीक जगह इस्तेमाल नही हो पा रहा हैं जिस कारण यह पैसा लैप्स होता जा रहा हैं। हरियाणा के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वे भी बड़े सुलझे हुए और योगय हैं पता नही इन्हे अब क्या हो गया हैं? पिछले दिनों जब ये पब्लिक अंडर टेकिंगज कमेटी के मैम्बर थे तो बडी बहादूरी के साथ काम किया करत थे। इन्होने एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरे ान में बडी़ बहादूरी के साथ कमियां निकाली थी ओर उन कमियों को दूर करने के लिए सुझाव दिये थे औरप आग्रह किया था कि अगर ये सूझाव मान लिये जाए जो कारपोरे ान का काम ठीक हो जाएगा लेकिन श्री भजन लाल कम्पनी को जवायन करने के बाद इनको भी कुछ हो गया है। ये भी कुद कर नही पाते हैं। हां इनको कुछ न कुछ ि ाकायत जरूर रहती हैं। हमकों इनसे बडी़ उम्मीद थी लेकिन अब वे कुछ करते ही नहीं। इनको सारे लूप होल्ज का पता हैं मुझे भी पता हैं। पी.आर.ओ. चाहे किसी को लगा दो चाहे किसी को हटा दो मुझे इस से कोई वास्ता नही हैं। दक्ष कुमार जैंन कोन हैं। इसको किस तरह हटाया गया, किस तरह से गडबड की गई हैं किसकी वजह से किसको दिलचस्मी हैं इससे हीमे कोई ताल्लूक नही है। चेयरमैन साहब, मै तो यह कहना चाहता हू कि आज सीड कारपोरे ान का बहुत बुरा हाल हैं। सीड कारपोरे ान बना तो रखी हैं लैकिन यह कारपोरे ान करती क्या हैं यह मै आपको

बताना चाहता हूं। इस कारपोरे ान मे एक गैंग बना हुआ है खास तोर से हिसार मै बना हुआ हैं हिसार में पिछले दिनो मे स्कैंडल हुआ थां यह आपका पता हैं। इस कारपोरे ान ने 14 हजार क्विंटल चना सीड के लिए खरीद लिया ओर यह चना बहुत घटिया था। कम रेट पर खरीद लिया और 400 रूपये क्विंटल यानी दूगने रेट पर किसानों को बेच दिया। लैबोरिटी मे जब इसको टैस्ट करवाया गया तो लैबौरेटरी वालो ने इसको सब–स्टैंडड घोशित कर दिया। इस कारनामे से सीड कारपोरे ान का कुछ नही बिगड़ा। अगर बिगडा है तो स्टेट का बिगडा हैं स्टेट को नुकसान हो गया और जिस किसान ने बीजा हैं उसका नुकसान हुआ। कारपोरे ान का कुछ नही बिगडा। अब सुना हैं कारपोरे ान ने इस सीड को औक ान कर दिया। इस तरह से लाखो रूपया का हरियाणा गवर्नमैंट को इस कारपोरे ान की वजह से नुकसान हुआ हैं। सीड को बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया जाना चाहिए, इस पर सारी स्टेट निर्भर लोगों को फायदा हौ औरप स्टेट की प्रोडक ान बढें। हरियाणा का किसान महेनती है रात दिन मेहनत करता हैं लेकिन इस प्रकार के बीज सप्लाई करने में उसके पल्ले कुछ नही पडता । इसका मेन कारण यीह है कि अच्छे बीजों की कमी हैं ओर इस औब्जैक्ट को अचीव करने के लिए यह कारपोरे ान नाकामयाब हैं। यही हाल फर्टिलाईजर का हैं। आज फर्टिलाजर पर सबसिडी मिलती हैं। अच्छी बात हैं सबसीडाइज्ड रेट पर खाद मिले, लेकिन इस सबसीडी को बीच के कुछ लोग खा रहे हैं। जिन लोगों का इसके साथ वास्ता हैं। वे खाद खा रहे

हैं। टोहाना में फर्टिलाईज और विडीसाईड की डिस्ट्रिक्यु ान मे घपला हुआ हैं। जब फर्टिलाईज और विडीसाईड की डिस्ट्रिव्यू ान हो रही थी तो किसी ने डी.सी. हिसार को टैलीफोन किया था कि बोगस परमिट काटे जा रहे हैं और खाद नाजायज तरीके से खाया जा रहा हैं। इस तरह घपलो में एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट बिलिंग कर रहा हैं बिलिंग तो करनी ही पडेगी लेकिन चेयरमैन साहब, वहां पर ऐसे इन्फलूएि ायल आदमी बैठे है जिनके प्रभाव से हमारे मिनिस्टर कुछ कर ही नही सकते। करते भी कैसे क्योकि यह मुख्यमंत्री के लेवल की बात हैं। सारी खाद एक ही आदमी खा रहा है। टैलिग्राम देनेप के बावजूद भी इन्कवायरी नही हुई कुछ भी नही हुआ। ऐसा पता लगा हैं कि उंचे दर्जे के लाग इस में इनवाल्वड हैं। चेयरमैन साहब, अगर ये इन्कवायरी करवाऐगें तो हम साबित करेगे और इस इन्कवायरी में इसकी मददे करेगें, इसको इस बात की चिन्ता नही करनी चाहिए। इस तरह ऐग्रो इंडसट्रीज कार्पोरे ान आज अढाई तीन करोड़ रूपये के घाटे मे डूबी पडी हैं। इसके अस्ैटस साढे 6 करोड़ रूपए के हैं और जायबिलिटीज साढे 10 करोड़ रूपये की है। यह हाल है एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट का। इसके अलावाप एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट ने मैलाथीन परचेज करने के लिए आर्डर्ज दिए थे। जब खरीद चुके तो पता लगा कि इसमें खराबी हैं। लैबोरेटरी में जब टेस्ट करवाया गया तो लेबोरेटरी ने इसको सब–सटैडर्ड घोशित कर दिया। टैस्ट करने के लिए इसको सैंट्रल इंयटीच्यूट मे भेजा गया। जिस सैम्पल को लेबोरेटरी ने पास किया उस सैम्पल की मैलाथीन को

किसानो को बेच दिया गया। जिन किसानों ने इसको इस्तेमाल किया था उन्होने कह दिया कि इस दवाई ने तो फसलो का ना ा कर दिय। फिर दोबारा लेबोरेटरी मै टैस्ट करने के लिए भेजा गया। फिर लेबोरेटरी ने इस को सब–सटैंडर्ड घोशित किया। लेकिन चेयरमैन साहब, ऐग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरे ान को इन बातो की जरा भी परवाह नही हैं। मै सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या ऐग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरे ान कोई प्राइवेट कम्पनी हैं जो जैसा चाहे करती रहे? इस कार्पोरे ान मे जितना पेसा लगा हैं। वह हरियाणा सरकार का लगा है। इसलिए इस ढंग से पैसे को वेस्ट नही करना चाहिए। चेयरमैन साहब, इसी तरह से पिछले दिनां में हमारे यहा हायर परचेज बेसिज पर 2 लाख रूपय की वसूली ट्रैक्टर कई एन्टरप्रन्योर्ज को दिए गए थें लेकिन तीन साल के बाद इस रूपय की वसूली नही हुई। फिर यह रूपया कि तों पर देने का हुकम जारी हुआ लेकिन फिरप भी कार्पोरे ान को पैसे नही मिले क्योंकि जब पैसा बकाया है वे इसी कार्पोरे ान मे नौकरियां कर रहे हैं। जब ये लोग नौकरियां कार्पोरे ान में कर रहे है तो यह पैसा इनकी तनख्वाहो मे क्यो नही काटा जा रहा? यह पैसा इन लोगो से वसूल होना चाहिए।

चेयरमैन साहब,एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फूड प्रोसैसिंग प्लांट मूरथल मे है। वहां पर जूस, जैम वगैरहा कई चीजे बनती हैं। भले राम जी के मुह मे पानी आ रहा हैं। (हंसी) वहां पर सरसों का साग तैयार होता हैं। अगर यहां पर सही ढंग से काम

चलाया जाए तो काफी प्रोफिट हो सकता हैं। लेकिन आप हैरान होगें यहां भी 70–80 लाख रूपए का घाटा हैं। अब आप पूंछेगे यहा क्या हो रहा हैं? चेयरमैन साहब, इसके पहले जो चेयरमैन साहब, हुआ करते थें वे विदे ा यात्रा पर गए थे यह बात इस रिपोर्ट से पता चलती हैं।विदे ा जाकर तकरीबन 16–17 हजार रूपए का आर्डर लेकर के आए लेकिन खर्चा इससे दूगना करके आए। इस सोदे मे हमे एक पैसा नही मिला। यह आर्डर एक कम्पनी से ले कर आए थे। लेकिन हमें एक पैसा फायदा नही हुआ। इसी तरह से इन के एयर क्राफटस का हाल हैं। तीन एयरप क्राफटस तौ पहले ही ड्स्पोज आफ कर दिये और एक सोहना के पास पडा़ हैं। पता नही इसका क्या करेगें। इसके बारे में मैने एक काल अटैन्ा न मो ान दी थी, उसका पता नही क्या बना? मेरा कहने का मतलब यह हैं कि सारे के सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट का भट्ठा बैठ रहा है।

चेयरमैन साहब, इसी तरह कोआप्रे ान डिपार्टमैंट मे हो रहा हैं। कोआप्रे ान डिपार्टमैंट में तो इससे भी बुरा हाल हैं ये किसान के बैटे हैं इनका चाहिए कि किसान को कोओप्रेटिव सोसायटीज से ओर बैंको से लोन दे और इस लोन पर इन्ट्रैस्ट कम करें। मै कोआप्रे ान मिनिस्टर को याद दिलाता हू कि आज किसान की हालत वही है जो 1935 में थी, जब छोटू राम हुआ करते थें। अगर सर छोटू राम कर्जे का बिल पास न करवाते तो आज किसान के पास जमीन न होती। आज भी किसान कर्जे में

दबा हुआ हैं, जैसे वह 1935 मे दबा हुआ था। इसलिए मेरी सरकार से गुजरि ा हैं कि किसानो के इस कर्जे को माफ कर दें। आज जितने भी मिल है वे सब के सब घाटे मे चल रहे हैं। घाटा इसलिए हैं कि कुछ आदमी फायदा उठा रहे हैं। करप ान कर लेते हैं। जैसे करनाल मे एक तगड़ा बिजनैसमैन के ताललूकात हैं। वह 9–10 रूपए किव्ंटल के करीब गन्ना खरीद लेता हैं ओर मिल में 20 रूपए क्विंवटल के भाव से बेच देता हैं। किसान का गन्ना इस मिल मे नही गया उस बिजनैसमैन का गन्ना गया और इस तरह से करोड़ो रूपया कमाया जा रहा है। चेयरमैन साहब, हांसी स्पिनिंग मिल की बडी आमदनी थी लेकिन आज यह भीघाटे मे जा रही है। यह घाटा कयो हो रहा हैं? यह हो रहा है मिस मैनेजमैंट और करप ान की वजह से । चेयरमैन साहब, यही हाल कोआप्रटिव बैंकस का हैं। इनकी भी दयनीय हालात हैं।

श्री सभापतीः आप वाईड–अप कीजिए।

प्रो. सम्पत सिहंः अभी दो मिनट मे खत्क करता हूं। चेयरमैन साहब, कोआप्रे ान डिपार्टमैंट में क्लर्कस, अकाउंटस क्लर्कस और जुनियर अकाउटैंट की पोस्टे भी गई लेकिन इन में कोई भी हरिजन केंडीडैट नही लिया गया। इस बारे में हमारे साथी मैम्बरान ने जब एतराज उठाया तो मुख्य मंत्री जी, ने वि वास दिलाया कि हरिजनों के लिए नवम्बर में फिर से इन्टरव्यू रखे हुए हैं। इन्टरव्यू हुए लेकिन पता नही एक नयी जाति हरिजनो में कैसे आ गई? भूप सिंह बि नोई, फतेहाबाद और राजेन्द्र सिंह

बि ानोई, अबोहर को सिलैक्ट किया गया। यह हरिजन जाति मे कब से भाामिल हो गए हैं? हरिजन जाति से ताल्लूक रखने वालो को लिया नही गया और दूसरे लोगो का रख लिया गया। हरिजनों को इस सरकार ने क्या इग्नोर किया जबकि लडके अवेलेबल थे?

श्री सभापतिः आपको बोलते हुए काफी समय हो गया हैं इसलिए आप वाइंड–अप करे।

प्रो0 सम्पत सिहंः चेयरमैन साहब, अभी एक मिनट मे खत्म करता हूं। इसी प्रकार का हाल ऐनिमल हस्बैंडरी डिपार्टमैंट का है। हिसार जिले में एक लाईव स्टाक फार्म हैं। उस फार्म में बडी़ अच्छी दूध देने वाली भैसे और गाये रखी हुई हैं। वहां पर अभी प ाु बडी़ अच्छी नसल के रखे जाते हैं। यह फार्म सारे एि ाया मे म ाहूर हैं। आज उस फार्म में इल प ाुओ के चारे को एक आदमी खा रहा हैं। प ाुओ को सही ढंग का चारी नही डाला जा रहा हैं। वह आदमी सुप्रिटैन्डैन्ट के पद पर लगा हुआ हैं। कवालिफाईड न होते हुए भी वहा लगाया हुआ हैं क्योकि वह मुख्य मंत्री जी, के हल्के का हैं। वह प ाुओं के चारे के पैसे तो खा ही रहा हैं साथ दूध में पानी भी मिला रहा हैं। दूध की नकली परचियां भी पकडी़ जाती हैं तो वैंडर के खिलाफ एक ान लिया जाता हैं उसे कोई पूछने वाला नही है। अगर अखबारों के छपवातें है तो धमकी दी जाती हैं कि मै आप लोगो को देख लूंगा क्योंकि मेरी आगे तक पहुंच हैं। इस किस्म के हालात आज

हरियाणा प्रान्त मे पैदा हो रहे हैं। जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्रीमती करतार देवी(कलानौर अनुसूचित जाति): चेयरमैन साहब, सब से पहले तो मै आपका धन्यवाद करती हूं क्योंकि आपने डिमानडज पर बोलने के लिए मुझे समय दिया। मै डिमान्डज नम्बर 4,17,18 और 22 पर अपने विचार रखना चाहती हूं। मै सदन को अधिक समय नही लेना चाहती क्योंकि अन्य आदरणीय सदस्यों ने भी अपने विचार प्रकट करने है। मै थोड़े ही समय में अपने विचार रखने का प्रयत्न करूगीं। चेयरमैन साहब, डिमान्ड नम्बर 4 रेवेन्यू के बारे के है उस पर कुछ अर्ज करना चाहती हूं। रेवेन्यू का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हैं। हरियाणा प्रानत का बेस हैं। विकास के क्षैत्र मे आगे बढने के लिए पहला कदम हैं। बजट में भी और बीस सूत्री कार्यक्रम में भी इसे द ार्या गया है। इस विभाग के कार्यक्रमो को इम्पलीमैंट करने से गरीब लोगों की उन्नति हो सकती है। जो तक गरीब लोगो को प्लाटस ओर सरपल्स लैन्ड देने की बात हैं। इस बारे में सरकार ने काफी कुछ किया हैं। यह तो नही कहा हा सकता कि इस बारे में सरकार ने कुछ भी नही किया लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि जिन लोगों को सरपल्स जमीन अलाट की गई हैं। उन्हे मुकदमैंबाजी मे पड़ा रहना पड़ता हैं। उन्हे जमीन तो अलझट हो गई लेकिन उसके कब्जे की सुरक्षा पूरी तरह से नही कर पा रहे हैं। वर्तमान कानून में इस किस्म की कमिय्र हैं कि वह अपनी

जमीन की पूरी तरह से हिफाजत नही कर पाता हैं। चेयरमैन साहब, मेरा इस बारे में सरकार को सुझाव है कि जो वर्तमान में सं ाोधन हो। अगर यही कानून रहा तो गरीब आदमी को उस जमीन के अलाट करने को कोई भी लाभ नही हैं।

चेयरमैन साहब, प्लाटस के विशय में भी यही हालत हैं। मै अपने हल्के कलानौरप के गाव से परिचित हूं। प्लाअस कई बार हो चुकी हैं। एक बार अलौटमैंट उस समय हुई थी जब बन्दोबस्त हुआ था। बन्दोबस्त के टाईम पर गरीब लोगोंप को प्लाटस दिए गए फिर बीस सूत्री कार्यक्रम के आधार पर 100—100 गज के प्लाटस देने की बात की गइफ लेकिन देखने में आया है कि वही प्लाटस बार बार अलौट किये जा रहे हैं।(ाोर) यह बात नही कह सकते कि काग्रेंस सरकार ने प्लाटस हरिजनो को अलौट ही नही किए हैं। प्लाट तो अलो हुए है लेकिन जो पंचायत का सामूहिक रकबा छोडा जाता हैं उसके बारे मे हर बार स्टेटमैंट मे लिचा दिया जाता हैं कि हमारे गांव में एक या दो एकड़ ही अलौअ किया जाता हैं। (ाोर) चेयरमैन साहब, आज तो हमरी कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं अनके लिए भावी कदम उठाने पड़ेगे उनके बारे में सतर्क होना पड़ेगा ताकि उन नीतियों को सही रूप मसे इम्पलीमैंट यिा जा सके। अगर हम उन नीतियों का ठीक तरह से पालन नही करेंगे तो हमारी इमेज खराब होगी लेकिन जो इस डिमान्ड के थ्रु पैसा मांगा हैं उसका तो मै समर्थन करती हूं क्योकि यह बहूत ही बडा़ विभाग हैं। नये कार्यक्रम को चलाने के

लिए जितना अधिक पैसा मिले उतना ही अच्छा हैं। अपोजी ान के साथी कई बार तो अच्छी बातों का भी समर्थन नही करते हैं। बिना सोचे समझे ही कहना आरम्भ कर देते हैं कि वहा भ्रश्टाचार हैं अव्यव्सथा हैं। जब वे इन बातो के बारे मे बोलना भाुरू करते हैं तो इन छोटी मोटी बातों मे ही बात खत्म हो जाती हैं।

मेरे से पहले बोलने वाले भाई ने बिजली और सिंचाई के बारे मे काफी कुछ कहा। मैं तो इस हाउस की पहली बार मैंम्बर बन कर आयी हू लेकिन जो भाई पहले से बन कर आए हुए हैं वे कांग्रेस सरकार और पिछली सरकार की नीनियों की तस्वीर को सामने रख कर सोंचें जिस समय पार्टी की सरकार आयी थी तो लोगो के मन मे यह विचार ाि कि यह सरकार कांग्रेस पार्टी से अच्छा काम करके दिखलाऐगी लेकिन कांग्रेस की सरकार से अच्छा काम नही कर पाई। चेयरमैन साहब, विरोधी दल के भाईयो ने रेवेन्यू की डिमान्ड पर मजाब भी उडाया हैं। मै उस टाईम की बातो कौ भूली नही हूं। जिन गरीब आदमियों को थोड़े बहुत प्लाटस दियो गये थे। उनके भी कब्जे जनता सरकार के टाईम मे छीन लिये थे। हरिजनो के दिमाग से पिछली सरकार की बात आत तक निकली नही हैं। जितना उस समय कहा गया था उतना जनता पार्टी की सरकार नही कर पायी थी। जितना उस समय कहा गया था उतना जनता पार्टी की सरकार नही कर पायी थी। वे लोग आज भी किसान की भलाई का दावा करते हैं। उस टाईम बिजली और सिंचाई के लिए 144 करेाड रूपया रखा गया था

लेकिन इस बार 235 करोड़ रूपया रखा गया है। वाटर कोसिर्ज और कैनालज को पक्का करने के लिए 200522 करोड़ रूपये का प्रबन्ध किया गया है। हमारी सरकार ने वर्ल्ड बैंक से इस बारे में ऐग्रीमैंट किया हैं। इससे इरीगे ान के पानी को ठीक प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकेगा।

चेयरमैन साहब, हमारी सरकार जितली भी अधिक से अधिक सरप्लस लैंड दे सकती थी उसके लिए प्रयास किया गया हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जितनी भी नई माईनर्ज इस सरकार के आने के बाद बनी हैं भाायद इससे पहले कभी और किसी सरकार के समय नही बनी। मेसे अपने हलके कलानोर में पिलाला माईनर सन् 1962 में बननी आरम्भ हुई भी लेकिन इस सरकार के आने के बाद ही वह पूरी हुई हैं। चेयरमैन साहब, मेरे हलके में इरीगें ान की कमी है। मै सरकार से अर्ज करूगीं कि गुडाना माईनर, बडौदी जाटान बडौछी रागड़ान आदि माइनर्ज के लिए मामला सरकार के अन्उर कन्सीडरे ान हैं। अगर उन्हे जल्दी से जल्दी कम्पलीट करा दिया जाये जो लोगो को काफी सहूलियत हो जाएगी। चेयरमैन साहब, हमारी अपोजी ान के साथी मजाक उड़ाते है। मै उनको बताना चाहती हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम ने सामाजिक व्यव्स्था में मोड दिया हैं ताकि गरीब आदमी ऊपर उठ सके। हम अपनी नीतियों के अनुसार अपने कर्तव्यो का पालन कर रहे हैं।

इसके अलावा मैं एक और बात प ा पालन विभाग के बारे मे कहना चाहती हूं प ा–पालन विभाग जिस में डेरी विकास ओर मछली विकास के लिए कुल मिला कर 1979–80 में 2.64 करोड़ रूपया रखा गया था उसके लिए इस साल बजट में 4.52 करोड़ रूपया रखा गया है। मै इस बात के लिए सरकार को बधाई देती हूं ओर यह समझती हू कि अगर हमारे विरोधी सदस्य ऐसी स्कीमो स्कीमों की नेगेटिव साईउ की ओर सोचने की बजाए कुछ रचनात्मक सहयोग दें जैसे कैसे फार्म भरा जाता हैं केसे और कहां से उनको कर्जा मिल सकता हैं ओर लोगा की डे–टू–डे समस्याऔ की ओर भी ध्यान दे तो अच्छा होगा। इससे हम लोग भ्रश्टाचार को रोकने में भी कामयाब होगे। मै समझती हूं कि जितनी भी मांगे रखी गई हैं यह ग्रामीण विकास के लिए जायज है और मैं समझती हूं कि जितनी भी मांगे रखी गई हैं यह ग्रामीण विकास के लिए जायज हैं ओर मै उन का समर्थन करती हूं। अब मै कुछ सहकारिता के बारे में भी कहना चाहूंगी। सहकारिता के बारे में वे कहते हुए हमारे कुछ भाईयो ने इस मूवमैंट को कन्डैम किया हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि अच्छा समाज बनाने का स्वपन तो हम ले रहे हैं कि हम समाजवादी समाज बनायगें लेकिन वह कैसे आएगा जब तक हम सहकारिता की बात को नही अपनायेगे। जब तक हम इकट्ठे होबर मिल कर काम करना, इक्ट्ठे होकर रहना नही सीखेगें तो कैसे हम समाजवादी समाज बना पायेगें। जब तक हम इक्ट्ठे मिलकर रहने ओर काम करने की प्रवृति को प्रोत्साहन नही देगें तब तक हम सामजवादी समाज की स्थापना में कामयाब

नही हो सकते। जब कोई चीज की जाती हैं तो यह होता है ही है कि उसमे कई बार कमियां रह जाती हैं। पहले हमने जब अफसर ााही पर कार्यक्रमों को छोड़ा था तो वह पूरी तरह से चौकस रहे। जो काम सहकारिता के क्षेत्र मे हुआ हैं। वह समाज के निर्माण के लिए बहुत ही अच्छा काम हुआ हैं। अग जो काम कृशि के क्षेत्र मे, सहकारिता के क्षेत्र में सिंचाई के क्षेत्र में और बिजली के क्षेत्र में किया जा रहा हैं वह समाजवादी व्यवस्था को कायम करने ओर हमारे मौजुदा समाज को बेहतर बानने के लिए एक ईमानदाराना कदम है। मै यह बात यहा पर कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार पूरी तरह से जागरूक हैं। इस के साथ ही हमारी की जिम्मेवारी भी बनती हैं कि हम भी जागरूक रहें। चेयरमैन साहब, मै एक बात कहना चाहूंगीं। मेर हलका कलानौर एक ऐसा हल्का हे जो सब–अर्बन हैं। वहा पर हाई स्कूल भी ओर कालेज भी हैं। मेरे हल्के में एजूके ान तो बहुत ज्यादा है लेकिन एम्पलायमैंट के एवेन्यूज बहुत थोड़े हैं। इस वजह से हमें एजूंके ान तो बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा हैं कि जिसका कोई हिसाब नही हैं। जब तक हम लोगों को पूरी तरह से रोजगार के अवसर प्रदान नही करा सकते, जब तक हम अपने आपको पूर्ण रूप से कामयाब नही कह सकते। इस लिए मैं आप के माध्यम से यह कहना चाहती हें कि मेरे इलाके मे भी सहकारिता के क्षेत्र मे कोई भी स्पिनिग मिल या जिनिंग मिल या कोई पेपर मिल लगाई जाए ताकि वहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। मै सदन का ज्यादा समय नही लेना चाहती।

जितना समय आपने मुझे बोलने के लिए दिया हैं, भाायद मैं उससे भी एक दो मिनट कम ही लूंगी। जो मांगे यहा पर रखी बई हैं मैं समझती हूं कि ये जायज मागं हैं और मे इनका समर्थन करती हूं। यहां पर अपने माननीय सदस्य साथियों से यह भी कहना चाहती हूं कि हम सब को अपनी जिम्मेवारी का अहसास होना चाहियैं। कोई अलोचना करने से पहले हमें जिन परिस्थितियों में हम रह जाते हैं अनक बारे में भी सोचना चाहिए। इनको यह भी सोचना चाहिये कि जब सत्ता इनके पास थी, तब इन्होने क्या किया था? आज ये लोग बहुत बढ–चढ कर बाते करते रहते हैं। अगर ग्रामीण भाईयो के विकास के लिए एक फण्ड बना दिया गया तो कोई गलत काम नही किया गया हैं। ग्रामीण विकास के लिए एक फण्ड बना दिया गया तो कोई गलत काम नही किया गया है। ग्रामीण विकास नाम की चीज आपके बजट में कभी थी ही नही। साढे चार करोड़ रूपया अब डी.ए.पी., आर.ए.डी.पी. और एन. आर. डी.पी के लिए रखा गया हैं। यह व्यवस्था इसलिए की गई हैं ताकि ग्रामीणो का विकास हो। चेयरमैन साहब, मै सरकार का इस लिए धन्यावाद और आभार प्रकट करना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र के विकास के लिए सहकारिता के क्षेत्र में कोई न कोई मिल जरूर लगाई जाए और वहां पर कृशि और सिचाई की व्यवस्था अच्छी बनाने के लिए खुडाना माईनर और एक नयी माईनर बनाने के लिए जो प्रोपोजल भेजी हुई हैं उसको स्वीकृत किया जाए तथा उन माईनर्ज को जरूर बनाया जाये और जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। इन भाब्दों के साि मैं इस बजट की डिमान्डज का

समर्थन करती हूं और आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

बहन भाान्ति देवी (करनाल): चेयरमैन साहब, सरकार को लोगों की भलाई के काम करने के लिए राजस्व की जरूरत होती हैं क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा, कोई भी कार्यक्रम चल नही सकता। मेरा कहना यह है कि राजस्व की वसूली के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। हमारा यह प्रयत्न भी होना चाहिए कि जो खेतीबाड़ी पर कोई टैक्स है या इन्कम टैक्स है या कोई भी टैक्स दूसरा है, जिसकी वसूली होनी है, वे सब के सब पूरी तरह से वसूल किये जायें। सरकार का यह फर्ज है कि वह अपने विभागों द्वारा पूरे टैक्स वसूल करें क्योंकि सरकार को कोई दान तो दता नही ंहै, उल्टा सरकार ही दान या अनुदान के रूप में लोगों को देती हैं। इसी पैसे के द्वारा सरकार जो भी कार्यक्रम बनाती है, उनको चलाती है। मेरा कहना यह है कि राजस्व की वसूली की तरफ पूरा ध्यान रखना भी चाहिए और सरकार रखती भी है। बिक्री कर एक मामूली सी बात है जिसको बढ़ाया गया है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जो गरीब है, किसान है या दूसरे हैं, उनके कृशि उत्पादन पर जो टैक्स लगाया गया है, उसका बोझ किसान पर न पड़े बल्कि उसका बोझ अन्तिम नियतिक पर पड़े हमारी सरकार इ बात का पूरा ध्यान रखती आ रही है और आ ाा है भविश्य में भी ध्यान रखेगी। गरीब आदमियों का भला हो और उनका हित हो, उनका उत्पादन बढ़े, लेकिन उन पर टैक्स का

बोझ न बढ़े, इस बात को पूरी तरह से ध्यान मे ंरखा गया है। इसी प्रकार से बिक्री टैक्स के बारे में भी और दूसरी टैक्सों के बारे में भी सरकार पूरा ध्यान रख सकेगी, यह मुझे आ ाा है। कृशि तो हमारे प्रदे ा का ही नहीं बल्कि सारे दे ा का एक साधन ऐसा है जिससे हमारे दे ा ओर प्रदे ा के सारे धन्धे चलते हैं। सारे कार्यक्रम इसी पर चलते है। कृशि उत्पादन के लिए हरियाणा में भूमि तो बहुत अच्छी है और जो पहले ठीक नहीं थी, उसको अब उपजाऊ बनाने के लिए और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न किया गया है। जिस भूमि का उपयोग हो सकता था, उसका सदुपयोग किया गया है। जिस भूमि में जिस प्रकार कृशि उत्पादन हो सकता है, उसी प्रकार का करने ाक प्रयत्न किया गया है पहले तो एक एक वर्श में केवल एक एक फसल ही हुआ करती थी। कोई अगर ज्यादा से ज्यादा कर लेता था तो दो फसलें पैदा कर लेता था लेकिन अब तो एक साल में तीन तीन फसलें पैदा की जा रही है। जाहं पर पहले सिंचाई के साधन उपलब्ध नही ंथे वहां पर अब सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा रही है। पहले के मुकाबले में अनाज का उत्पादन बढ़ता जा रहा है और मैं यह चाहती हूं कि हमारा इस दि ाा में लगातार प्रयत्न चलता रहना चाहिए ताकि जितनी आबादी बढ़ रही है, कम से कम उसके लिए कुछ हद तक हम उत्पादन को बढ़ा तो सकें। हमारा हरियाणा प्रान्त दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में काफी सम्पन्न प्रान्त है। यहां पर कृशि और दूसरे धन्धे सभी अच्दी प्रकार से चल रहे हैं। हमारी यहां कोई भूखा नहीं है लेकिन फिर भी गरीबी बिल्कुल नहीं रही हो, ऐसी बात भी

नहीं है। लोगों को हर तरफ से सुखी बनाने के लिए और उनको रोजगार मुहैया करवाने के लिए ताकि उनको खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा मिले, कृशि बहुत जरूरी है और उसके लिये हमारी सरकार ने चहुंमुखी प्रगति प्रदे ा में करने की कोि ा ा की है। कृशि के विकास के लिए बीज अच्छे होने चाहिए। इसके लिए बीज निगम, हमारे इलाके में जैसे आलू की पैदावार लोग बहुत करते है, वहां पर आलू का बीज तैयार कैसे किया जाये, कैसे उसे बोया जाये, किस प्रकार से उसको उखाड़ा जाये और सिक प्राकर से उसको स्टोर करके रखा जाये, इन सब बातों के लिए बताती है। यह कारपोरे ान आलू का बीज ही नहीं, प्याज का बीज और लहसुन का बीज भी उपलब्ध करवा देती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि लोगों को यह मालूम होता है कि कौन सा बीज कब और किस समय बोना है जिससे उसकी पैदावार अच्छी होती है, प्याज अच्छा होता है लहसुन अच्छा होता है। चेयरमैन साहब, इसी तरह से गेंहू, जीरी के बोने काटने और रखने का सही तरीका लोगो को बताया जाता हैं। ये चीजे तो इतनी कौमन है कि हर किसान इनके बारे में जानता है ओर यह भी जानता है कि इनकी पैदावार किस तरीके से बढाई जा सकती हैं। बढिया से बढिया फर्टीलाईजर और कीटना ाक दवाईयो की जानकारी लोगों को दी जा रही हैं ताकि वे अपना उत्पादन अधिक कर सकें और अपनी आय को बढाकर अपने प्रदे ा और दे ा को समपनन बना सकें। चेयरमैन साहब, प्राकृतिक आपदाऔ की बात तो ऐसी हैं जेसे कहा जाता हैं कि हानि, लाभ जीवन, मरण, य ा

अपय ा प्रभु के हाथ में हैं। मनुश्य के हाथ में कुछ भी नही हैं। लेकिन यह सरकार लोगों की पूरी तरह से मदद करती हैं और सहायता सराहनीय और प्र ांसनीय हैं। कई दफा राजस्व की माफी की जाती हैं। यह बहुत अच्छी बात हैं। इससे किसानेां की हौसला अपजाई होती हैं। फसलों की बीमा योजना की भी बात की गई हैं। यह बहुत अच्छी बात हैं। इस योजना से किसानो को अच्छी मदद मिलेगी। अगर यह योजना चालू हो जाए तो किसानों की चिंता समाप्त हो जाएगी। हमारे दे ा की जो अर्थ वयवस्था ईं वह भी बहुत अच्छी हैं। पिछली खरीफ की फसल भी अच्छी रही। और अब रबी की फसल भी अच्छी रहेगी। तिल्हनों ओर दालों का जो कार्यक्रम चल रहा हैं। हमारे प्रदे ा के चीनी मिल अच्छे काम कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, हमारे प्रदे ा में सिचाई की योजनाए हैं वे काफी बडी़ हैं औरप उनसे लोग फायदा उठा रहे है। करनाल मे जो ट्यूबवैल हैं वे अच्छा काम कर रहे है लेकिन फिरप भी किसानो को बिजाई के समय कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं। सरकार को उसे दूर करना चाहिए। चेयरमैन साहब, हमारी सरकार किसाने की जमीन एक्वायर करती हैं। उन लोगों की जमीन काफी कीमती होती हैं। कभी कभी सरकार एक किसान की सारी जमीन एक्वायर कर लेती हैं। इससे किसानों को काफी परे ाानी होती है। उनके पास रोटी को कोई सहारा नही रहता। मेरा सरकार से कहना हैं कि जिन लोगों की सारी जमीन एक्वायर कर ली जाए उनको नौकरी में प्रोत्सानह दिया जाना चाहिए। उनको इण्डस्ट्री लगाने में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उनको

बचाने की बहुत आव यकता हैं। चेयरमैन साहब, प ा पालन के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा हैं। यह तो सभी जानते हैं कि हरियाणा में चाहे काफी तरक्की हुई हैं। फिर भी दूध की आव यकता पूरी करने के लिए अधिक प्रयत्न जरूरी है। मेरा कहना तो यही हैं कि प ापालन की दि ाा में अच्छा काम हो रहा हैं। लोगों को कर्जे मिल रह हैं और उनकी हर तरह से सहायता की जा रही हैं।(घंटी) चेयरमैन साहब, मै इन भाब्दो के साथ डिमाण्ड का समर्थन करती हूं।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल(मुढाल खुर्द): चेयरमैन साहब, मै डिमाण्ड चार और पन्द्रह पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझसे पहले चार माननीय सदस्य बोल चुके हैं और उन्होने कहा कि अपोजी ान के साथी तो केवल नुक्ता चीनी के लिए बोलते है। चेयरमैन साहब, इसमैं नुक्तचीनी की कोईबात नही हैं। चेयरमैन साहब, हम ता इनकी जय भी बोलने के लिए तैयार हैं अगर ये अच्छे काम करके दिखाए लेकिन ये तो कुछ काम करते ही नही। पिछले चुनाव में लोगों ने इनको रिजैक्ट कर दिया था। जिस स्टेट में पोलिटिकल सिस्टम खराब हो वहां पर आर्थिक डिवैलपमैंट या इकोनोमिक डिवैल्पमैंट नही हो सकती। पिछले मई के चुनाव में लोगा ने अपोजी ान की सरकार बनाने के लिए राय दी थी।

श्री सभापतिः आप डिमाण्ड पर बोले।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः चेयरमैन साहब, * * ** * * ** *

उधोगमंत्री (श्री लछमन सिंह): चेयरमैन साहब, ये पहली दफा चुनकर आए हैं इसलि इनको अभी पता नही हैं कि कैसे बोलना हैं। * * * * * यह रिकार्ड पर नही आना चाहिए।

श्री सभापतिः आप केवल डिमाण्ड पर ही बोले।

चोधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः चेयरमैन साहब, मै कह रहा था कि जिस प्रदे ा का पोलिटिकल सिस्टम या राजनैतिक व्यवस्था ठीन ने हो वहां इकौनोमिक डिवैल्पमैंट कैसे होगी? चेयरमैन साहब, गवर्नर ऐड्रस में किसानो को जो 170 करोड़ रूपए की फसल बरबाद हो गई थी उसका चौदह करोड़ रूपया किसानों को कम्पनसे ान देने की बात कही गई हैं लैकिन अफसोस के साथ कहना पडता हैं कि आज भी उस 14 करोड़ में से 64 लाख रूपया बकाया है क्योकि यह सरकार ब्यूरोकेसी बेस्ड हैं पिछले साल अप्रैल और मई में ओलो के कारण किसानो की फसल बरबाद हो गई लेकिन एक साल होने जा रहा हैं आज तक सब किसानों को मुआवजा नही दिया गया। बहन जी कह रही थी कि यह सरकार किसानों को मुआवजा नही दिया गया। बहन जी कह रही थी कि यह सरकार किसानों की हितैशी हैं। मै कहना चाहता हूं कि हितैशी हाती तो यह 64 लाख रूपया बकाया नही रहता। चेयरमैन साहब, जब हमारी सरकार थी ओर चौधरी देवी लाल चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होने चार सौ रूपया पर किल्ले के

हिसाब से कम्पन ोसन देने को प्रोवीजन किया था। उस वक्त फैसला किया था कि अगर किसी किसान का ओले से नुक्सान होता हैं तो उसको चार सौ रूपया फी किल्ला के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। आज उन बातो को चार साल हो गए ओर सब चीजो के रेट बढ गए। एम्पलाईज की तनखाह बढ गई, खाद का रेट बढ गया लेकिन किसान के मुआवजे का रेट नही बढा। चौधरी बीरेन्द्र सिह कहते हैं। कि हम तो चार सौ की जगह छः सौ रूपया देगें लेकिन ये सब कहने की ही बातें हें। आज तक किसान के मुआवजे का एक पैसा भी नही बढा। यह सरकार कहती हैं कि हम प्रो–किसान हैं। चेयरमैन साहब, आज ही अखबारो में आया हैं और केन्द्रीय सरकार ने कहा हैं कि हरियाणा खेतीबाड़ी पर पूरा ध्यान नही दे रही है। खेाती बाड़ी पर पूरा पैसा खर्च नही किया जा रहा हैं। चेयरमैन साहब, इस सरकार ने 33 करोड़ मे से बीस करोड रूपया भी खच्र नही किया लेकिन फिर भी यह सरकार अपने आपको प्रो–किसान सरकार कहती हैं। अभी मेरे भाईयो ने कहा कि यह सरकार खाद पर और बीज पर किसान को सबसिडी देती हैं। चेयरमैन साहब, हालात तो यह है कि इस सरकार ने आत ही खाद के भाव बढा दिए। चेयरमैन साहब, इस सरकार ने नैपथा फर्टीलाइजर के दाम बढाए और मै पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं मि दुनिया मे से से मंहगा खाद हिन्दूस्तान का किसान लगाता हैं लेकिन फिर भी यह सरकार कहती हैं कि यह प्रो–किसान सरकार हैं। चेयरमैन साहब, जहां तक इरीगें ान फैसिलिटीज का सम्बन्ध हैं आज भी ऐसो इलाके हैं जहां पर एम.

आई.टी.सी. ने बताया कि हमने 50 ट्यूबवैल लगा दिए लकिन उनमें से 12 ट्यूबवैल भी काम नही कर रहे हैं।

चेयरमैन साहब, बिजली के रेट पहले 1981 में बढे थे। जब झगड़े हुए तो चौधरी भजन लाल ने उनको ड्रोप कर दियां उसके बाद पिछले सितम्बर में फिर बढा दिये। पता नही यह सरकार वाले कैसे समझ गये कि किसानों की आमदनी बढ गई हैं या उनकी प्रोसपैरिटी बढ गई हैं। चेयरमैन साहब, आज हरियाणा की पर कैपिटा इंकम पहले से घटी हैं। आज से 4–5 साल पहले सारे दे ा मे हरियाणा दूसरे नम्बर पर था लेकिन आज सातवे नम्बर पर हें।

लोक स्वास्थय राज्य मंत्री (चौधरी लाल सिंह): चेयरमैन साहब, मैरा प्वायंट आफ आर्डर हैं * * * * * ** * वह कार्यवाही से काट दिया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये हरियाणा को सातवे नम्बर पर लाने लग रहे हैं जबकि हरियाणा तो एक नम्बर पर हैं।(ाोर)

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल: अब मै प ा पालन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस महकमे के हमारे बहुत योग्य मिनिस्टर हैं लेकिन आज भी 8–10 हजार की आबादी तक के ऐसे गांव है जहां पर कोई प ा हस्पताल नही हैं। प ाुधन भी किसानों के लिए उतना ही जरूरी हैं जितनी खेती की पैदावार। चार हजार से लेकर दस हजार तक की आबादी के आज भी काफी

गावं ऐसे हैं जिनमें ये पूरी सुविधाए नही दे पाएं जहां तक मैंडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात हैं आज भी दस–दस हतार की आबादी के गांव बगैर हस्पताल के है बल्कि कइयो में तो डिसपैसरी भी नही हैं। चौधरी भजन लाल जी भिवानी गये थे ओर इन्होने खुद माना था कि कुछ गावों को सड़क मिलनी चाहिए लेकिन आज तक कही पर भी एक छटांक मिट्टी भी डली हैं। जहां तक ऐजुके ान की बात हैं आज भी 15–15 हतार की आबादी के गांव ऐसे हैं जिनमें प्राइमरी स्कूल भी नही हैं। फिर ये कहते हैं कि हम डिवैल्पमैंट के काम कर रहे हैं। यह तो आपने नैचुरल क्लाइमिटीज का कम्पनसै ान देने के बारे प्रोवीजन रखा हैं, वह बहुत कम हैं। मेरा सुझाव है कि गवर्नमैंट किसान को 400–400 रूपए एकडत्र की बजाए 600 रूपये एकड़ के हिसाब से कम्पनसै ान दे ताकि बढते हुए भावें मे किसानो का भी गुजारा हो सके। इसके इलावा जो माइनर इरीगें ान की फैसिलिटीज हैं वह भी किसानो को दी जाए। लोग फैसिलिटी को भी आसान बनाया जाए ताकि उनको जल्दी लोन मिल सके।

17.00 बजें

चौधरी धीर पाल सिंह (बादली): चेयरमैन साहब, मै डिमाण्ड नम्बर 4, 15, 17 और 18 पर बोलूंगा। चेयरमैन साहब, मांग नम्बर 4 के जरिये हमारी सरकार की सूखे की राहत के लिए 11 करोड़ कुछ लाख रूपए अनुदान देने की स्कीम हैं। मै आपके माध्यम से सरकार से बताना चाहता हूं कि रोहतक जिले के साथ

राजनीतिक भावना से बर्ताव किया जा रहा हैं। उसे सिंफ 20 लाख रूपये का अनुदान दिया गया। चेयरमैन साहब, आप भी किसान हैं। किसानों का आह भरने वाली सरकार ने जनवरी के आखिरी हफते में बीज का अनुदान दिया। वह अनुदान किसानों के काम आने वाला नही था क्योंकि किसानों के पास इतनी भाक्ति नही थी कि उसको प्रयोग में ला सकते। किसान बेचारा सोसाईटियो के माध्यम से बीज और खाद लेता हैं। वह अनुदान जनवरी में दिया गया जबकि रोहतक ओर महेन्द्रगढ में तो नवम्बर के आखिर में बिजाई होती हैं। इस अनुदान के लिए सात जिले आत थें। हर जिले की 175 लाख रूपए की रे ाो बनती थी लेकिन रोहतक को सिर्फ 20 लाख रूपए दिये गये जोकि राजनैतिक भावना से दिये गए। जब चौधरी देवी लाल की सरकार थी तो उसने यह घोशणा की थी कि अगर किसी किसान की फसल जल जाती हैं तो उसको भी मुआवजा दिया जाएगा। एक गवाना गांव का करतार सिंह हैं उसकी 100 प्रति ात फसल जल गई लेकिन उसको आत तक पैसा नही मिला। इसी तरह से माजरी गांव का धर्म सिंह है उसकी फसल भी सारी की सारी नश्ट हो गई लेकिन उसको भी आज तक कोई मुआवजा नही मिला। इसके बाद मैं कनफैड के बारे कुद कहना चाहता हूं। जितनें भी कंज्यूमर स्टोर है वे सारे घाटे में चल रहे हैं। हर गांव में इन दुकानों के जरिये लोगों को राहत देने की जो चीज हैं वह हें चीनी। गेंहू, चावल, दाले और कपड़े का तो वहा नाम नि ाान ही नही हैं। बादली मे 12–13 हतार की आबादी हैं और वहां पर 50 प्रति ात नान–ऐगीकल्चरिस्टस रहते

हैं। बड़े दूख के साथ कहना पड़ता हैं कि वहां महीने में तीन दिन चीनी बंटती हैं। नौकरीयो के बारे में मै यह कहना चाहता हूं कि रोहतक सैंट्रल कोआप्रेटिव बैक में जनवरी 1982 में नियूक्तियां की गई। उनमें 50 प्रति ात चौधरी भजन लाल के आदमी नियूक्त किये गऐं। मै भी वही उस बैंक का डायरैक्टर था। इन्टरव्यू हुई और नियूक्ति का टाईम आया। उस समय वहा के एम.डी. को ट्रांसफर कर दिया गया और अपनी मर्जी का एम.डी. वहां पर लगा दिया जो बाहर से लोग थे उनको जानते थे। उनको लगाया गया। चेयरमैन साहब, इसके बाद आप खाद को ले लेजिए। किसान अपने खेतों में खाद इस आ ाा से डालते हैं कि उनकी फसल अच्छी हों। लेकिन उनको जो खाद मिलती हैं वह सारी मिलावट वाली मिलती हैं। उसको मु कल से एक कट्टा खाद को सोसाइटी से मिलता हैं लेकिन उसमे न तो नाईट्रोजन की भाक्ति होती हैं और नह दूसरी भाक्ति होती हैं। सारी मिलावट वाली मिलती है। इसी तरह से कीट ना ाक दवाइयो की बात हैं। उनमें भी मिट्टी और राख मिली हुई होती हैं। वे बेचारी कर्जा लेकर दवाईयां खरीदते हैं लेकिन वे उनके किसी काम नही आती। किसान लोग जो कीटना ाक दवाईया खरीदते हैं वह दवाई कोई काम नही करती हैं। चेयरमैन साहब, केन्द्रीय सरकार ने 1980 में हरियाणा सरकार को 55 करोड़ रूपए कृशि पर खर्च करने के लिए दिए थे लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता हैं कि यह सरकार उस पैसे को राहत देंगे और हर काम में किसानो को प्राथमिकता देगें। इसके अलावा चेयरमैन साहब, आपने आज

अखबार में भी पढा होगा। आज के अखबारेां में केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा सरकार को बुरी तरह लताड़ा हैं और कहा हैं कि जनता सरकारप के टाईम में हरियाणा ने जितनी कृशि की पैदावार की थी उसके मुकाबले मे इस समय की सरकार पैदावार नही कर सकी हैं। इसके अलावा मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि इस बजट में एस.वाई.एल. नहर की खुदाई के लिए पैसे का प्रावाधान नही किया गया है। यदि उस नहर की खुदाई के लिए पेसा नही दिया गया तो उसका काम अधूरा रह जाएगा। इसके अलावा मै एक बात अपने हल्के के बारे मे कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के में एक जाहगीरपुर ड्रेन हैं। उसका पानी निकालने के लिए 1953 से वहां पर इंजन लगाए गए थें वे सारे इन्जन वैसे ही पड़े हैं। उनसे कोई काम नही लिया जा रहा हैं और वे सारे खराब हो गए हैं। चेयरमैन साहब, आप भी किसान हैं हम भी किसान हैं इसलिए हमको किसानेा के दर्द का पता है। मै सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार उस ड्रेन की तरफ ध्यान दे। इन भाब्दो के साथ मै आपका धन्यावाद करता हूं औरप इन डिमाण्ड का विरोध करते हूये अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

मास्टर ि ाव प्र ाद (अम्बाला भाहर): चेयरमैन साहब, मै डिमांड 4, 15, 17, 18, 21 और 22 के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहले कोआप्रे ान की डिमांड के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे कोआप्रे ान मिनिस्टर साहब हाउस मे बैठे है। मै इनसे कहना

चाहता हूं कि यदि आप इस डिमांड में यह और लिख देते कि हमारे राजनैतिक लोगों में चरित्रा की कमी हैं तथा उसको कैसे दूर किया जाए, तो आपको उसमें सारी अपोजी ान का साथ मिल जाता हैं। यदि यह बात इस डिमांड मे लिख दी जाती तो इस बात का पता लगा सकता था कि कहा करप ान हैं ओर कहां बेइमानी हैं। चेयरमैन साहब, कहा जाता हैं कि अगर राजा ईमानदार होगा तो उसकी प्रजा बेईमानी नही हो सकती और राजा बेईमान होगा तो प्रजा ईमानदार नही रह सकती। आज के युग में ऐसे राजा हो गए हैं जो राजनैतिक भ्रश्टाचार और बेइमानी में वि वास रखते हैं।(ाोर एव विघ्न)

श्री सभापतिः आप कृपया डिंमाड पर बोले।(ाोर एव विघ्न)

मास्टर ि ाव प्र ाद (अम्बाला भाहर): चेयरमैन साहब, कोआप्रेटिव सोसइटीज की तरफ से या कोउाप्रे ान डिपार्टमैंट की तरफ से जितनी भी दुकाने और कोआप्रेटिव स्टोर हरियाणा के अन्दर खोले गए है उनमें से एक भी दुकान या कोआप्रेटिव स्टोर मुनाफे मे नही चल रहा हैं सारे घाटे मे चल रहे हैं। एक प्राईवेट दुकानदार अपनी छोटी सी दुकान में अपने परिवार को और दुकान का खर्चा निकाल कर मुनाफा कमा लेता हैं। यदि प्राइमरी दुकारदार अपनी दुकान का और परिवार का खर्चा निकाल कर मुनाफा कमा लेता हैं तो गवर्नमैंट की तरफ से जितने कोआप्रेटिव स्टोर्ज या मिनी बाजार खोले गए हैं वे मुनाफे में क्यो नही चल

रहे हैं इसका क्या कारण हैं? एक भी सरकारी दुकान ऐसी नही हैं जो मुनाफे में चल रही हो। इसी प्रकार से डेरी डिवैल्पमैंट कारपोरे ान के मिल्क प्लांट है वे भी घाटे मे चल रहे हैं लगभग सारी कारपोरे ान घाटे मे चल रही हैं। चेयरमैन साहब, आज मुख्यमंत्री जी ने भी यह बात मानी हें कि हिसान कनकास्ट लिमिटिड पहले हर महीने लगभग 15–16 लाख रूपये घाटे में चल रही थी लेकिन अब वह 6–7 लाख रूपए घाटे मे चल रही हैं। चेयरमैन साहब, मै सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जितनी कारपोरे ान घाटे में चल रही है उनका क्या कारण हैं? घाटे का कारण कही यह तो नही कि इन कारपोरे ान में कही न कहीं भ्रश्टाचार हो रहा हो? चेयरमैन साहब, हमारे हरियाणा प्रान्त में जितनी भी कारपोरे ान हैं वे तमाम घाटे मे चल रही हैं और घाटे में इसलिए चल रही हैं क्योकि उनमे कही न कही भ्रश्टाचार पनप रहा हैं।

अम्बाला चेयरमैन साहब, मै यह भी कहना चाहता हूं कि चुनावों मे पहले अम्बाला भाहर की मार्किट कमेटी के सैक्रेटरी की बदली कर दी गई थी जबकि उसको अम्बाला भाहर में आए हुए केवल 3–4 महीने ही हुए थें। उस सैक्रेटरी के खिलाफ न वहां के लोगों की तरफ से कोई ि ाकायत थी ओर न ही वहा के स्थानिय एम.एल.ए. की तरफ से कोई ि ाकायत थी फिर भी उसका अम्बाला भाहर से ट्रांसफर कर दिया गया। यदि किसी कर्मचारी को एक जगह पर तीन साल का अर्सा हो जाता है तो उसका ट्रांसफर

हो सकता हैं लेकिन उसको केवल तीन महीने के बाद ही वहा से बदल दिया गया। जब मैंने उसके ट्रांसफर के बारे में मार्किट कमेटी के चेयरमैन साहब, से बात की तो उसका ट्रांसफर रोक दिया गया। इस किस्म की बातें हो रही है। उस ट्रासफर के पिछे कोई न कोई भ्रश्टाचार का उदे ाय भी हो सकता हैं। मैने उस सैक्रेटरी के बारे मे चेयरमैन साहब, से कहा कि आप इसका ट्रांसफर क्यो कर रहे है? इसको तो अभी केवल 3–4 महीने ही हुए हैं, यह बहुत अच्छा आदमी हैं इसको यही पर रहने दिया जाए। उसके बाद उसका ट्रांसफर रोक दिया गया। चेयरमैन साहब, इस तरह से यदि किसी का ट्रांसफर करना हो तो इसका मतलग यह हुआ कि उसके ट्रांसफर की पीछे भ्रश्टाचार का कोई उदे य हो सकता हैं।(ाोर एव विघ्न) जिस समय हमारी सरकार थी, उस समय हमने किसानेां को खाद का एक कट्टा 70 रूपये में दिया था। आज की सरकार किस भाव पर दे रही है, यह आपको ही पता होगा। हमारी सरकार ने समुदायिक विकास के लिए काम किया था। जिस समय हमारी सरकार थी उस समय हमने जो कर्मचारी म्यूनिसिपल कमेटियो मे काम करते हैं उनके 50 रूपये प्रतिमास के हिसाब से बढाए थे। इसी प्रकार से जो व्यक्ति सड़को पर काम करते हैं उनके वेतन बढाए थें। हरिजनो के लिए बाकायदा चौपाले बनानी भाुरू किया था। मै पूछना चाहता हूं कि आज की सरकार क्या कर रही है? जैसा मै पहले कह चुका हूं कि यदि यह सरकार भ्रश्टाचार को कम करने और क्रप ान को खत्म करने और राजनैतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए काम करे तो

बात समझ मे आ सकती हैं। मै मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि अम्बाला भाहर में एक अस्पताल बन रहा हैं। उस में पानी की टूंटिया लगनी हैं ओर ये टूंटिया पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट द्वारा लगायी जानी हैं। इनका ठेका लाल सिंह के लड़के को तीन लाख रूपये का दिया गया हें। (ोम– ोम की आवाजे) चौधरी भजन लाल जी तो सूझ–बूझ वाले हैं लेकिन ये भी अब काफी परे ाानी महसूस कर रहे हैं। ये 36 एम.एल.एज. चुनकर आए थें। * * * ** (ाोर) यह इनकी नोलेज मे हैं।(ाोर)

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): चेयरमैन साहब, इनहोने * * * * * जो बात कही है वह रिकार्ड से ऐक्सपंज होनी चाहिए।

श्री सभापतिः यह जो बात कही गई हैं उसे ऐक्सपंज कर दिया जाए।

मास्टर ि ाव प्र ाादः चेयरमैन साहब, मै कोई नाजायज बात नही कर रहा। हरियाणा के एक बड़े मिनिस्टर के लड़के के विरूद्व 10 लाख रूपये का गबन पाया गया हैं। यह केस सैन्ट्रल गवर्नमैंट की तरफ से रजिस्टर किया गया हें। भाायद मुख्य मंत्री जी, को इस केस का पता हैं। ये पता नही क्यो ऐक ान नही ले रहे? इन की अब मु ि कल हैं। आज हरियाणा में भ्रश्टाचार प्रतिदिन बढता जा रहा हैं यदि ये सही ढंग से काम करे तो इनको आज हरियाणा के अन्दर किसी नए टैक्स लगाने की आव यता नही थी। हरियाणा के डिवैल्पमैंट के कोई भी काम नही हो पा रहे

। * * * * इनका एक पैर चण्डीगढ रहता हैं और एक पैर दिल्ली में रहता है।

श्री सभापतिः माता और भाई वाली बात एक्सपंज कर दिया जाये।

मास्टर ि ाव प्र ाादः चेयरमैन साहब, यदि चौधरी भजन लाल सही काम करें तो हरियाणा दे ा के नक्े पर सबसे ऊपर हो सकता हैं। आज हरियाणा भ्रश्टाचार के मामले में और बदनामी की वजह से बहुत बदनाम हो चुका हैं। (ाोर)

सहकारिता मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह): चेयरमैन साहब, आज विभिन्न मांगो पर आनरेबल साथियो ने चर्चा की। को–आप्रेटिव महकमे के बारे मे चौधरी साहब सिंह सैनी, प्रो. समप्त सिंह, श्रीमति करतार देवी, चौ. बलबीर सिंह, मास्टर ि ाव प्रसाद और चौ. धीरपाल जी ने विभिन्न मुददो ओर कारगुतारियो के बारे में काफी चर्चा की हैं। मास्टर ि ाव प्रसाद जी एक बात भूल गए। इन्होने कहा कि मुख्य मंत्री जी, ने यह माना हैं कि कानकास्ट कम्पनी घाटे में चल रही हैं। चेयरमैन साहब, कोई संसथा और गवर्नमैंट की क्या मं ाा हें कि ऐसे संस्थानो के जरिये ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। बहन करतार देवी ने सही भाब्दों में व्याख्या की हैं कि सामूहिक तौर पर जो काम करना होता हैं उसी को सही मायनों में कोआप्रेटिव कहा जा सकता हैं जिस समाजवाद की नीव प. जवाहर लाल नेहरू ने रखी

थी और अब श्रीमती इन्दिरा गांधी जिस पथ पर चल रही हैं उसका सही मायना यही है। कि पब्लिक सैक्टर में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धन्धे चल रही हैं उसका सही मायना यही हैं कि पब्लिका सैक्टर में ज्यादा से ज्यादा उदयोग धन्धे लगाये जाऐं ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लेकिन जो भाशण इन्होने अभी दिया हैं उसमें समाजवाद की कोई चीज नही हैं। यह चाहते है कि हमारी सरकार को और चौधरी भजन लाल जी का यह पक्का इरादा हैं कि चाहे वह टैनरीज हैं या कानकास्ट या दूसरी कार्पोरे ान यदि वे घाटे मे भी हैं तो भी उन्हे जारी रखा जाये। आज की सरकार सारी पूंजी को एक पूजीपति के हाथ में जाने नही दे रही। (ाोर) भाई बलबीर सिंह जी दल–बदल की बात कह रहे थें मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिस समय चुनाव लड़कर आये थें उस समय आप कौन से लोकदल के थें। अब आप बताइए कि आप कर्पूरी ठाकुर ग्रुप लोकदल के थे या चरण सिंह ग्रुप लोकदल के थे? यदि कोई दल–बदल है तो यही सबसे बड़े दल बदल के लोग हैं। चेयरमैन साहब, मै एक बात बताना चाहता हूं कि लोकदल दिल्ली के अन्दर बी.जे.पी. के साथ चुनावो के दोरान समझौता करता हैं। यानि पूजीपतियों के साथ समझोता करता है। अब ये यहां पर किसानों के हमदर्द बन रहे हैं। (ाोर)

Sh. Mangal Sein: Sir, I strongly refute the charge. BJP never belonged to capitalsts. Instead they belong to capitalists. They dance at the tuen of capitalists.

Sh. Hira Nand Arya: They are teh agents of the capitalists.

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायंअ आफ आर्डर सर। इनकी कांग्रेस पार्टी के असली मैम्बर तो सिर्फ तीन या चार ही हैं।(ाोर)

राजस्व मंत्री (चौधरी फूल चन्द मुलाना): आन ए प्वायंअ आफ आर्डर सर। चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंअ आफ आर्डर एक भोयर की भाकल में हैं:—

वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नही होता,

हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हें बदनाम।

जब भी हम बोलना भाुरू करते हैं तो ये बीच मे रूकावट डालते हैं। हमारी बात सुनते ही नही हैं, जब भी बोलते हैं तो सिर्फ हमारी पार्टी की ही बात करते हैं।(ाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): चेयरमैन साहब, मेहरबानी करके आप इनको बैठा दीजिए। जब हम बोलते है तो ये भाोर मचाने लग जातें हैं। आप इन्हे बैठने के लिए कह दे।(ाोर)

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

राव निहाल सिंह: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। चौधरी भजन लाल जी की सरकार सर्वदलीय सरकार

हैं। इसमे लेाकदल के मैंम्बर भी भामिल हैं। हमारी पार्टी के भी भाामिल हैं और स्वतंत्र पार्टी के मैंब्र भी भाामिल हैं।(ाोर)

चौधरी भजन लालः राव साहब, आप बैठे बैठे दुखी हो गए। आप वहा से इधर ही आ जाएं तो ठीक हैं।

श्री मनफूल सिंहः स्पीकर साहब, आपके आने से पहले रैवेन्यू मिनिस्टर साहब ने एक भोयर की भाक्ल में प्वायंट आफ आर्डर किया था। उसी भाक्ल में मेरा भी प्वायंट आफ आर्डर हैं।

इमारत बनाने वाले इमारत बना बहरेतला ताल पर,

किनारों पर मत बना अक्सर डूब जाते हैं।(हंसी एव भाोर)

चोधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि हमारे साथी श्री साहिब सिंह सैनी ने हरियाणा स्टेट लैंड डिवैल्पमैंट बैंक के बारे में चर्चा की कि पिछले साल इस बैंक के द्वारा 36 करोड रूपये से ज्यादा विभिन्न मदों के लिए कर्जे तकसीम किए गए। इसी तरह दूसरे लोगों को भी तकसीम किये गयें और अब की बार सिर्फ 11 करोड रूपए ही बांट सके हैं। भाायद मेरे लायक दोस्त को पूरी फिगरप का पता नही हैं। मै उन्हे सकी फिगर बातना चाहता हूं। हमने पिछले साल 1981–82 में 36 करोड़ नही बल्कि 46 करोड़ रूपये किसानों को ट्रैक्टर के लिए, टयूबवैल के लिए, स्प्रिकलर्ज–सैट लगाने के लिए और मिनी डैरी लगाने के लिए कर्जे दिये और इस साल 1982–83 में 11

करोड़ नही बल्कि 17 करोड़ के करीब बांट चुके हैं। इस बार अगले साल के लिए जो हमारा टार्गेट हैं वह भी हम जरूर पूरा करेगें। इसके साथ ही साथ मैं सदस्यो को यह भी बताना चाहता हूं कि भिवानी और महेंन्द्रगढ जिलों में जहां स्प्रिकलर्जसैट लगाकर किसान अपनी खेती पैदा करता हैं वहा हमने हिदायत दी हैं कि कोई भी किसान जो स्प्रिकलर्जसैट लगाने के लिए कर्जा लेना चाहता हैं। उसको कर्जा दे दिया जाए और इस कर्जे का भूगतान जल्दी किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इन्होने श्री धर्मवीर हुड्डा, जो मिनी बैंक मैनेजर थे, के बारे में चर्चा की कि वे कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी मे ि ाक्षा ग्रहण करते रहे ओर उनहोन कुछ गड़बड़ की। मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि यह बात महकमें के नोटिस में पहली बार आई। कुछ लोग कुरूक्षेत्र में 13.09.1982 को और 15.09.1982 को मिले। जब हमें यह ज्ञात हुआ तो हमने उस कर्मचारी को ससपैंड किया और इसके बाद उसने अपना रैजिगनै ान महकमे को दिया। इसके खिलाफ इन्कवायरी हुई ।(व्यवधान)

चौधरी साहब सिंह सैनीः वह तो आपकी नौकरी छोड़ कर चला गया हैं भाायद मंत्री महोदय को इस बात का पता नही है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरे साथी श्री साहब सिंह सैनी और प्रोफैसर सम्पत सिंह जी ने किसानों को सस्ते बीज और कर्जे देने की बात कही और यहां

तक कह दिया कि किसानों के ऊपर जो कर्जे हैं वे मुआफ करने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सदन को एक बात बताते हूए खु ाी महसूस कर रहा हूं । जब नई विधान सभा का गठन हुआ और मुख्य मंत्री जी, ने स्टेट की बागडोर सम्भाली, उस समय किसान से भीर्ट टम्ज्र लोन पर साढे 12 परसैन्ट के हिसाब से ब्याज लिया जाता था लेकिन सारे हिन्दुस्तान के अन्दर हमारे मुख्य मंत्री जी, पहले मुख्य मंत्री है जिन्होने भौर्ट टर्म्ज लोन के रूप में 140 करोड़ रूपये के लगभग किसानों मे बांटा और साढे 12 परसैन्ट ब्याज की दर को घटाकर 11 परसैन्ट किया।(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इन्होने तो 14 परसैंट कर दिया था लेकिन यह जनता गवर्नमैंट ही थी जिसने 14 परसैन्ट से घटाकर साढे 12 परसेंट किया था।(व्यवधान)

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, साढे 12 परसैन्ट ब्याज को घटाकर 11 परसैंट उस वक्त किया था जब रिर्जव बैंक आफ इन्डिया और कमर्ि ायल बैंक ने ब्याज के रेट्स डेढ परसैंट बढा दिये थे। इसका मतलब यह हुआ कि डेढ परसैंट की बैंक की बढोतरी को रोका और डेढ परसैंट हमने ब्याज घटा दिया, यानी 3 परसैंट की छूट किसान को दी गई।(तालियां) इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय मै प्रोफेसर सम्पत सिंह को और बता देना चाहता हूं कि इन्होने लोकदल के लीडर चौधरी चरण सिंह की तरह चौधरी छोटू राम जी का नाम लिया और कहा कि किसानो के लिये कुछ किया जाए। लौकदल (सी) मी तरह प्रोफेसर सम्पत सिंह

ने पूजीपतियों के साथ समझोता नही किया, लेकिन यह फैक्ट है कि उन्होने दिल्ली के इलैक ान मे पूजीपतियों के साथ समझौता किया और वोट के लिए घर घर जाते रहें। (व्यवधान)

श्री मंगल सैनः अगर इनको ब्रहाचारी का हवाई जहाज न मिलता ******तो ये यहां न बैठते। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावतीः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, ये पूंजीपतियों की बात कह रहे हैं। आज कांग्रेस से ज्यादा पूंजीपतियों की रखवाली करने वाली दूसरी कोई जमात हो नही सकती जिसके राज में लिविंग स्टैडर्ड में 1 औरी 4000 रूपये का फर्क हैं। मंत्री जी को पार्टी की बात नही करनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः इन्होने जो गवर्नर साहब का नाम लिया हैं, इसको ऐक्सपंज कर दिया जाए।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, अगर मैं कोई बात कहूं और उसके तथ्य मेरे पास न हो तो भाोभा नही देता। प्रोफैसर सम्पत सिंह और साहब सिंह ने कहा कि हरियाणा कोआप्रेटिव भूगर मिले आज घाटे में चल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मै सारे सदन को बताना चाहता हूं कि ऐग्रीकलचर प्राईस कमी ान ने हरियाणा सरकार को हिदायत दी हैं कि गन्ने का भाव साढे 13 रूपये किंवटल दिया जाए। इस सिलसिले मे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में, सब प्राईवैट और कोआप्रेटिव भूगर मिल्ज के प्रतिनिधियो की मीटिंग

हुई और उस मिंटीग मे फैसला किया गया कि किसान को श्री भजन लाल की सरकार और श्रीमती इंदिश्रा गांधी की सरकार 20 रूपये क्विंटल से कम का भाव नही देगी। (तालियां)(श्रीमती चन्द्रावती की तरफ इ ाारा करते हुए) बहनजी, यह सरकार आपकी सरकार ती तरह नही हैं, जिस जनता सरकार की आप प्रधान थी। उस वक्त आप कुद कहती थी, चौधरी देवी लाल कुछ कहता था और डा. मंगल सैन कुछ कहते थें।(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, अगर इन्होने पार्टी की ही बात कहनी हैं तो हम भी पार्टी की बात कर लेते हैं।(व्यवधान)

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपको सबमिट करना चाहता हूं कि जब से कोआप्रेटिव भाुगर मिल्ज हरियाणा मे लगे हैं तब से हरियाणा के किसान की आर्थिक अवस्था में सुधार हुआ हैं और इन भाुगर मिलों को 22 करोड़ रूपया सेव किया जा सकता था। अध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा लगाए कि समाजवादी ढांचे के अन्दर हरियाणा सरकार ने जो नीति अपनाई हैं उसके मुताबिक सरकार ने किसान को 22 करेाड़ रूपया फालतू दिया और स्वयं घाटा उठा लिया। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी प्रो. सम्पत सिंह ने सिलैक ान के बारे में, एक और साथी ने रोहतक के बैंक बारे में कहा कि इसमे बि नोइयो का लगाया जा रहा है। इन्होने किसी खास जात बिरादरी की बात की थी। अध्यक्ष महोदय, आप जिस जिले से ताल्लुक रखते हैं, उस में सरकार ने पिछले दिनों भर्ती की है। आप बे ाक रिकार्ड चैक कर सकते हैं हरिजनो का,

बैकवर्ड क्लासिज का और एक्स–सर्विस मैंन का सारे का सारा कोटा पूरा किया हैं। यह बिल्कूल गलत बात हैं कि किसी खास बिरादरी को तरजीह दी गई हें। सन 1975 से पहले मिनि बैंक सैक्रेटरीज का कौमन केडर नही था। हर सोसाइटी के इम्पलाइज अलग से होते थें, उस टाईम पर सोसाइटीज भी पांच छः हजार के करीब थी लेकिन अब दो हतार हैं। कौमन केडर बनने के प चात किसी वि ोश जाति के लोगों को भर्ती नही किया गया। किसी खास जाट, सैनी या अन्य को नही लगाया गया है। जिसकी जितनी रिजर्वे ान बनती हैं उसी के हिसाब से भर्ती की जाती है। हरिजनो को पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया हैं।

श्री भागी रामः मंत्री महोदय ने बताया कि रिजर्वे ान का पूरा ख्याल रखा जाता हें। मेरे क्वै चन का जवाब देते हुंए मुख्य मंत्री जी, ने आ वासन दिया था कि नवम्बर में जो इन्टरव्यू होगा उस समय हरिजन जाति के कैडीडैटस लिए जाएगें लेकिन आपको यह जान कर हैरानी होगी कि उस समय बी.कौम. और फर्स्ट डिवीजन ग्रेजुएटस लड़के आये लेकिन उन में से एक भी लडका सिलेक्ट नही किया गया। जिन लडकों ने इन्टरव्यू नही दिया था उन्हे सिलैक्ट कर लिया गया।।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इनके बारे में मै भी बताऊ कि यह हरिजनो के कितने हमदर्द हैं। इनकी ही मिसला देना चाहता हूं। आज से चार दिन पहले मेरे पास आये और कहने लगे कि लैन्ड मार्गेज बैंक इन्टरव्यू हुआ हैं। उसमें मेरा भी एक

लडकां एल.बी.ओ. के लिए कैन्डीडेट हैं उसे आप सिलैक्ट करवा देना। मैने कहा कि हरिजन लड़के का आप नाम दे देना लेकिन इन्होने कहा कि हरिजन का तो नही दूसरी जाति का हैं। आप इस बात से अन्दाजा लगाये कि ये कितने हरिजनो के हमदर्द है।

श्री भागी रामः मैने कभी यह नही कहा कि मेरे किसी लड़के को आप सिलैक्ट कर देना। दूसरी चौधरी बीरेन्द्र सिंह के हाथ मे भी क्या हैं जो इन्हे कहता कि सिलैक्ट कर देना। वह तो चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यहा कान्फैड के बारे में भी चर्चा की गई। इन्होने कहा कि कान्फैड की रिटेल आउटलैटस पूरा सामान वहा नही पहुंचा पायी। स्पीकर साहब, कान्फैड का इतना बड़ा इनफ्रास्ट्रक्चर हैं कि गावं की आबादी दो हजार या दो हजार से ऊपर हैं, उस हर गांव में जरूरियाते जिन्दगी की चीजे मुहैया करी हैं। तीन साल से हम प्रयत्न कर रहे हें कि हर गांव में आम जरूरत की चीज पंहुचे लेकिन इनकी बायबिलिटी में कुछ समय लगेंगो। पिछले साल 15 करोड़ रूपये की असैि ायल कमोडिटीज दूर–दराज इलाको में पहुंचायी हैं। कानफैड मे एफीसिएन्सी लाने के लिए स्टाफ भी कम किया हैं लेकिन जब हम स्टाफ कम करने की बात करते हैं। हमने 450 ऐडहाम इम्पलाईज को सर्विस से निकाला हैं। पहले दस लाख का घाटा होता था लेकिन अब पिछले महीने से घाटा नीचे आ गया हे। 6–7 लाख का घाटा आ गया है। इसलिए मै हाउस को यकीन

दिलाना चाहता हूं कि कानफैड किी रिटेल आउटलैटस पर जरूरियाते जिन्दगी की चीजे अधिक मात्रा मे मुहेया की जाऐगी।

स्पीकर साहब, एक ओर बात हैं ओर भी ध्यान दिलया गयय कि डेरी डिवैल्पमैंट फैडरे ान ठोस से काम नही कर रही। आप्रे ान फल्ड–2 मे हरियाणा सरकार की डेरी डिवैल्पमैंट फैडरे ान को 33 करोड रूपया मिलने जा रहा हैं। आज जहां हमारी दो लाख 20 हजार लीटरप मिल्क प्लांटस की कैपसीटी है वह अगले 6 सालों में 8 लाख लीटर कैपसिटी हो जाएगी। जब इतनी मात्रा में दूध मिलने लगेगा तो किसानेा और गरीब लोगो की हालत मे भी सुधार हो जाएगा। हमारे हरियाणा प्रदे ा मे सारे दे ा का 1/8 हिस्सा दूध होता हैं लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी हैं कि जब तक हम अपने घर पर दूध का इस्तेमाल न कर ले दूसरे को बेचना पसन्द नही करतें। डैरी डिवैल्पमैंट फैडरे ान का विकास करने की हम पूरी कोि ा ा करेगें ताकि गरीब किसानों और गरीब आदमियों को अधिक से अधिक लाभ हो सके और उनकी आर्थिक अवस्था मे भी सूधार हो सके। इन भाब्दो के साथ मै सदन से दरखास्त करूगां कि कोआप्रटिव की डिमान्डज को सर्वसम्मती से पास किया जाये।

कृशि मंत्री(चौधरी सुरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, खेती बाडी के महकमे के बारे में चौधरी सम्पत सिंह जी और चोधरी साहब सिंह सैनी ने विचार रखे। वे अपनी तकरीर के दोरान कुछ बाते सरकार के नोटिस मे लेकर आये हैं। उन्होने यह भी कहा हैं

कि एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट मे कई किस्म के घपले हैं। ऐग्रोइन्डस्ट्रीज कारपोरे ान का भी चर्चा किया। चौधरी सम्पत सिंह जी ने आज अखबार का हवाला दिया। आज सुबह जब मैं दिल्ली से आ रहा था तो खु ाकिस्मती से पानीपत में मैने भी उस अखबार को खरीद लिया। मैंने भी उस अखबार को पढा है क्योकि मुझे भी बड़ी क्यूरोसिटी थी कि उसमे एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के बारे मे जो चर्चा किया गया उसे देखू। लेकिन बेहतर यह होता कि लिखने वाला हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट से फैक्टस एण्ड फिगर्ज ले कर और अपनी तसल्ली करे लिखता। लेकिन उसने बिना तसल्ली के ही आकंडें दिये हैं। मै मानता हूं कि सन् 1978–79 में हरियाणा मे 63 लाख टन से ज्यादा अनाज का उत्पादन हुआ हैं। अगर इस बात को क्रडिट आपकी सरकार का यानपी जनता सरकार को हैं तेा बड़ी अच्छी बात हैं। मै इस बात को मानता हू कि आपकी सरकार ने अच्छा किया होगा लैकिन आपको यह नही भूलना चाहिए कि सन 1978–79 की बिजाई सन 1977 में हुई होगी। अगर आपने किसानो की भलाई के लिए अच्छा कदम उठाया होता तो चौधरी सम्पत सिंह जी सदन मे इस बात की चर्चा न करते। मै भाई सम्पत सिंह की इतलाह के लिए बताऊ कि जिन जिन बातो में गड़बड़ हुई है वही घोटाले पे ा कर पाये हैं। वास्तव मे इन तमाम बातों का सम्बन्ध चौधरी सम्पत सिंह जी से तो नही है लेकिन उन व्यक्तियों से जरूर हैं जो इस सदन मे यहां या वहां बैठे रहे हैं। चौधरी सम्पत सिंह जी ने कहा कि हरियाणा में सन् 1978–79 के बाद रिकार्ड फसल नही हुई।

स्पीकर साहब, मै सन् 1979–80, 1980–81 और 1981–82 की खरीफ की और रबी की फसल का भी चर्चा करूंगा क्योकि 15 जुलाई और 15 अगस्त से न पहले और न बाद मे बारि ा हुई। हमे मानसून ने बडा़ धोखा दिया। ये कहते हैं कि गवर्नमैंट के टाईम पर रिकार्ड फसल हुठ थी। सन् 1978–79 में 63.10 लाख टन पैदावार हुई लेकिन हमारे समय ड्राउट कन्डी ान में 64 लाख टन अनाज पैदा हुआ। (तालियां) अध्यक्ष महोदय, मै यह तसलीक करता हूं कि हमारा टारगेट पूरा नही हुआ लेकिन इन के टाईम से तो कभी भी कोई टारगेट पूरा ही नही हुआ। सन् 1978–79 में पानी की हालत अच्छी थी। पानी की हालत अच्छी होने के बारे मे सरकार का कोई कन्ट्रीब्यू ान नही होता। अगर गोबिन्द सागर में पूरा पानी नही आएगा तो बिजली नही मिलेगी ओर नहरो में पूरा पानी नही आ सकेगा। जब बारि ा न होने पर सरकार क्या करती हैं? भाई सम्पत सिंह जी ने अखबार का भी चच्र किया लेकिन जिस भाई ने अखबार वाले को खबर दी, उसका नाम मै नही लेना चाहता। वह सरकारी अफसर दिल्ली मे है या यहा का कोई दूसरा आदमी हैं छठी पंचवर्शीय योजना मे कृशि विभाग को 110 करोड़ रूपया अलौट हुआ लेकिन उन्होने कहा है कि 55 करोड़ मे से 22 करोड़ रूपया ही खर्च हुआ हैं। स्पीकर साहब, आपको पता है क्योंकि आप भी कृशि मंत्री रपहे हैं। इस विभाग में पांच विग और भी हैं जिनमे पैसा जाता हैं। मै सदन की इतलाह के लिए बताऊ कि हमने 55 और 60 करोड़ रूपया खर्च किया हैं।

स्पीकर साहब, वन विभाग के विशय मे कहा गया कि वहां पर भी पैसा खर्च नही किया गया। मै उनकी इतलाह के लिए बताऊ कि हरियाणा मे सन् 1980–81 में डेढ करोड़ सन् 1981–82 मै 6 करोड़ सन् 1982–83 में 8 करोड़ पौधो की प्लान्टे ान हुई हैं और सन् 1983–84 में दस करोड़ पौधे लगाये जायेगे। अपोजी ान के भाईयो को यह भी मालूम होना चाहिए कि फोरैस्टरी के लिए पैसा हम अपने दम पर ले कर आये हैं। वर्ल्ड बैंक वालो ने कहा है कि अगर किसी स्टेट ने वनो का काम देखना है तो हरियाणा प्रान्त मे जाकर देखें।

श्री हरि चन्द हुडडा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। अभी मेरे दोस्त मंत्री महोदया एक बात कह रहे थे।(व्यवधान व भाोर) मै एक बात कह लूं। दरअसल 1978 से पहले सारे हिन्दूस्तान मे कृशि पर साढे सतारह परसैंट से ज्यादा खच्र ही नही हुआ। 1979 मे साढे सैंतीस परसैंट विधान के मुताबिक खर्च किया गया है। यह जो करोड़ो रूपए का अनुमान लगा रहे है यह 1978 मे केवल साढे सतारह परसैंट था ओर 1979 मे उसके बाद साढे सैंतीस परसैंट आया था। यह जो कुछ कह रहे हैं यह गलत कह रहे हैं।(व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नही हैं।(व्यवधान व भाोर)

श्री हीरा नन्द आर्यः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, मंत्री महोदय यह बताए कि क्या 20 करोड़ रूपया जंगलात महकमे न भिवानी जिले में खर्च किया हैं? जो मुख्य मंत्री जी, के चहेते इस फारैस्ट डिवैल्पमैंट बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हे। यह रूपया उनके हवाल कर दिया जाता हैं, क्या यह बात ठीक हैं?

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, सदन में एक बात कही गई। हरियाणा प्रान्त मे बैकवर्ड एरियाज हैं, महेन्द्रगढ जिला, भिवानी जिला, गुड़गाव जिला, हिसार जिला, सिरसा जिले का कुछ इलाका और रोहतक जिले का झज्जर और नाहड़ का इलाका। यहां पर इस बात की चर्चा की गई कि इन इलाको के लिए कृशि विभाग ने कोइ काम नही किया। मैं आपके जरिये से अध्यक्ष महोदय, सदन को यह बताना चाहता हूं कि पिछले सालो में जब चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी भी मैम्बर थे, चोधरी कंवल सिंह भी मैंम्बर थे, उस वक्त की फिगर्ज निकाल लिजिए। (व्यवधान व भाोर) 33 लाख रूपये की सबसीडी कृशि विभाग ने स्पिंलर्ज के लिए दी थी और केवल साढे पांच सौ स्पिंकलर्ज की प्रोपोजल थी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने यह महसूस किया कि वास्तव में बैकवर्ड एरियाज के लिए जां पर पानी लिफट इरेगें ान स्कीम होने के बावजूद कई जगह नही पहुंच पाता, क्योकि वहा पर ऊंचा लेवल हैं, इनके 33 लाख के मुकाबले मे 2 करोड़ 21 लाख रूपये की सबसीडी दी ओर 2800 स्प्रिंजलर्ज के लिए दी। मेरी इस बात

को तसलीम तो यह भी करते हैं ऊपर से चाहे जो कुछ भी कहते रहे। सबसीडी के बारे मे अध्यक्ष महोदय, मे यह भी बता दूं कि कहा कहा पर मिलती हें। फर्टीलाइर्ज पर और वगैरा पर देते हैं। 20 करोड़ रूपया फौरेस्ट्री के लिए कही नही दिया जाता हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं आपको फिगर्ज दे तो आप देखेगे कि आज तक इस सकरार ने किसानो के लिए जो कुछ किया हैं। वह मेरे विरोधी भाईयों की जब सरकार थी जब ये लोग सता में थे। तो कभी नही किया गया था। साहब सिंह जी ने वीडीसाइडज के बारे में एक कम्पलेंट की। 3–4 रोज पहले इन्होने सदन में चर्चा की थी। इसका जिक्र आज भी उनहोने किया हैं। उन्होने यह कम्पलैंट चूकि पिछले फ्राईडे को ही दी थी, इस लिए हम उस बारे मे अभी तहकीकात कर रहे हैं। मै इनका यह बताना चाहता हूं कि 92 लाख रूपया सबसीडी हमने वीडीसाईडज पर दी हैं। मुझे एक बात की खु ाी हैं। जब भी मेरे विरोधी दल के भाई मेरे पास दफतर मे आते थें और इस बारे मे मुझे बताते थे तो इनको अपने इलाके मे पहुंचने के बाद इस बात की दोबार ि ाकायत नही मिलती थीकि वीडीसाईडज के बारे मे कुछ गड़बड़ हैं।(व्यवधान व भाोर)

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, यह सिडाइज के बारे मे बता रहे हैं कि सब अच्छा हें। मै इनको यह बताना चाहता हूं कि करनाल जिले मे एक निसिंग गांव हैं, वहा पर एक आदमी सबसिसईजड, वीडीसाईडज

को पंजाब में बेचने की वहम हसे सस्पैंड किया गया हैं। यह कैसे कह रहे हैं कि इनके पास कोई कम्पलैट ही नही आई?(व्यवधान व भाोर)

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः सर, हमने यह 92 लाख की सबसिडी एक लाख 10 हजार हैक्टैयर्ज जमीन को का त के ऊपर दी है। पैडी पर 21 लाख 60 हजार रूपए की सबसीडी दी है और आप ही देखिए इनके जमाने की 56,314 हैक्टयर्ज के मुकाबले में हमने एक लाख 10 हजार हैक्टेयर्ज जमीन की का त के लिए सबसीडी दी हें जोकि दुहाई देते हैं। एक बात मंसे और याद बात रही है। हमारे ये भाई किसान की बहुत दुहाई देते हैं। एक भाई गन्ने की वबात भी कर रहा था। मुझे तो अचम्भा होता हैं जब हमारे ये भाई गन्ने की कीमत की बात करते हैं। इसक राज मे गन्ने का क्या भाव था? उस समय 4 रूपए क्विंटल था। अध्यक्ष महोदय, यह लोग किसान को 4 रूपए से ज्यादा भाव नही दिलवा सके।(व्यवधान व भाोर)

श्री कंवल सिंहः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, मै मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि हमारे इसी हाउस के एक माननीय सदस्य श्री टेक राम जी को 1976 में इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि उनके घर मै गेहू पडी़ थी। वह गेहूं कान्फीरकेट कर ली गई थी। क्या यह बात सही हैं या गलत हैं? (व्यवधान व भाोर)

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः मुझे पता नही कि इस बारे में सच्ची बात कया हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने 2 करोड़ 39 लाख रूपए की फर्टिलाईजर पर सबसिडी दी और विरोधी पक्ष का एक भी सम्मानित सदस्य यह कहने के लिए नही आया कि हमने किसी को फर्टिलाईजर पर सबसिडी नही दी। स्पीकर साहब, एक बात चौधरी सम्पत सिंह ने कही कि हिसान में चने के बीज का सैक्न्डल हुआ। अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कूल दुरस्त हैं। इस किस्म की ि ाकायत हमे मिली। अध्यक्ष महोदय, असल में ि ाकायत यह थी कि जैनुअन एग्रीकल्चरिस्ट को वास्तव में बीज नही मिला। चीफ मिनिस्टर साहब ने डिप्टी कमि नर को इंक्वायरी के लिए नियुक्त किया और इंक्वायरी हुई। उसमे चोदह औफिसर्ज दोशी पाए गए। उन सबकों सस्पैंड किया गया। जो डीलर्ज थे उनके लाईसैंस कैन्सिल कर दिए गए। अध्यक्ष महोदय, यह हो सकता हैं कि चौधरी सम्पत सिंह के सिद्वातों को सामने रखकर उनके खिलाफ ऐक ान न हुआ हो। यह दूसरी बात हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मै एग्रो–इण्डस्ट्रीज कार्पोरे ान के बारे में कुद कहना चाहता हूं। (व्यवधान व भाोर) जिस मैलाथीन का जिक्र चौधरी सम्पत सिंह ने किया उसके बारे मे मै कहना चाहता हूं कि लेबोरेटरी से जो सैम्पल फेल हुए और सरकार के नाटिस में अब यह बात आई तो उनकी सेल बन्द करवा दी गई। उसके बाद दुबारा हमने गवर्नमैंट आफ इंडिया की जो लेबोरेटरी हैं उसके पास हो गए और एक फेल हो गया। जो फेल हुआ उस के मैटीरियल को बाहर नही निकाला। वह 1861 क्विंटल के लगभग

था। उसको हमने कम्पनी को वापिस कर दिया। जो टैस्ट मे ठीक था उसको मार्किट मे बेचा।

अध्यक्ष महोदय, डा. मेगल सैन ने स्वामी आदित्यवे ा को चेयरमैन बनाया था।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, अगर ये इतनी सच्चाई बोलेगे तो फिर काम चल लिया।(व्यवधान व भाोर) आप मुख्य मंत्री जी, से डरते क्यो हैं।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, डा. साहब जानते हैं कि मै डरने वाला आदमी नही हूॅ। मै डरना तो जानता ही नही हूं। मै कह सकता हुॅं। चौधरी भजन लाल और डा. मंगल सैन दोनो ने मिलकर बनाया। (व्यवधान व भाोर) अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी की गतिविधियां जब हमारे नोटिस में आई तो हमने चीफ मिनिस्टर के नोटिस में उनको लाया और चीफ मिनिस्टर ने उनका हटा दिया।

कुछ आवाजेंः चीफ मिनिस्टर ने नही हटाया था बल्कि उनको तो जनता ने हटाया था।

श्री कवंल सिंहः स्पीकर साहब, रिकार्ड की बात हैं। ये बैचारे हमारी बहुत मदद करना चाहते थे। ये पी.यू.सी. के मैम्बर थे। एक दफा हमारे साथ इन्होने सिगनेचर भी कर दिये थे ंलेकिन चौधरी भजन लाल ने दवाब डाला और बेचारे डर गए।(व्यवधान व भाोर)

चौधरी सुरैन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस चीज पर जिस फाइंडिंग्ज पर मैने दस्तखत किये थे आज भी मेरा स्टैन्ड वही हैं। मैंने स्वामी जी को नाटिस दिया है कि आप से पैसे की रिक्वरी क्यों न की जाए और स्पीकर साहब, साहब, जो इनके चहेते थे उनको भी नोटिस दिऐ हें। अध्यक्ष महोदय, सच बात तो यह हैं कि हरियाणा सरकार के नोटिस मे जब कभी भी कोई इररैगुलेरिटी आई तो सरकार ने कायदे कानून के साथ उसको डिल किया।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, सच बोलने पर मै इनकी दाद देता हूं। ये एक बात को क्लेरिफाठ कर दे कि स्वामी आदित्यवे ा को ट्रेजरी बैंन्चिज के बार बार कहने पर और हमारे कहने पर रिमूव किया या सरकार ने स्वय रिमूव किया?

चौधरी सुरैन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी, के पास जब इस सदन की और दूसर ि ाकायते पहुंची तो मुख्य मंत्री जी, ने उन्हे रिमूव किया। अध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर साहब को एग्रो इण्डस्ट्रीज के बारे में जब तसल्ली हो गई कि काम के बारे मे ओर दूसरी चीजों में इररैबुरिटीज हो रही है तो इन्होने उन्हे हटा दिया। (व्यवधान व भाोर) अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी के टी.ए.डी.ए. के बारे मे तथा दूसरी किस्म की ि ाकायते जब सरकार के नोटिस में आई तो उनको हटा दिया गया। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, हवाई जहाज के बारे में एक बात आई। यह बडे खेद की बात हैं कि एक सम्नानित सदस्य यह बात कहे कि सोहना

के पास ऐग्रो–इण्डस्ट्रीज का जो हवाई जहाज स्प्रे के लिए रखा जाता हैं वह स्मगलिंग के लिए रखा गया हैं। बात यह है कि उस हवाई जहाज के वायरलैस और रेडियों को लाईसैस ऐक्सपायर हो गया है और जब तक इन दोना के लाईसैंस रिन्यू न कराए जाए वह एयर क्राफट टेक–औफ नही कर सकता। उनकी सर्टिफिके ान जरूरी होती है। ये दोनो दो दिन लेट हो गए और इसलिए हवाई जहाज टेक–औफ नही कर सका। इस लिए यह बात बैबनियाद हैं। ट्रैक्टर्ज की ि ाकायत हमारे पास हैं ओूर इसकी जाच पडताल कर रहे हैं।

अन्त मे मै अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारी जो मांगे है उनको पास किया जाए।

18.00 बजे

जन स्वास्थय राज्य मंत्री(चौधरी लाल सिंह): स्पीकर साहब, मै आपकी मारफत सदन को और माननीय सदस्य मास्टर ि ाव प्रसाद जी जिनहोने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया हैं बताना चाहता हूं कि मेरे बेटे पर ठेकेदारी का जो इल्जाम लगाया गया हें वह गलज हैं। जो ठेकेदारी मेरे बेटे के नाम है वह मै लिखित रूप मे इन के नाम करने को तैयार हूं। मेरा बेटा तो अभी पढ रहा हैं। कानून के अनूसार जिसका टेण्डर कम होता हैं उसको ठेका मिल

जाता हैं। मै स्पीकर साहब, इनकी तरह नही जोकि चौक मे बैठकर गरीब लोगों को यू ही लूट रहा है।(हसी व भाोर)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, अगर यह बात गलत हैं तो ये बात दे कि कहीं उनके बेटे के नाम कोई लेाएस्ट टैण्डर तो नही खुला। कही उसके नाम से कोई टैण्डर तो नही आया हैं।

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, मैने तो कहा है कि यह इल्जाम गलत हैं (भाोर व व्यवधान)

राजस्व मंत्री (चौधरी फुलचन्द): अध्यक्ष महोदय, मांगो पर चर्चा करते हुए कुछ माननीय सदस्यो ने अपने विचार यहां पर रखें और जो पैसा रैवेन्यू विभाग से सम्बन्धित हैं, उस पर भी कुछ बाते कही गई हैं। खासतौर पर प्रो. सम्पत सिंह जी ने बोलते हुए कहा कि किसानों को बसाने की बजाये उजाउ़ा जा रहा हैं। मै उनका यह बताना याहता हूं कि सरकार की नीति किसानों को उजाडना नही हैं। मै उनको यह बताना चाहता हैं कि सरकार की नीति किसानों को उजाड़ना नही हैं। सरकार की नीति किसानों को बसाना हैं। सदन को यह बातना चाहता हूं कि 1961 मे पंजाब सरकार ने यह भूमि पैकेज डील मे ली थी और यह जमीन हरिजनो को रिस्ट्रिक्टिड बोली मे दी जाती हैं। पहले सरकार की यह नीति थी कि जिन का कब्जा 1960 से होगा उनको भूमि सरकारी कीमत पर दी जाएगी किन्तु अब यह भूमि उन लोगों को भी सरकार कीमत पर दी जाती हैं जिनका कब्जा 1975 से हैं।

बाकी भूमि हरिजनो को बोली मे दी जाती हैं और इस तरह से हम 23 हजार हरिजन परिवारो को इस तरह की जमीन दे चुके है और उस पर बसा चुके हैं। अगर कोई इन प्लाटस की अलाटमैंन्टस को फर्जी साबित कर दे तो हम उसकी पूरी चाज करवाने के लिए तैयार हैं। जिस भाई का ये नाम ले रहे है उकसे नाम कोई भूमि नही है।

स्पीकर साहब, श्रीमती करतार देवी जी ने बोलते हुए कहां कि बहुत सारी भूमि जो गरीब हरिजनो को अलौट कर दी गई हैं उसके पास से जाने न पाये। हमने पहले ही यह भार्त रखी हैं कि जो हरिजन रकबा खरीदेगा वह 10 साल तक आगे नही बेच सकेगा। अगर 10 सालो के बाद कोई उसे बेच भी देता हैं तो वह कानूनी तौर पर सही है। लेकिन खिलाफ हम कानूनी कार्यवाही नही कर सकते। लेकिन अब सरकार इस पर विचार कर रही है कि अगर रकबा किसी हरिजन के नाम से कैंसिल किया गया हो तो वह किसी दूसरे और आदमी को बोली मे नही जाएगा। वह अगर किसी दूसरे को अलाट किया जाएगा तो केवल हरिजन को ही उसकी अलाटमैंट की जाएगी। इसके अलावा एक और आत मेरी बहन जी ने यह कही कि प्रधान मंत्री महोदया जी के 20 सूत्रीय प्रोग्राम के तहत जो प्लाट्स दिया जा रहे हैं उनका कब्जा लोगों को नही मिल रहा हें और कुछ प्लाट्स की अलाटमैंट ही नही हुई। मै यह बताना चाहूगां कि पिछले सर्वे के अनुसार जिन 2 करोड़ 43 लाख 500 लोगों को प्लाट्स दिये जा चुके हैं। बहन

जी को मै यह भी कहूंगा कि 20 सुत्रीय प्रोग्राम के तहत सरकार ने स्टेट लेवल पर रैवैन्यू टौन अप कमैटी बनाई हैं। हरिजनो तथा पिछडी़ जाति के लोगो को सर्वे हम करवा रहे है और जो ऐलिजीबल पाये गये, उनको पंचायत की भूमि से या दूसरी भूमि से प्लाटस की अलाटमैंटस की जाएगी।(ताल्लियां)

स्पीकर साहब, धीरपाल जी ने मुआवजे की बात कही कि कई जगहेां पर ओलावृश्टि के कारण जो लोगों की फसलो का नुकसान हुआ हैं। उसका मुआवजा लोगो का नही दिया गया हैं। हम यह कोि ा ा कर रहे हें और की भी है कि जिन लोगो का कहीं पर भी नुकसान हुआ हैं उस नुकसान के अनुसार सरकार की तरफ से जो भाडयूल तय हुए हैं उनके मुताबिक उनको मुआवजा दिया जाए। अगर कही पर इस तरह को मुआवता बकाया रह गया हो तो वह भी पैसे की कमी के कारण। तो वह मुआवजा इस साल पूरा बंटवाया जाएगा। स्पीकर साहब, कुदरत की जो मार पड़ती हैं उसका इलाज किसी के पास नही है। जब मौत मा कुल्हाड़ा पड़ता हैं या बिमारी पड़ती हैं तो हम कोि ा ा करते हैं कि डाक्टर से उससे बचने के लिए दवाई ली जाए लेकिन कुदरत की मार की कोई अपील नही हैं लैकिन फिर भी सरकार ने यह सोचा कि जिन किसानों की तरफ से की जाए ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके और वे अपने आप को सरकार के हाथो मे सेफ समझ सके।(ताल्लियां)

श्री अध्यक्षः मुलाना साहब, अब आप वाइंड अप किजिए।

चौधरी फुलचन्दः ठीक है सर, मै वाइंउ अप करने जा रहा हूं। स्पीकर साहब, मुआवजे के बारे में यह भी कहा गया हें कि 400 रूपये पर एकड़ के हिसाब से जो मुआवजा सकराकर की तरफ से दिया जा रहा हें वह बहुत कम हैं। मै उनका बताना चाहता हूं कि इनके टाइम मे 2 करोड़ रूपया मुआवजे का बांटा गया था लेकिन हमारे समय में 14 करोड़ रूपया बांटा गया हैं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हें कि इनके वक्त मे किसानो की ज्यादा मदद की गई यह इस सरकार ने गरीब किसानो का पुरा ध्यान रखा हैं। स्पीकर साहब, यहां यह बात आई कि जो प्लाटस बांटे गये हैं उनका अभी तक कब्जा लोगों का नही मिला । एक तरफ तो ये लेाग किसानों के हतें ाी बनते हैं और दूसरी तरफ कुझावला कांड भी करवाते हैं।(ाोर एव व्यवधान) धीरपाल जी ने यह भी कहा है कि सूखें के समय पर लोगों को किसी प्रकार की राहत नही दी गयी। जहां तक स्टेट मे सूखे का सम्बन्ध हैं, हमने उस बक्त केंन्द्र सरकार को इस बारे में लिखा और केन्द्र सरकार से जो सहायता मिली वह विभिन्न वर्गो मे बांट कर हमने लोगों का राहत दी थी। हमने किसानों का मालिया भी माफ किया है और गरीब किसानो की हर तरफ से मदद की हैं। इस दौरान कितने ही संकट आए, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी सूखा तो कभी औले पड़े लेकिन फिर भी हमने सभी मुसीबतों का डटकर मुकाबला किया और हमारी सरकार ने यह तय किया कि हर आफत मे हम किसानों की मदद करेगें और की भी। फण्डज के अनुसार पूरी पूरी मदद देने का प्रवाधान हमारी सरकार ने किया है। धीरपाल जी ने

एक बात यह कही कि करतार सिंह और धर्म सिहं की सारी फसले आग लगने से तबाह हेा गयी थी लेकिन उनको मुआवजा देने के लिए सराकर ने कुछ नियम बनाए हैं। डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिसट्रे ान के पास इसके लिए फण्डज होते है। सरकार के नियमों के मुतबिक मुआवजा दिया जाता हैं। इसलिए स्पीकर साहब, इन्होने जो जो बाते हमारे नोटिस में लायी है उनकी इन्कवायरी करवा कर नियमों के अनुसार कार्य किया जाएगां।

स्पीकर साहब, मै सम्पत सिह जी को एक और बात का भी जवाब देना चाहता हूं। उन्होने कहा कि हरिजनो को जमीन नही दी जाती। मै उन्को बताना चाहता हूं। कि जो सरप्लस इवैक्यूलैंड है वह हरिजनो मे रिस्ट्रिकटिड औक ान से बाटी जाती हैं औरप अलौट भी उन्ही को की जाती हैं। जिनका कब्जा बनता हैं।सिवाए उस भूमि के जो एक एकड़ से कम होया जो रकबा कम हो गया हेा या कोई भाहरी जायदाद हो। इन भाब्दा के साथ मै निवेदन करूंगा कि ये मांगे बिल्कूल जायज हैं और इनको पास कर दिया जाए।

भाहरी तथा ग्राम योजना मंत्री(सरदार हरपाल सिंह): स्पीकर साहब, अभी डिमांडज पर चर्चा हो रही थी। उसमे प ा पालन विभाग पर भी थोडी चर्चा आई मे आपके द्वारा सदनक को बताना चाहूंगा कि सरकार प ा पालन की तरफ पूंरा ध्यान दे रही हैं। हम इस बात को अच्छी तरह से समझते है कि प ा पालन के द्वारा ही हम अपने प्रदे ा के किसानो की हालत अच्छी कर सकते

हैं। मै कह सकता हूं कि हमारे प्रदे ा के प ाु सारे दे ा मे सब से अच्छे माने गये है। पिछले दिनो इलाहाबाद मे आल इडिया कैटल भाो हुआ था। उसमे सारे दे ा के सभी प्रदे ाो के जानवर गये और भाो की इनागुरे ान प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने की। सदन को यह जान कर खु ाी होगी कि जो प्रथम एनीमल माना गया वह हरियाणा के लाईव स्टाक फार्म हिसार को बफला बुल थां उसको सबसे जयादा ईनाम मिला। सदन को यह भी सून कर खु ाी होगी कि उस भाो मे हरियाणा की 82 एन्टरीज थी और हमे 83 ईनाम मिले। जो प्रदे ा एक नम्बर पर आया वह भी हरियाणा प्रदे ा ही हैं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, जब एन्टरीज 82 थी तो इनाम 83 कैसे मिले?

सरदार हरपाल सिंहः मै एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे एक एनीमल दूध में भी अच्छा हो और नस्ल मे भी अच्छा हेा तों उसके लिए दो ईनाम हैं। ये ईनाम एक प ाु के दौहरे भी हो सकते हैं और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। (विघ्न)

श्री निहाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये सारे जानवर हिसार मे ही क्यो रहते हैं और कही क्यो नही रहतें? (हंसी)

सरदार हरपाल सिंहः भैस रोहतक की अच्छी हैं। हिसार के तो बुल म ाहूर है। स्पीकर साहब, अभी एक आनरेबल मैम्बर ने

यह जिक्र किया कि किसी ऐरिया में बैटर्नरी हस्पताल या डिसपैसरीज कम हैं। मै सदन को बाताना चाहता हूं कि जो हम प ाुओ के लिए हरियाणा मे वेटरनरी एड दे रहे हैं वह 4450 प ाुओं मे पीछे एक इस्टीच्यू ान यानी एक हस्पताल या एक डिसपैंसरी खोलते हैं। इतनी वैटरनरी एड का सारे दे ा मे कोई भी स्टेट इंतजाम नही कर सकी। इसमें भी हम सब से आगें है इसके बाद जो अवेलेबिलिटी आफ मिल्क हैं वह दे ा मे एवरेज एक व्यक्ति को 128 ग्राम मिलती हैं लेकिन हरियाणा मे 484 ग्राम दूध मिलता हैं । इससे भी आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा मे मिल्क प्रोडैक ान मे भी दूसरी स्टेटो से आगें है। लाइव स्टाक फार्म के बारे मे पीछे एक ि ाकायत आई थी कि यहां पर दूध की डिस्ट्रीब्यू ान ठीक नही हैं। हमने वहा के इन्चार्ज को बदल कर दूसरे को लगाया। उसके बाद दोबारा ि ाकायत आई कि अभी भी मिल्क डिस्ट्रीब्यू ान ठीक नही हो रही है। हमने बाकायदा केस रजिस्टर करवाया और इन्कवायरी विजीलैस के सुपुर्द कर दी। उसमे जो भी दोशी माया जाएगा चाहे कोई भी हो किसी के साथ कोई भी लिहाज नही की जाएगी। सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि मिल्क की डिस्ट्रीब्यू ान उस फार्म कै एम्पलाईज की बजाए अअ हमने डेरी डिवैल्पमैंट कार्पोरे ान के हवाले करने का फैसला कर लिया ताकि मिल्क डिस्ट्रीब्यू ान में इम्प्रूवमैंट हो ओर लेागो को ठीक ढग से दूध मिल सके। इन भाब्दो के साथ रिक्वैस्ट करूगां कि यह मांग पास कर दी जाए।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग की डिमांड न. 15 के जरिये से हाऊस पसे 62,65,40,005 रूपये की मंजूरी मागी जा रही है। मै सदन के सदस्यो का बहुत आभारी हूं कि सिंचाई विभाग के बारे मे कोई नुक्ताचीनी उन्होने नही की। (विघ्न) मै इससे यह मानता हैं कि सिंचाई विभाग से सब पूरी तरह से सन्तुश्ट हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डरप हैं। स्पीकर साहब, डिमाण्डज पर टाईम की कमी की वजह से ज्यादा चर्चा नही हो पाई। बजट पर बोलते हुए मैने स्पैसिफिकली कहा था जिसका जवाब फाइनैंस मिनिस्टर ने नही दिया। मै चाहूगां कि उस बात का जवाब अब मंत्री जी दे। बजट मे केवल 82 करोड़ रूपया मेजरप औरप मीडियम स्कीमो के लिए एलोकेट किया है।। अकेली एस.बाई.एल. अगर स्पैसिफाइड टाईम मे कम्पलीट करनी हैं तो उस पर 100 करोड़ रूपये से फालतू लगेगा। एस.वाई.एल. के लिऐ ये 20 करोड़ रूपया पहले दे चुके हैं। इसके लिए हमे न बजट स्पीच मै और न बजट की किताबो मे कुछ मिला। उसके लिये क्या प्रबनघ हैं यह मंत्री जी कृपया बताए?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: मैने इस बात का भी जवाब देना था। अध्यक्ष महोदय, हमारा सारा प्रान्त कृशि प्रधान प्रान्त हैं। हमारे सिंचाई विभाग का काम सारे प्रदे ा में सिंचाई उपलब्ध करवाना हैं। हमारे प्रदे ा मे सिचाई के कुदरती साधन नही हैं, बारि ा का भी भारी अभाव हैं। हमारी जो पाना की

डिमाण्ड है वह 33.5 एम.ए.एफ. हैं उसके मुकाबले मे हमारे जो रिसोर्सिज हैं, चाहे वे जमना से है, भाखडा़ से हैं या अंडर ग्राउन्ड वाटर से है वे 14.30 एम.ए.एफ. हैं। यह जो गैप हैं इसका ब्रिज करने के लिए सिंचाई विभाग अपने रिसोर्सिज को बहुत किफायते से यूटिलाईज करने और साधनो को बढाने का यत्न कर रहा है। 1983–84 के बजट मे आपने देखा होगा कि 70 लाख रूपया हमने मल्टी परपज प्राजैक्ट के लिए खर्च करना हैं। जितनी भी दरमियानी और बड़ी योजनाए है उनके लिए सरकार ने 81 करोड़ 90 लाख रूपये का प्रावधान किया है। मै उनको बताना चाहता हूं कि एस.वाई.एल. नहर की खुदाई के लिए इस बजट मे 30 करोड़ रूपए प्रावाधान किया गया हैं। यह 30 करोड़ रूपया जो पहले 50 करोड़ रूपया रखे हूंए है उससे अलग हैं। कोई माननीय सदस्य यह न समझे ककि यह 30 करोड रूपया उस 50 करोड़ रूपये मे से 20 करोड़ रूपय खर्च होने को बाद बचता हैं। यह 30 करोड़ रूपय का अलग से प्रावधान किया गया हैं। स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार एस.वाई.एल नहर की खुदाई के लिए बहुत ही प्रयत्न ील हैं। भारत सरकार भी हरियाणा सरकार को मैच्रिग ग्रांट के तौर पर एड दे रही है। स्पीकर साहब, हमे एस.वाई.एल नहर के पानी का हिस्सा 1976 मे मिला था लेकिन 1976 के फैसले को बहुत ढीला रखा गया और यह फैसला 1981 तक लटकता रहा। फिर 1982 के भुरू मे वह फैसला हुआ। 1982 के बाद एक साल के अन्दर 100–200 करोड़ के प्रोजैक्ट को कोई भी सरकार और किसी भी पार्टी की सरकार पूरा नही कर सकती।

स्पीकर साहब, हमे पूरी उम्मीद हैं कि अब एस.वाई.एल. नहर का खुदाइ का काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा और इस काम के लिए हमे जितना पैसा चाहिए उसमे कोई कमी नही आने देगें। इस नहर की खुदाई के लिए हम वर्ल्ड बैंक से एडवांस पैसा ले लेगें। पैसे की कमी की वजह से एस.वाई.एल. नहर की खुदाई का काम ढीला होने का सवाल ही पैदा नही होता। हमने पिछले साल के बजट में भी इस काम के लिए पैसे का प्रावधान न होने के बावजूद भी अपने साधनों से जितना पैसा पंजाब सरकार ने मांगा था वह पैसा उसको दे दिया था। स्पीकर साहब, इसके अलावा काफी बडी–बड़ी स्कीम्ज हैं। जौ लिफ्ट इरीगें ान की स्कीम हैं, उसको मुकम्मल करने के लिए इस बजट मे 9 करोड़ रूपए का प्रावाधान किया गया हैं। कुछ स्कीम ऐसी हैं जो अडंर एग्जामिने ान हैं। उनकों भी कम्पलीट करना हैं। इसी प्रकार से जो नहरो और रजवाहेा को पक्का करने की स्कीम हैं उसके लिए हमने इस बजट में 21 करोड़ रूपए का प्रावधान किया हैं। हथनी कुण्ड बैराज के लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया हैं। इसी प्रकार से फ्लउ कंट्रोल के लिए साढे 17 करोड़ रूपए का प्राधान किया गया हैं। स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदे ा 1966 मे बना था। आप 1967 से 1979 तक के बजट निकाल कर देख लिजिए। उस दौरान केवल एक या दो रजवाहों की ऐक ाटैन ान हुई होगी लेकिन 1979–80 से लेकर 1982–83 तक ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट ने लगभग 90 राजवाहों की ऐक ाटेन ान की स्कीम इन हैंड ली हें। उन 90 राजबाहों मैं से लगभग 20 रजबाहों की ऐक ाटें ान कम्पलीट हो चुकी हैं

और 27 स्कीमों पर काम चल रहा हैं। बाकी 43 राजबाहों की स्कीम्ज इस साल और अगले साल के अन्त तक कम्पलीट हो जाने की उम्मीद हैं। इन सभी रजबाहों की स्कीमें कम्पलीट हो जाने के बाद सिंचाई सुविधाओ में काफी बढोत्तरी होगी।

बैठक का समय बढाना

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सैंस हो तों हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढा दिया जाए।

आवाजेंः ठीक है जी। हाउस का टाईम 10 मिनट के लिए बढा दिया जाए।

श्री अध्यक्षः बैठक का समय 10 मिनट बढाया जाता हैं।

वर्श 1983–84 के बजट पर अनुदानो की मांगों पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री हरि चन्द हुड्डाः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरे हल्के मे 15 ड्रेन्ज हैं उन में से 13 ड्रेंन्ज की खुदाई का काम मैने खुद ने करवाया था। मैने अपने हल्के की दो ड्रेन्ज, नादल और किलाई, के बारे में सुरजेवाला साहब को लिख कर दिया हैं कि इन ड्रेन्ज को खुदवाया जाए। मैने अपने हल्के में 15 ड्रेन्ज में से 13 ड्रेन्ज की खुदवाई का काम करवा दिया था लेकिन दो ड्रैन्ज बाकी रहती हैं। इसलिए मैं इन से दरख्वास्त

करूंगा कि इन दोनों ड्रेन्ज को खुदवाने के लिए सरकार की तरफ से तवज्जो दी जाए।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने जिन ड्रेन्ज का नाम लिया है उनमें से एक ड्रेन का केसा हाई कोर्ट मे पेडिंग हैं और उस ड्रेन का जमींदारों ने हाई कोर्ट से स्टे ले रखा हें। दूसरी ड्रेन का केस सिविल कोर्ट में पेंडिंग हैं। इन का जब भी फैसला हो जाएगा, ड्रेन को बनाऐगे। स्पीकर साहब, नए 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत हरियाणा सरकार ने छठी पंच वर्शीय योजना में सिचाई की सुविधाओं को बढाने के लिए काफी प्रोत्साहन दिया हैं। स्पीकर साहब, प्लानिंग कमी ान ने हरियाणा सरकार से इस बात की सहमति प्रकट की हैं कि 15 लाख हैक्टैयर भूमि को बढा करके 32 लाख हैक्टेयर भूमि में सिचांई सुविधाओं को बढा दिया जाए। इसी प्रकार से 1983–84 के साल में जिनती भी सिंचाई सुविधाऐ बढेगी उनसे एक लाख एकड़ नई भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। इसके अलावा मै यह भी बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा की नहरों ओर रजबाहों को पक्का करनके के लिए पहली फेज मे 77 करोड़ रूपये दिए थे।

चौधरी औम प्रका ाः स्पीकर साहब, मंत्री जी नहरो और रजबाहों को पक्का करने के बारे मे कह रहे हैं। मै इन को एक सुझाव देना चाहूंगा कि नहरो की लाईनिब करते समय जो मैटीरियल यूज किया जाता हैं वह सब–स्टैंडर्ड मैटेरियल यूज

किया जाता हैं। जे.एल.एन. नहर की जो लाईनिंग की गई हैं उसमें सब–स्टैंडर्ड मैटीरियल यूज किया गया हैं जिस के कारण उसा नहर में बहुत ज्यादा सीपेज हो रही हैं। इसलिए मै मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस समय आप नहरों और रजबाहों की लाईनिंग का काम करवाए उस समय जे.एल.एन. नहर कि मिसाल अपने सामने रख करके लाईनिंग का काम करवाएं ताकि सीपेज न हों।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, मै हाउस को बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक ने पहली फेज में जो 77 करोड़ रूपया नहरो और रजबाहों को पक्का करने के लिए दिया था उससे 25 हजार वर्ग फुट नहरों और रजबाहों को पक्का किया गया हैं। हाउस को इस बात की खु ाी होगी कि हमारा वर्ल्ड बैंक के साथ 90 करोड़ रूपए काक सैकिण्ड फेज का ऐग्रीमैंट कम्पलीट हो चुका हैं। यह पैसा हरियाणा मैं अगले चार सालों मै नहरो और रजबाहों को पक्का करने पर खर्च होगा। इन भाब्दों के साथ मैं हाउस से दरख्वास्त करूंगा कि इरिगें ान विभाग की जो डिमांड हैं उस को मंजूरी दी जाए।

वर्श 1983–84 के बजट पर अनुदानो की मांगों पर मतदान

Mr. Speaker: Now I will put the Various Demands to the vote fo the house.

आवाजें: इन्हें इक्टठा ही पुट कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Quetion is –

That a sum not exceeding RS. 5,48,36,520 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of the charge under Demand No.4-Revenue.

Mr. Speaker: Quetion is –

That a sum not exceeding Rs. 40,33,88,750 for revenue expenditure and Rs. 3,24,56,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of the charges under Demand No. 17-Agriculture.

That a sum not exceeding Rs. 9,48,40,000 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of the charges under Demand No. 18-Agriculture Husbandry.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a sum not exceeding Rs. 13,21,33,100 for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of the charges under Demand No. 21-Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 4,73,03,000 for revenue expenditure and Rs. 12,09,74,300 for capital

expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 1983-84 in respect of the charges under Demand No. 22-Coorperation.

The motion was carried.

श्री अध्यक्षः अब सदन कल मंगलवार दिनांक 22.03.1983 प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थागित किया जाता हैं।

18 : 28 बजे

(तत्प चात सदन मंगलवाल दिनांक 22.03.1983 को प्रातः 9.30 बजे तक लिए स्थगित हुआ)

ANNEXURE

Drinking Water Tanks

***278 Sh. Nar Singh:** Will the Minister of State for Public Health be pleased to state whether any water tanks for the supply of dringking water have been constructed in the State during the period from 1978-79 to date; if so, constituency-wise number thereof?

Chief Minister(Chaudhri Bhajan Lal): A statement showing the number of water works constructed in the State during the period form 1978-79 to July, 1983 is placed on the Table of the house.

STATEMENT

Sr. No.	District	Name of the Constituency	No. of Water Works constructed during 1978-79 to 7/83.
1	2	3	4
1.	Ambala	Kalka	33
		Naraingarh	29
		Sadhaura	3
		Chachhrauli	5

		Mullana	6
		Ambala City	1
		Naggal	7
		Total	84
2.	Bhiwani	Badara	7
		Dadri	4
		Mundhal	5
		Bhiwani	1
		Loharu	5
		Bawani Khera	9
		Total	31
3	Gurgaon/Faridabad	Ferozepur Zhirka	4
		Taoru	7
		Hathin	5
		Palwal	3
		Ballabhgarh	4
		Mewla Mahrajpur	5

		Sohna	10
		Pataudi	9
		Gurgaon	7
		Hssanpur	2
		Faridabad	1
		Total	61
4.	Hissar	Bhattu Kalan	12
		Barwala	4
		Narnaud	7
		Hansi	6
		Hissar	2
		Ghirai	7
		Adampur	7
		Ratia	4
		Dabra Kalan (Part area in Hissar)	4
		Tohana	6
		Fatehabad	8

		Total	67
5.	Jind	Jind	2
		Narwana	7
		Uchana	5
		Jullana	5
		Rajound	2
		Safidon	9
		Kalayat	3
		Total	33
6.	Karnal	Nilokheri	2
		Jundla	3
		Gharaunda	3
		Asandh	2
		Samalkha	5
		Naultha	4
		Total	19
7.	Kurukshetra	Shahbad	2
		Thanesar	9
		Pehowa	3

		Pundri	4
		Pai	1
		Gulha	1
		Kaithal	1
		Total	21
8.	Mohindergarh	Rewari	5
		Narnaul	13
		Ateli	9
		Bawal	8
		Jattusana	3
		Mohindergarh	11
		Total	49
9.	Rohtak	Hassangarh	5
		Kiloi	3
		Meham	4
		Kalanaur	3
		Beri	5
		Salhawas	2
		Jhajjar	7

		Badli	9
		Bahadurgarh	11
		Total	49
10.	Sirsa	Ellanabad	4
		Rori	16
		Darba Kalan	6
		Dabwali	6
		Total	32
11.	Sonipat	Kaliana	2
		Rohat	5
		Baroda	2
		Rai	1
		Gohana	1
		Total	11
		Grand Total	457